● वर्ष : 17 ● अंक : 225 ● मूल्य : 02 रुपया मात्र ● पृष्ठ : 08

LKS

दैनिक लोकतंत्र की शान

WWW.LKSTV.IN

लोकतंत्र का स्तंभ

दिल्ली से प्रकाशित शुक्रवार 05 जून 2026

मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति रोड्रिगेज के बीच व्यापार पर अहम बातचीत

एजेंसी। नई दिल्ली

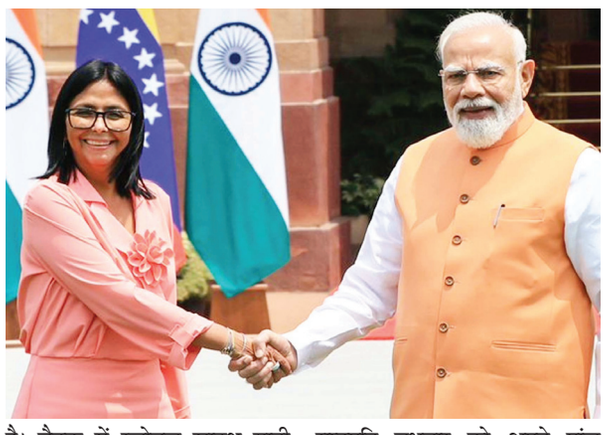

वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज, पांच दिवसीय दौरे पर भारत पहुंची हैं, भारत पहुंचकर उन्होंने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विस्तृत और व्यापक बातचीत की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के पूरे दायरे की समीक्षा की और विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार किया। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बैठक की जानकारी देकर बताया कि विशेष रूप से ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवाएं और ऑटोमोबाइल उद्योग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग के नए मौकों पर गहन विचार-विमर्श हुआ। दोनों देशों ने इस बात पर जोर दिया कि आर्थिक और तकनीकी साझेदारी को और मजबूत करे, ताकि दोनों देशों को दीर्घकालिक लाभ मिल सकें। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार, बातचीत के दौरान वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान हुआ। दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति जाहिर की कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में दोनों देशों की भूमिका और आपसी सहयोग को और सुदृढ़ करना जरुरी है। बैठक में ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। दोनों नेताओं ने माना कि आर्थिक स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और विकास से जुड़े साझा लक्ष्यों पर विकासशील देशों को एकजुट होकर काम करना चाहिए। इसके पहले, रोड्रिगेज ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद जयशंकर ने लिखा था कि वे नई दिल्ली में डेल्सी रोड्रिगेज से मिलकर प्रसन्न हैं और भारत-वेनेजुएला रिश्तों को मजबूत करने में उनके लंबे समय से चले आ रहे योगदान की सराहना करते हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति बुधवार को अपने पांच दिवसीय भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंची थीं। इस दौरे का मुख्य मकसद दोनों देशों के संबंधों को और गहरा करना और साझेदारी में नई गति लाना है। भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा और निवेश क्षेत्र में एक लंबी और मजबूत साझेदारी रही है। भारतीय सरकारी कंपनियों ने वेनेजुएला के ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश किया है और भविष्य में भी सहयोग बढ़ाने की व्यापक संभावनाओं पर काम चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वेनेजुएला के प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता के दौरान दोनों देशों ने खनन क्षेत्र में संभावित सहयोग और संसाधनों के आकलन को लेकर भी चर्चा की। विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्व) रुद्रेंद्र टंडन ने गुरुवार को पत्रकार वार्ता में कहा कि वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देशों में से एक है, जबकि भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के कारण तेल का बड़ा उपभोक्ता है।

विदेशमंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति से की मुलाकात

नई दिल्ली। विदेशमंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने आज यहां वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने एक्स पर लिखा, "आज यहां (दिल्ली) में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज से मिलकर मुझे खुशी हुई। भारत-वेनेजुएला संबंधों के प्रति उनके लंबे समय से चले आ रहे समर्पण की मैं बहुत कद्र करता हूं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात हमारे सहयोग को और मजबूत करेगी। यात्रा के दौरान कार्यवाहक राष्ट्रपति रोड्रिगेज प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत-वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में आगे सहयोग के रास्ते तलाशे जाएंगे।

ज्वलंत मुद्दा **संपादकीय**

हाका लगाकर पश्चिम बंगाल में टीएमसी का शिकार

जब किसी का शिकार करना होता है तो शिकारी शिकार को हाका लगाकर ऐसी जगह ले जाते हैं जहां पहले से ही कोई बड़ा गड्ढा खुदा होता है। घबराहट में शिकार भागता हुआ जाता है और उसी गड्ढे में गिर जाता है। उसके बाद शिकार को पिंजरे में बंद करके रख लिया जाता है। कुछ इसी तरह का शिकार पश्चिम बंगाल में भाजपा ने ममता बनर्जी की टीएमसी का किया है। ममता बनर्जी की 28 साल पुरानी पार्टी का शिकार परंपरागत तरीके से कर लिया है। पार्टी के 58 विधायकों को ममता बनर्जी से दूर करने का जो जाल फैलाया गया था, उसी जाल में ममता फंस चुकी हैं। इस जाल को तोड़कर बाहर निकलना शायद ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए अब संभव नहीं रहा।

विधानसभा के चुनाव में जैसे-तैसे 80 सीटों पर टीएमसी के विधायक जीते थे। टीएमसी की ओर से विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र बोस को पत्र भेजा गया था, जिसमें शोभनदेव चट्टोपाध्याय को टीएमसी के विधायक दल का नेता और सचेतक इत्यादि की जानकारी दी गई थी। नामों वाला संबंधित पत्र विधानसभा अध्यक्ष को भेजकर नियुक्ति का अनुरोध किया गया था। विधानसभा अध्यक्ष ने उस पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की। इसी बीच ऋतुव्रत बनर्जी ने जो टीएमसी के विधायक हैं और उनके एक साथी विधायक ने अपने हस्ताक्षर जाली बताकर विधानसभा अध्यक्ष के यहां आपत्ति जताई। मामला पुलिस और सीआईडी तक पहुंचा। टीएमसी के पत्र पर नियुक्ति रोक दी गई।

उसके बाद ऋतुव्रत बनर्जी को भाजपा और विधानसभा अध्यक्ष का संरक्षण मिला। एक सूची 58 विधायकों की ऋतुव्रत बनर्जी ने विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी। विधानसभा अध्यक्ष ने ताबड़तोड़ ऋतुव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष घोषित कर दिया। उन्होंने सचेतक के रूप में जो नाम दिया था उसे स्वीकार कर लिया। जिसके कारण विधानसभा अध्यक्ष द्वारा निश्चित रूप से संसदीय परंपराओं में जिस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए थी वह नहीं की गई। जिस तरह से सांसद अभिषेक बैनर्जी और सांसद कल्याण बनर्जी की सड़क पर पिटाई की गई थी, उसके वीडियो वायरल किए गए, विधायकों को बैठक में नहीं पहुंचने दिया गया।

विधायकों के बीच यह संदेश पहुंचाया गया वह ममता बनर्जी का साथ छोड़ दें और ऋतुव्रत बनर्जी के साथ आ जाएं। तभी वह सुरक्षित रहेंगे अन्यथा उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।अभिषेक बनर्जी के घर ईड़ी ने दस्तक दे दी है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल की सरकार टीएमसी के विधायकों और नेताओं के ऊपर कार्यवाही कर रही है, 2 लाख से अधिक केंद्र सरकार के अर्धसैनिक बल के जवान तैनात हैं।

सैयद जकी हैदर | सम्पदक/प्रकाशक
MOBE NO.**9911371802**
EMAIL. SYEDZAKIHAIDER**786**@GMAIL.COM

संक्षिप्त समाचार

सीबीएसई ने त्रि-भाषा फार्मूला मनमाने ढंग से लागू कियाः कांग्रेस

नई दिल्ली। कांग्रेस ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) पर ऑन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) प्रणाली और कक्षा 9 एवं 10 में त्रि-भाषा फार्मूले को जल्दबाजी में और मनमाने तरीके से लागू करने का आरोप लगाया है। पार्टी ने कहा कि इससे शैक्षणिक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त हो जाएगी। कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गुरुवार को कहा कि दिसंबर 2025 में सीबीएसई की गवर्निंग बॉडी ने पाठ्यक्रम समिति की सिफारिश को स्पष्ट रूप से मंजूरी दी थी कि एनसीईआरटी द्वारा ग्रेडेड पाठ्यपुस्तकें जारी होने तक मौजूदा भाषा व्यवस्था जारी रहे। इस निर्णय पर तत्कालीन चेयरमैन और सचिव ने हस्ताक्षर भी किए थे। इसके बावजूद मई 2026 में सीबीएसई ने परिपत्र जारी कर 01 जुलाई से कक्षा 9 एवं 10 में तीसरी भाषा जोड़ने का निर्देश दिया और स्कूलों से कहा कि वे कक्षा 6 की एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों से 9वीं के छात्रों को पढ़ाएं। उन्होंने सवाल किया कि पिछले छह महीनों में आखिर क्या बदला, जबकि एनसीईआरटी ने कक्षा 9 एवं 10 के लिए कोई नई भाषा पाठ्यपुस्तक जारी नहीं की है। इस कदम का कोई शैक्षणिक औचित्य नहीं है और इससे लाखों छात्रों का शैक्षणिक भविष्य प्रभावित हो रहा है। शिक्षा मंत्रालय और उसकी स्वायत्त संस्थाएं शिक्षा विशेषज्ञों की सलाह के बजाय राजनीतिक एजेंडे पर काम कर रही हैं। रमेश ने कहा कि जब जवाबदेही की बात आती है तो सीबीएसई के अधिकारियों को पद से हटाया जाता है।

अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति ट्रंप के ईरान के साथ युद्ध अधिकार पर रोक लगाई

वाशिंगटन। अमेरिकी कांग्रेस के निचले सदन 'प्रतिनिधि सभा' (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव) ने बुधवार को 215-208 वोटों से एक समवर्ती प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के साथ युद्ध करने के अधिकारों पर रोक लगा दी। महत्वपूर्ण यह है कि डेमोक्रेट्स के इस प्रस्ताव का चार रिपब्लिकन ओहियो के प्रतिनिधि वॉरेन डेविडसन, पेंसिल्वेनिया के ब्रायन फिट्ज़पैट्रिक, मिशिगन के टॉम बैरेट और केंटकी के थॉमस मैसी ने समर्थन किया। एबीसी न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रस्ताव में कहा गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान या उसकी सेना या सरकार के किसी भी हिस्से के खिलाफ शत्रुतापूर्ण कार्रवाई में अमेरिकी सशस्त्र बलों का इस्तेमाल तब तक बंद कर देना चाहिए, जब तक कि युद्ध की घोषणा या बल प्रयोग का अधिकार देने वाला कानून पारित न हो जाए। प्रतिनिधि सभा से पारित यह प्रस्ताव अब सीनेट में जाएगा। सीनेट भले ही इसका समर्थन कर दे, लेकिन एक समवर्ती प्रस्ताव में कानून जितना वजन नहीं होता और इसे राष्ट्रपति के सामने पेश नहीं किया जाता, न ही इस पर राष्ट्रपति के वीटो का अधिकार लागू होता है। मतदान के बाद हाउस की विदेश मामलों की समिति के वरिष्ठ डेमोक्रेट ग्रेगरी मीक्स ने पत्रकारों से कहा, "कांग्रेस ने आज संविधान का पालन किया है। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों ने कहा कि अब बहुत हो चुका।

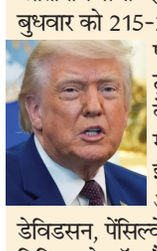

शिक्षक भर्ती मामले में 15 को अभिषेक से पूछताछ करेगी ईडी

ईडी ने उनके निवास पर जाकर थमाया समन

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कड़ा रुख अपनाते हुए तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी को समन जारी किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारी कोलकाता के कालीघाट स्थित उनके आवास पर नोटिस लेकर पहुंचे, जिसके तहत उन्हें आगामी 15 जून को पूछताछ के लिए जांच अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होने का कड़ा निर्देश दिया गया है। सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय एजेंसी शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार मामले से जुड़े कथित वित्तीय लेन-देन की गहराई से जांच कर रही है। इस जांच के दौरान लीप्स एंड बाउंड्स नामक संस्था से संबंधित कुछ संदिग्ध वित्तीय जानकारियां और दस्तावेज सामने आए हैं, जिनके आधार पर एजेंसी अभिषेक बनर्जी से विस्तृत पूछताछ करना चाहती है। बताया जा रहा है कि ईडी की एक विशेष टीम सबसे पहले उनके शांतिनिकेतन स्थित ठिकाने पर पहुंची थी, लेकिन वहां अभिषेक बनर्जी के मौजूद न होने के कारण अधिकारी कालीघाट रोड स्थित उनके मुख्य आवास पर पहुंचे। उस समय भी अभिषेक बनर्जी घर पर उपस्थित नहीं थे और बताया गया कि वे पार्टी प्रमुख व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा बुलाई गई एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने गए हुए थे।

पीएम पांच जून को गुजरात और दमन के दौरे पर, 21,700 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की देंगे सौगात

एजेंसी। नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल (5 जून) गुजरात और दमन का दौरा करेंगे। इस दौरान वो गुजरात के सूरत में लगभग 18,800 करोड़ रुपये और दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री लक्षद्वीप के लिए 885 करोड़ रुपये की बंदरगाह परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने आज बताया कि वो कल दोपहर करीब 2:30 बजे सूरत जिले के हजीरा पहुंचकर वहां चल रही औद्योगिक गतिविधियों और आधारभूत ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसके बाद वह सड़क, ऊर्जा और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी 18,800 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे तथा जनसभा को संबोधित करेंगे। सूरत में प्रधानमंत्री वडोदरा-मुंबई आठ लेन नियंत्रित प्रवेश (एक्सेस कंट्रोल्ड) एक्सप्रेसवे के पैकेज-6 और पैकेज-7 राष्ट्र को समर्पित करेंगे। साथ ही वह राष्ट्रीय राजमार्ग-56 के महत्वपूर्ण हिस्सों को चार लेन बनाने की परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इससे आदिवासी क्षेत्रों की संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंच आसान बनेगी। इस दौरान प्रधानमंत्री सूरत में 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। अस्पताल में विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं के साथ केंद्रीय प्रयोगशाला तथा 24 घंटे आपात और ट्रॉमा देखभाल की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा वह अंतरराज्यीय विद्युत पारेषण प्रणाली के तहत गुजरात की ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार परियोजना का उद्घाटन करेंगे। वलसाड में विद्युत वितरण प्रणाली उन्नयन, दहेज पेट्रोलियम-रसायन एवं पेट्रो-रसायन निवेश क्षेत्र तथा सरीगाम औद्योगिक विकास निगम में अपशिष्ट निस्तारण एवं शोधन अवसंरचना और जंबूसर बल्क ड्रग पार्क की उपयोगिता परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वह दमन जाकर शाम करीब 6:15 बजे हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और नमो अस्पताल राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके बाद वह लगभग 2,970 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। दमन में लगभग 1,340 करोड़ रुपये की परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की जाएंगी, जिनमें नामो हवाई अड्डे का नया टर्मिनल भवन और नामो अस्पताल प्रमुख हैं।

सुपारी तस्करी नेटवर्क पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, मिजोरम में नौ ठिकानों पर छापे

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मिजोरम-म्यांमार सीमा पर म्यांमार की सूखी सुपारी (अरेका नट) की तस्करी से जुड़े संगठित नेटवर्क के खिलाफ गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने मिजोरम के सीमावर्ती शहर चंफाई में नौ स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। कार्रवाई का केंद्र तस्करी नेटवर्क से जुड़े प्रमुख स्थानीय सहयोगियों के आवास और व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं। ईडी ने बताया कि जांच में सामने आया कि आरोपी म्यांमार से तियाउ नदी के रास्ते बड़ी मात्रा में अवैध सुपारी भारत लाते थे। इसके बाद माल को स्थानीय गोदामों में रखा जाता था और फर्जी ई-वे बिल तथा जाली दस्तावेजों के जरिए उसे स्थानीय स्तर पर खरीदा गया वैध माल बताकर बाजार में खपाया जाता था। जांच एजेंसी के अनुसार, इस अवैध कारोबार के जरिए सैकड़ों करोड़ रुपये का धन उत्पन्न किया गया और उसे विभिन्न माध्यमों से छिपाने तथा वैध दिखाने का प्रयास किया गया। एजेंसी की प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपितों ने सीमा क्षेत्र में अपनी जनजातीय पहचान का लाभ उठाते हुए सीमा शुल्क अधिकारियों के समक्ष 'फ्रंट क्लेमेंट' के रूप में भूमिका निभाई। वे जब्त की गई तस्करी की खेप को छुड़ाने के लिए पुराने और असंबंधित आयात दस्तावेजों का इस्तेमाल करते थे तथा माल पर वैध स्वामित्व का दावा करते थे।

जब कानून के रखवाले वसूली करने लगें तो असहाय हो जाता है नागरिक

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अगस्त में मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर नाबालिग के साथ यात्रा कर रहे व्यक्ति से जबरन वसूली और धमकी देने के आरोपी तीन रेलवे पुलिसकर्मियों की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। इन पुलिसकर्मियों को पिछले साल सितंबर में बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहत दी थी। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि जब कानून लागू करने वाले ही जबरन वसूली करने लगें, तो नागरिक असहाय होकर देखता रह जाता है और उसके पास झुकने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को अस्पष्ट बताते हुए उसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि अपने पद का दुरुपयोग करने वाले किसी पुलिस अधिकारी के मामले से निपटते समय एक आम आरोपी व्यक्ति पर लागू होने वाली सामान्य धारणाएं लागू नहीं होंगी। यह घटना पिछले साल अगस्त महीने की है। एक यात्री अपने एक नाबालिग बच्चे के साथ राजस्थान जा रहा था। यात्री ने आरोप लगाया था कि पुलिसकर्मियों ने उसके पास से 14 ग्राम सोने का बिस्कुट और 31,900 रुपए नकद मिलने के बाद उसे हिरासत में ले लिया था और फिर उससे जबरन वसूली की गई।

अस्पताल में धधकने लगी आग, आईसीयू में दम घुटने से 5 मरीजों की मौत

दिल्ली की होटल के बाद मुजफ्फरपुर का अस्पताल बना आग का गोला

मुजफ्फरपुर। दिल्ली के होटल में लगी आग ठीक से शांत भी नहीं हुई थी कि बिहार के मुजफ्फरपुर शहर के ब्रम्हपुरा इलाके में स्थित निजी प्रसाद हॉस्पिटल में गुरुवार तड़के एक हृदयविदारक हादसा सामने आ गया। जहां अस्पताल के आईसीयू (सघन चिकित्सा कक्ष) में भीषण आग लगने से चार मरीजों की दर्दनाक मौत हो गई। इस भयावह आग की घटना में कई अन्य लोग गंभीर रूप से झुलसकर जख्मी हो गए हैं। हालांकि स्थानीय स्तर पर मृतकों की संख्या 10 होने की चर्चा है, लेकिन जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने आधिकारिक तौर पर अब तक 4 मरीजों के मरने की पुष्टि की है। घटना की गंभीरता को देखते हुए हताहतों की संख्या और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। घटना के बाद से ही मौके पर राहत एवं बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है। फायर ब्रिगेड, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमें स्थिति को संभालने में जुटी हुई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर करीब 20 मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) समेत जिले के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। अस्पताल परिसर के पास परिजनों तथा स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई है, जिन्हें नियंत्रित करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बलों को तैनात किया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, यह दर्दनाक हादसा सुबह लगभग 3:20 बजे हुआ। आग अस्पताल की चौथी मंजिल पर स्थित आईसीयू में लगी, जहां उस समय 15 से अधिक मरीज भर्ती थे, जबकि फायर फाइटिंग टीम ने इसकी संख्या लगभग 25 बताई है। ये सभी मरीज पिछले करीब एक सप्ताह से वहां गंभीर स्थिति में भर्ती थे।

दक्षिण-पश्चिम मानसून ने केरल में दी दस्तक

एजेंसी। नई दिल्ली

दक्षिण-पश्चिम मानसून ने तीन दिन की देरी से केरल में गुरुवार को दस्तक दे दी। इसके असर से केरल के साथ-साथ तमिलनाडु और कर्नाटक में कुछ जगहों पर अगले सात दिनों तक भारी बारिश का पूर्वानुमान है। अगले दो-तीन दिन में यह पूरे गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों के अलावा पूर्वोत्तर के राज्यों में आगे बढ़ सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार मानसून ने तेजी से आगे बढ़ते हुए केरल के साथ-साथ लक्षद्वीप, माहे, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया है। इसके अलावा दक्षिण-पश्चिम तथा दक्षिण-पूर्व अरब सागर के बचे हुए हिस्सों और बंगाल की खाड़ी के कई इलाकों में भी मानसून आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 से 3 दिनों के भीतर दक्षिण-पश्चिम मानसून के और आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल हैं। इसके जल्द ही पूरे गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों, कर्नाटक और तमिलनाडु के बाकी हिस्सों, दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी, पश्चिम-मध्य, पूर्व-मध्य तथा उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों सहित पूर्वोत्तर राज्यों में पहुंचने के आसार हैं। केरल में मानसून के आगमन के लिए पिछले दो दिनों से दक्षिण-पूर्व अरब सागर में घने संवहनी बादलों की लगातार बढ़ोतरी देखी गई। निचले स्तरों पर पछुआ हवाओं की रफ्तार करीब 37-46 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई और दक्षिण-पूर्व अरब सागर के ऊपर पछुआ हवाओं की गहराई समुद्र तल से 4.5 किमी ऊपर तक फैली हुई है। पिछले 48 घंटों में केरल के अधिकतर हिस्सों में व्यापक और कुछ जगहों पर भारी बारिश दर्ज की गई। पल्लुरूथी (एर्नाकुलम) में 9 सेमी, मट्टनचेरी (एर्नाकुलम) और कोच्चि आई.ए.एफ., चेरथला (अलापुझा) में 8 सेमी, वैकोम (कोट्टायम) में 7 सेमी, अलुवा, कुमारकम, नेय्याट्टिनकारा, पीरमाडे, कलामासेरी, कुरुदामनिल, वदावथुर, कोच्चि सी.आई.ए.एल. में 6 सेमी, थाइकॉटुस्सेरी, इडुक्की, तिरुवनंतपुरम, थोडुपुझा, मुन्नार और कन्नूर समेत कई इलाकों में 3-5 सेमी तक बारिश हुई। पलक्कड़, वायनाड, मलप्पुरम, कासरगोड और कोझिकोड के कई हिस्सों में 1-2 सेमी तक बारिश हुई। उल्लेखनीय है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून आमतौर पर एक जून को केरल पहुंचता है।

एसयू-30एमकेआई लड़ाकू विमान पहली बार नवी मुंबई हवाई अड्डे पर उतरा

नई दिल्ली। भारतीय वायु सेना का एक सुखोई एसयू-30एमकेआई लड़ाकू विमान गुरुवार को पहली बार नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। यह इस हवाई अड्डे के अब तक के छोटे से परिचालन इतिहास में मील का पत्थर है और यह देश के बढ़ते नागरिक उड्डयन बुनियादी ढांचे में आईएएफ की बढ़ती पहुंच का भी एक प्रदर्शन है। रायगढ़ जिले के उलवे में स्थित नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन पीएम मोदी ने 8 अक्टूबर, 2025 को किया था और इसका वाणिज्यिक परिचालन 25 दिसंबर, 2025 को शुरू हुआ। यह छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ-साथ, मुंबई महानगर क्षेत्र के दूसरे हवाई अड्डे के रूप में कार्य करता है। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन से पहले हुए ट्रायल में विमान की भूमिका से एक कदम आगे है। जब अक्टूबर 2024 में इंडियन एयरफोर्स के सी-295 मीडियम टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट विमान ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहली लैंडिंग की थी, तब एसयू-30एमकेआई सिर्फ रनवे के ऊपर से कम ऊंचाई पर उड़ान भरने के लिए मौजूद था, इस लिहाज़ से गुरुवार की यह फ़ाइटर लैंडिंग इस हवाई अड्डे पर अपनी तरह की पहली घटना है।

Mfg & mkt by.. ANGEN PHARMACEUTICALS (OPC) PRIVATE LIMITED

Distributorship ke liye contact Karen .
(9315755133 / ya email Karen)
angenpharmaceuticals@gmail.com

संक्षिप्त समाचार

कांग्रेस का केंद्र पर महिला-बाल स्वास्थ्य व पोषण जरूरतों की अनदेखी का आरोप

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जरूरतों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने गुरुवार को कहा कि सरकार अपनी विफलता को उजागर करने वाले राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 (एनएफएचएस-6) के अहम आंकड़ों को जानबूझकर छुपा रही है। खरगे ने एक्स पर कहा कि एनएफएचएस-6 के आंकड़े केंद्र सरकार की अक्षमता को सामने लाते हैं। हर पांच में से एक बच्चा तीव्र कुपोषण से पीड़ित है, एक-तिहाई बच्चे कम वजन के हैं और छह से 23 माह के 84 प्रतिशत बच्चों को पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा। 15 से 49 वर्ष की 57 प्रतिशत महिलाएं एनीमिया से ग्रस्त हैं और हर पांच में से एक महिला कुपोषित है। उन्होंने कहा कि सरकार चुनिंदा आंकड़ों को दबाने और प्रचार पर जोर देने जैसी रणनीति अपनाती है, जिससे वास्तविक स्थिति सामने नहीं आ पाती।

कर्दमपुरी वार्ड का निरीक्षण, स्वच्छता, नाला निर्माण और अतिक्रमण हटाने पर जोरः सत्या शर्मा

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने गुरुवार को शाहदरा नॉर्थ जोन के कर्दमपुरी वार्ड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सत्या शर्मा ने वार्ड में स्वच्छता व्यवस्था और समयबद्ध सफाई कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में नियमित, प्रभावी और उच्च मानकों के अनुरूप सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि नागरिकों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण मिल सके। इस दौरान स्थायी समिति की अध्यक्ष ने पंडित राम नारायण वशिष्ठ मार्ग स्थित नाला संख्या-52 का भी निरीक्षण किया। नाले की स्थिति का जायजा लेने के बाद उन्होंने जोनल उपायुक्त को इसके पुनर्निर्माण हेतु विस्तृत लागत अनुमान शीघ्र तैयार कर कार्य प्रारंभ करने को कहा। साथ ही वार्ड की गलियों में स्थित छोटे नालों का निर्माण मानसून से पूर्व पूरा करने पर विशेष जोर दिया, ताकि जलभराव की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। उन्होंने स्थानीय पार्षद को आश्वस्त किया कि विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।साथ ही सत्या शर्मा ने बाबरपुर छठ घाट का दौरा किया, जहां स्थानीय निवासियों ने अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने नागरिकों द्वारा उठाए गए मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों से इनके शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने को कहा।स्थायी समिति अध्यक्ष ने वार्ड में अतिक्रमण की समस्या पर भी सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों से प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने से न केवल नागरिकों की आवाजाही सुगम होगी, बल्कि क्षेत्र के समग्र विकास और सौंदर्यीकरण में भी सुधार आएगा।निरीक्षण के अंत में सत्या शर्मा ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए दिए गए सुझावों का समयबद्ध पालन सुनिश्चित करने पर बल दिया, ताकि कर्दमपुरी वार्ड में नागरिक सुविधाओं को और बेहतर बनाया जा सके। इस अवसर पर स्थानीय पार्षद मुकेश बंसल, जोनल उपायुक्त ममता यादव तथा संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

सलीम डोला के अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ सिंडिकेट पर ईडी की कार्रवाई, 21 ठिकानों पर छापेमारी

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2 और 3 जून को मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम, 2002 के तहत मुंबई, सूरत, अंकलेश्वर और राजकोट में 21 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई सलीम इस्माइल डोला और उसके सहयोगियों द्वारा संचालित अंतरराष्ट्रीय संगठित मादक पदार्थ तस्करी सिंडिकेट की जांच से जुड़े मामले में की गई है।ईडी की तलाशी में सलीम डोला के नेटवर्क को कवर किया गया जिसमें रसायन आपूर्तिकर्ता, रसायन व्यापारी, मेफेड्रोन (एमडी) नामक सिंथेटिक मादक पदार्थ के निर्माता और वितरक, हवाला ऑपरेटर और करोड़ों रुपये की बेनामी संपत्तियों के धारक शामिल हैं। इस कार्रवाई का उद्देश्य अवैध आपूर्ति श्रृंखला और मनी लॉन्ड्रिंग तंत्र की अहम कड़ियों को निशाना बनाकर सिंडिकेट की परिचालन क्षमता और वित्तीय ढांचे को बाधित करना था। तलाशी के दौरान लगभग 1.33 करोड़ रुपये मूल्य की नकदी, विदेशी मुद्रा, सोने की ईंटें और बैंक बैलेंस जब्त व फ्रीज किए गए। इसके अलावा भारत और दुबई स्थित करोड़ों रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज भी बरामद किए गए। एजेंसी ने बताया कि जांच विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा मुंबई में दर्ज कई प्राथमिकी पर आधारित है। अब तक की जांच से स्पष्ट हुआ है कि यह एक अत्यधिक संगठित अंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क है, जो रसायनों की खरीद, मेफेड्रोन का गुप्त निर्माण, अंतरराज्यीय परिवहन और वितरण, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी, हवाला चैनलों के माध्यम से अपराध की आय का संग्रह और परतदार निवेश तथा सहयोगियों और अन्य व्यक्तियों के नाम पर चल-अचल संपत्तियों के अधिग्रहण में संलिप्त है। ईडी ने बताया कि मामले में आगे की जांच जारी है।

सीतारमण ने महिला संचालित मूंगफली प्रसंस्करण इकाई का किया उद्घाटन

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कर्नाटक के यादगीर जिले में महिलाओं के नेतृत्व में संचालित राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) समर्थित मूंगफली प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। यह ऐसी इकाई है, जो मूंगफली को भून सकती है, तेल निकाल सकती है और पीनट बटर जैसे उत्पाद बना सकती है।सीतारमण ने बाडेपल्ली गांव में किसानों के प्रशिक्षण और साझा सुविधा केंद्र का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कर्नाटक के यादगिर स्थित बडेपल्ली गांव में 'किसान प्रशिक्षण एवं साझा सुविधा केंद्र' के उद्घाटन समारोह के दौरान अपने संबोधन में पेड्डापल्ली महिला किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड की सराहना की, जो इस इकाई का संचालन कर रही है। उन्होंने कहा कि कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में स्थापित ऐसी सात मूल्य संवर्धन इकाइयों में से यादगीर की इकाई अकेली है, जिसे पूरी तरह महिलाएं चला रही हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि उन्हें बताया गया है कि इस इकाई का संचालन करने वाली महिलाओं को किसानों से सीधे मूंगफली खरीदने में कठिनाई हो रही है। उन्होंने कहा कि महिलाएं मंडियों एवं बाजारों से खरीद करने की कोशिश कर रही हैं और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने इसके लिए अलग से एक अधिकारी भी नियुक्त किया है। फिर भी ऐसा लगता है कि बीच में कोई बिचौलिया उन्हें सीधे खरीदने से रोक रहा है। स्थानीय प्रशासन से जवाबदेही मांगते हुए उन्होंने पूछा कि कच्चा माल खरीदने में कठिनाई क्यों होनी चाहिए। उन्होंने साथ ही कहा कि केवल एक इकाई से यादगीर के मूंगफली उत्पादन का पूरा उपयोग नहीं हो सकता तथा ऐसे कई और केंद्रों की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन से जुड़ा पश्चिम बंगाल

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) के कार्यान्वयन के लिए गुरुवार को त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) हुआ। नेवा संसदीय कार्य मंत्रालय की एक मिशन मोड परियोजना है। इसका उद्देश्य एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से देशभर की विधानसभाओं के कामकाज को डिजिटाइज़ और आधुनिक बनाना है। एमओयू पर हस्ताक्षर के समय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, विधि एवं न्याय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुनराम मेघवाल, सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन और पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष रथिंद्र बोस उपस्थिति रहे। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में जुड़े। पत्रकारों को संबोधित करते हुए किरेन रिजिजू ने विधायी संस्थानों में डिजिटल परिवर्तन के महत्व पर प्रकाश डाला और पश्चिम बंगाल विधानसभा को पूर्णतः डिजिटल सदन बनाने की दिशा में भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष रथिंद्र बोस ने विश्वास व्यक्त किया कि नेवा के कार्यान्वयन से राज्य में विधायी कार्यप्रणाली की दक्षता, पारदर्शिता और सुलभता में सुधार होगा। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने इस पहल का स्वागत किया और प्रौद्योगिकी को अपनाकर शासन संस्थाओं के आधुनिकीकरण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।

भारत में 25 करोड़ लोग संतुलन विकारों से प्रभावित-वर्टिगो की अनदेखी समस्या के लिए अब दिल्ली में समर्पित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस

» पैसिफिक वनहेल्थ ने देश के अग्रणी न्यूरोटोलॉजिस्ट डॉ. अनिर्बान बिस्वास के नेतृत्व में विशेष केंद्र की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य वर्टिगो और संतुलन संबंधी विकारों के मरीजों के लिए बेहतर निदान, पुनर्वास और दीर्घकालिक रिकवरी सुनिश्चित करना है

लोकतंत्र की शान

नई दिल्लीः भारत में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी 2021 में 13.8 करोड़ से बढ़कर 2031 तक लगभग 19.4 करोड़ होने का अनुमान है, जो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती वृद्ध आबादी में से एक है।[1] इसके बावजूद, चक्कर आना (डिज़ीनेस) और संतुलन संबंधी समस्याएं दुनियाभर में बुजुर्गों के अस्पताल या डॉक्टर के पास जाने के सबसे आम कारणों में शामिल होने के बावजूद[2], भारत में वर्टिगो और संतुलन विकार आज भी बड़े पैमाने पर पहचान, निदान और उपचार की कमी का सामना कर रहे हैं। अनुमान है कि भारत में लगभग 25 करोड़ लोग वेस्टिबुलर और संतुलन संबंधी विकारों से प्रभावित हो सकते हैं। ये ऐसी जटिल लेकिन उपचार योग्य स्थितियां हैं, जिनकी अक्सर पहचान नहीं हो पाती। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि पूरे देश में इन विकारों के निदान और उपचार के लिए 80 से भी कम विशेष क्लीनिक उपलब्ध हैं। इस बढ़ती स्वास्थ्य चुनौती को ध्यान में रखते हुए, पैसिफिक वनहेल्थ ने नई दिल्ली के लाजपत नगर स्थित अपने केंद्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वर्टिगो एंड बैलेंस डिसऑर्डर्स की स्थापना की है। इस केंद्र का नेतृत्व भारत के प्रतिष्ठित न्यूरोटोलॉजिस्ट और देश में वर्टिगो एवं संतुलन विकार प्रबंधन के अग्रदूत माने जाने वाले डॉ. अनिर्बान बिस्वास कर रहे हैं। इस केंद्र का शुभारंभ वर्टिगो अवेयरनेस वीक 2026 (1–7 जून) के दौरान किया गया है, जिसका उद्देश्य लोगों को चक्कर आना, असंतुलन, बिना कारण गिरना और वेस्टिबुलर विकारों के प्रति जागरूक बनाना है। डॉ. अनिर्बान बिस्वास, प्रिंसिपल डायरेक्टर, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोटोलॉजी एवं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वर्टिगो एंड बैलेंस डिसऑर्डर्स, पैसिफिक वनहेल्थ, ने कहा, "वर्टिगो कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह शरीर की संतुलन प्रणाली में किसी गड़बड़ी का संकेत देने वाला एक लक्षण है। दुर्भाग्यवश, हजारों मरीज वर्षों तक परेशानी झेलते रहते हैं क्योंकि चक्कर आने की समस्या को अक्सर तनाव, कमजोरी, बढ़ती उम्र या केवल न्यूरोलॉजिकल समस्या मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। संतुलन विकार केवल कान तक सीमित नहीं होते, बल्कि इनमें मस्तिष्क, दृष्टि, नसें, मांसपेशियां और यहां तक कि मानसिक स्वास्थ्य भी शामिल होता है। भारत में सबसे बड़ी कमी सटीक और समय पर निदान की है। विशेष जांच सुविधाओं और पुनर्वास सेवाओं से युक्त समर्पित बैलेंस डिसऑर्डर सेंटर मरीजों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं तथा उनका आत्मविश्वास, गतिशीलता और जीवन की गुणवत्ता बेहतर बना सकते हैं।" आंकड़े इस समस्या की गंभीरता को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। भारत में लगभग 40 प्रतिशत वयस्क किसी न किसी रूप में वर्टिगो या संतुलन विकार से प्रभावित हैं। उम्र बढ़ने के साथ इसका जोखिम तेजी से बढ़ता है। 60 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक तीन में से एक व्यक्ति और 80 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक दो में से एक व्यक्ति इस समस्या से प्रभावित होता है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर प्रभाव के अलावा, इसके सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी परिणाम भी गंभीर हैं। शोध बताते हैं कि चक्कर आने की समस्या बुजुर्गों में गिरने के जोखिम को 60 प्रतिशत से अधिक बढ़ा देती है[3], जबकि 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में आकस्मिक मृत्यु का सबसे बड़ा कारण गिरना ही है।[3]

अग्निवीर, ओआरओपी और दिव्यांगता पेंशन पर राहुल का मोदी सरकार पर हमला

सरकार बनते ही अग्निवीर योजना खत्म करेंगेः राहुल गांधी

लोकतंत्र की शान, सना खान, ब्यूरो चीफ, दिल्ली

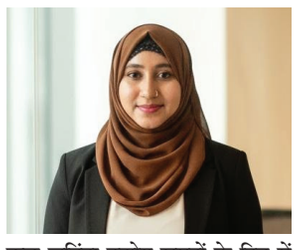

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में आयोजित पूर्व सैनिक एवं अर्धसैनिक बल स्वाभिमान सभा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना भारतीय सेना की परंपरा और सैनिकों के भविष्य के खिलाफ है तथा कांग्रेस की सरकार बनने पर इसे समाप्त कर दिया जाएगा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार सैनिकों को वन रैंक-वन पेंशन (ओआरओपी) और दिव्यांगता पेंशन से जुड़े लाभों से वंचित कर रही है। उन्होंने कहा कि चार साल की सेवा के बाद अग्निवीरों को पर्याप्त सुरक्षा और पेंशन का अधिकार नहीं मिलता, जिससे सैनिकों और उनके परिवारों का भविष्य असुरक्षित हो जाता है। उन्होंने केंद्र सरकार पर बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश की आर्थिक और रक्षा नीतियां कुछ चुनिंदा उद्योग समूहों के हित में चलाई जा रही हैं। भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर भी सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि इससे किसानों, छोटे व्यापारियों और मध्यम उद्योगों को नुकसान होगा। राहुल गांधी ने कहा कि देशहित और सैनिकों के सम्मान की रक्षा के लिए कांग्रेस लगातार आवाज उठाती रहेगी।

कम दर्द, तेज रिकवरीः हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी में DAA तकनीक बनी मरीजों के लिए वरदान - डॉ. ईश्वर बोहरा

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। लगातार बढ़ता हिप दर्द, चलने-फिरने में परेशानी और उठने-बैठने के दौरान होने वाली असहजता आज बड़ी संख्या में लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर रही है। ऐसे मरीजों के लिए अब हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी का एक आधुनिक और अत्याधुनिक विकल्प सामने आया है, जिसे डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच (DAA) टोटल हिप रिप्लेसमेंट कहा जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह तकनीक मरीजों को कम दर्द और तेज रिकवरी का लाभ प्रदान कर रही है। BLK-Max सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में सीनियर डायरेक्टर एवं सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉ. ईश्वर बोहरा के अनुसार, DAA तकनीक पारंपरिक हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की तुलना में अधिक सुरक्षित, कम दर्दनाक और तेजी से रिकवरी देने वाली प्रक्रिया है। डॉ. बोहरा बताते हैं कि इस तकनीक में हिप जॉइंट तक शरीर के सामने वाले हिस्से से एक छोटे चीरे के माध्यम से पहुंचा जाता है। पारंपरिक सर्जरी के विपरीत इसमें मांसपेशियों को काटा नहीं जाता, बल्कि उन्हें सावधानीपूर्वक अलग किया जाता है। इससे ऊतकों को कम नुकसान पहुंचता है और मरीज को ऑपरेशन के बाद कम दर्द का सामना करना पड़ता है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह तकनीक उन मरीजों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो लंबे समय से हिप दर्द, चलने-फिरने में कठिनाई या एक्स-रे में दिखाई देने वाली गंभीर जॉइंट क्षति से जूझ रहे हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस, एवास्कुलर नेक्रोसिस (AVN), पुराने हिप फ्रैक्चर, रूमेटाइड आर्थराइटिस और लंबे समय से गतिशीलता संबंधी समस्याओं से पीड़ित मरीजों को इससे विशेष लाभ मिल सकता है। जब दवाइयां, फिजियोथेरेपी और इंजेक्शन राहत देने में असफल हो जाते हैं, तब DAA हिप रिप्लेसमेंट मरीजों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डॉ. बोहरा के अनुसार, DAA तकनीक के कई फायदे हैं। इसमें छोटा चीरा लगाया जाता है, मांसपेशियों को नुकसान नहीं पहुंचता, रक्तस्राव कम होता है और मरीज जल्दी चलना-फिरना शुरू कर सकता है। अधिकांश मरीज ऑपरेशन वाले दिन ही चलने लगते हैं, अस्पताल में कम समय तक भर्ती रहते हैं और तीन से चार सप्ताह के भीतर अपनी सामान्य दिनचर्या में लौट आते हैं। डॉ. बोहरा ने यह भी बताया कि सफल सर्जरी और बेहतर रिकवरी के लिए ऑपरेशन से पहले की तैयारी भी बेहद महत्वपूर्ण होती है। मरीजों को अपने ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और हृदय स्वास्थ्य को नियंत्रित रखना चाहिए, डॉक्टर को अपनी सभी दवाओं की जानकारी देनी चाहिए, फिजियोथेरेपी करनी चाहिए और घर पर आरामदायक रिकवरी की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि हिप दर्द किसी व्यक्ति की जीवनशैली और दैनिक गतिविधियों को प्रभावित कर रहा है, तो समय रहते उपचार कराना बेहद जरूरी है। DAA तकनीक ने हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी को पहले से अधिक सुरक्षित, सरल और प्रभावी बना दिया है, जिससे मरीज कम समय में अपनी सामान्य जिंदगी में लौट पा रहे हैं।

मालवीयनगर अग्निकांडः मृतकों के परिजनों को 10 लाख, गंभीर घायलों को 5 लाख की सहायता

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में मालवीय नगर अग्निकांड के घायलों से मुलाकात की। दिल्ली सरकार ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि और गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख रुपये की सहायता राशि देने घोषणा की है। यह जानकारी सोशल मीडिया अकाउंट 'सीएमओ दिल्ली' पर साझा की गई है। मुख्यमंत्री ने मैक्स अस्पताल दौरे के दौरान घायलों और उनके परिवार वालों से बातचीत की। उन्होंने उपस्थित डॉक्टरों के साथ चल रहे उपचार की समीक्षा की और अधिकारियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। प्रत्येक मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी और गंभीर रूप से घायल लोगों को 5 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। मृतकों के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक घर ले जाने की व्यवस्था की जा रही है।मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पताल अधिकारियों के समन्वय से घायलों के चिकित्सा खर्च की व्यवस्था की जाएगी, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक मरीज को सर्वोत्तम संभव देखभाल मिले। दिल्ली सरकार प्रत्येक पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने और इस कठिन समय में शोक संतप्त परिवारों को शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं। उल्लेखीनय है कि इस अग्निकांड 21 लोगों की मौत हुई है और घटना की मजिस्ट्रियल जांच का आदेश दिया गया है। रेस्टोरेंट के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। शहर भर में अवैध संपत्तियों, अनधिकृत गेस्ट हाउसों और अग्नि सुरक्षा नियमों एवं भवन निर्माण उपनियमों का उल्लंघन करते हुए संचालित प्रतिष्ठानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे परिसरों को सील कर कानून के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाएगा।

जमाअत के उपाध्यक्ष ने दिल्ली अग्निकांड के पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की, सुरक्षा नियमों के पालन और जवाबदेही की भी मांग की

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष प्रो. सलीम इंजीनियर ने दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में लगी भीषण आग में लोगों की दुखद मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया। रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 21 मृतकों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। मीडिया को जारी एक बयान में प्रोफेसर सलीम इंजीनियर ने कहा, ''मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं और प्रभावित लोगों के लिए शक्ति और धैर्य की प्रार्थना करता हूं। मैं जख्मियों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होने की भी कामना करता हूँ। यह दुखद घटना सुरक्षा नियमों के पालन और उनके क्रियान्वयन में हुई गंभीर चूकों का परिणाम है। होटल में आग से सुरक्षा के बुनियादी उपायों की कथित कमी और तय सीमा से कहीं ज़्यादा मेहमानों को ठहराने के लिए कमरों का इस्तेमाल, खराब प्रशासन और सार्वजनिक स्थानों तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में सुरक्षा नियमों को लागू करने में विफलता को दर्शाता है।''

कांग्रेस नेता अलका लांबा ने 2024 के मामले में बरी होने के लिए दायर की अर्जी

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। वर्ष 2024 में महिला आरक्षण के मामले पर निषेधाज्ञा का उल्लंघन कर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने के मामले में दोषी करार दी गईं कांग्रेस नेता अलका लांबा ने बरी होने के लिए राऊज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी दायर की है। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार ने इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 6 जून को होगी।गुरुवार को इस मामले में अलका लांबा की सजा की अवधि पर सुनवाई होनी थी। अलका लांबा की ओर से पेश वकील इमरान अली ने प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट की धारा 4 के तहत अर्जी दाखिल करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के अच्छे व्यवहार को देखते हुए उसे बरी किया जाना चाहिए। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील चिरनजीत सिंह ने जवाब दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की जिसके बाद कोर्ट ने 6 जून को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया।कोर्ट ने 25 मई को अलका लांबा को दोषी करार दिया था। इस मामले में कोर्ट ने 14 जनवरी को अलका लांबा के खिलाफ औपचारिक रुप से आरोप तय करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने अलका लांबा को भारतीय न्याय संहिता की धारा 132, 221, 233ए और 285 के तहत आरोप तय किया था। कोर्ट ने 20 दिसंबर 2025 को संबंधित घटना का वीडियो देखा था जिसमें पाया गया कि वो बलपूर्वक लोकसेवक को उसके काम में बाधा पहुंचा रही थीं। वो बैरिकेड पार कर प्रदर्शनकारियों को उकसा रही थीं। कोर्ट ने 20 अगस्त 2025 को दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए अलका लांबा को समन जारी किया था। कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 221, 223(ए), 132 और 285 के तहत संज्ञान लिया था।मामला 29 जुलाई 2024 को जंतर-मंतर पर महिला कांग्रेस का महिला आरक्षण को लेकर प्रदर्शन था। उस प्रदर्शन में मुख्य वक्ता अलका लांबा थीं। दिल्ली पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा का आदेश जारी किया था। अलका लांबा पर आरोप है कि उन्होंने निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए करीब डेढ़ बजे दूसरे प्रदर्शनकारियों के साथ टालस्टाय मार्ग पर लगे बैरिकेड पर पहुंचीं और नारेबाजी करने लगीं। वे संसद का घेराव करने पर आमादा थे। मौके पर मौजूद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने लाउडस्पीकर से निषेधाज्ञा के बारे में प्रदर्शनकारियों को जानकारी दी और प्रदर्शन खत्म करने की चेतावनी दी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अलका लांबा और उनके समर्थकों ने महिला और पुरुष पुलिसकर्मियों को धक्का देकर बैरिकेड को पार किया और कुछ प्रदर्शनकारियों ने संसद मार्ग रोड को जाम कर दिया। पुलिस के काफी समझाने के बाद भी अलका लांबा और दूसरे समर्थक वहां से नहीं हटे जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद सब-इंस्पेक्टर अनीता सिंह के बयान पर अलका लांबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।

गडकरी और हरदीप पुरी ने देश की पहली फ्लेक्स-फ्यूल कार का शुभारंभ किया

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ यहां भारत की पहली फ्लेक्स-फ्यूल कार का शुभारंभ किया। यह पहल मारुति सुजुकी द्वारा की गई है। गडकरी ने इस अवसर पर कहा कि फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों से उत्सर्जन में कमी आएगी, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटेगी और लगभग 1.44 लाख करोड़ रुपये का विदेशी मुद्रा बचत संभव होगी। यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ, टिकाऊ और आत्मनिर्भर गतिशीलता के विज़न के अनुरूप है।उन्होंने कहा कि यह कदम बायोफ्यूल को बढ़ावा देगा, किसानों को सहारा देगा, ग्रामीण ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा और रोजगार के अवसर पैदा करेगा। परिवहन क्षेत्र से होने वाले प्रदूषण का हिस्सा लगभग 40 प्रतिशत है और इसे कम करना सरकार की प्राथमिकता है। दिल्ली जैसे शहरों में लोग वायु प्रदूषण के दुष्प्रभावों से भलीभांति परिचित हैं और इस दिशा में ठोस कदम उठाना जरूरी है।गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हरदीप सिंह पुरी की विशेष पहल और मारुति सुजुकी जैसी कंपनियों के सहयोग से भारत ने यह महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है।

संक्षिप्त समाचार

पर्यटन को सांस्कृतिक पुनर्जागरण, रोजगार सृजन और वैश्विक पहचान से जोड़कर आगे बढ़ाएं : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

लोकतंत्र की शान : लखनऊ :- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना, आध्यात्मिक परंपरा और ज्ञान विरासत का प्रतिनिधि प्रदेश है। पर्यटन विकास को केवल आधारभूत संरचना निर्माण तक सीमित न रखते हुए उसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण, स्थानीय अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन और वैश्विक पहचान से जोड़कर आगे बढ़ाया जाना चाहिए। गुरुवार को पर्यटन विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था को नई गति देने में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका है। पर्यटन विकास के माध्यम से स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प, पारंपरिक कला, खानपान, संस्कृति और सेवा क्षेत्र को भी व्यापक अवसर प्राप्त होंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण से जुड़े ज्ञान भारतम् मिशन की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की प्राचीन पांडुलिपियां हमारी सभ्यता, दर्शन, विज्ञान और सांस्कृतिक चेतना की अमूल्य धरोहर हैं। इनका संरक्षण और डिजिटलीकरण केवल अभिलेखीकरण का कार्य नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़ने का माध्यम है। बैठक में अब तक 13 लाख 70 हजार से अधिक पांडुलिपियों के सर्वेक्षण, डिजिटलीकरण और संरक्षण की प्रगति की जानकारी दी गई। पर्यटन नीति-2022 में प्रस्तावित संशोधनों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश को निवेश, नवाचार और अनुभव आधारित पर्यटन का अग्रणी केंद्र बनाया जाए। बैठक में नीम करोली बाबा सर्किट तथा बुंदेलखंड फोर्ट सर्किट के रूप में नए क्षेत्रों के विकास पर चर्चा हुई। साथ ही 'परंपरा' विरासत अनुभव केंद्र, कृषि पर्यटन तथा वाइनयार्ड पर्यटन जैसी नई अवधारणाओं को बढ़ावा देने पर भी विचार-विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन नीति ऐसी हो जो निवेश आकर्षित करे, रोजगार बढ़ाए और पर्यटकों को विशिष्ट अनुभव प्रदान करे।

मुरादाबाद सरकारी अस्पताल की लापरवाही एंबुलेंस में ऑक्सीजन ना होना मैरिज जिंदगी और मौत के बीच जूझते मैरिज

लोकतंत्र की शान : मंडल प्रभारी अवनीत कुमार शर्मा, मुरादाबाद । उत्तर प्रदेश मुरादाबाद/जिला अस्पताल की घोर लापरवाहीः एंबुलेंस में ऑक्सीजन खत्म होने और बेड न मिलने से मरीज जिंदगी और मौत के बीच जूझने को मजबूरमुरादाबादःआज [घटना की तारीख/ 3 जुलाई दिन] बुधवार मुरादाबाद के स्वास्थ्य तंत्र की एक बेहद संवेदनहीन और दर्दनाक तस्वीर सामने आई है, जहाँ जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खुल गई। एंबुलेंस में ऑक्सीजन खत्म होने और जिला अस्पताल में समय पर बेड न मिलने के कारण एक मरीज को घंटों तड़पना पड़ा।प्राप्त जानकारी के अनुसार, मरीज [मरीज का नाम/ अक्षय ठाकुर उम्र] 30 साल की हालत गंभीर होने पर उन्हें [किस क्षेत्र/ मुरादाबाद स्थान] से जिला अस्पताल लाया जा रहा था। आरोप है कि रास्ते में ही एंबुलेंस की ऑक्सीजन समाप्त हो गई, जिससे मरीज की हालत और ज्यादा बिगड़ गई। इसके बावजूद, जब मरीज को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया, तो यहाँ भी उन्हें तत्काल चिकित्सा सुविधा और बेड उपलब्ध नहीं कराया गया।अस्पताल प्रशासन की इस गैर-जिम्मेदाराना रवैये और लेटलतीफी के कारण मरीज को अस्पताल के गलियारों में तड़पने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो मानवीय संवेदनाओं का घोर उल्लंघन है।हमारी प्रमुख माँगेंःइस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए।एंबुलेंस में ऑक्सीजन खत्म होने और अस्पताल में बेड न मिलने के लिए दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई हो।मुरादाबाद के सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए तत्काल प्रभाव से पर्याप्त बेड और ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। मुरादाबाद से पवन गुप्ता की रिपोर्ट

व्यापारी सुरक्षा फोरम 74/ 22 ने पालिका अध्यक्ष के 3 साल पूरे होने पर किया भव्य स्वागत

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा, हसनपुर : गुरुवार को व्यापारी सुरक्षा फोरम 74/22 द्वारा हसनपुर आदर्श नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष राजपाल सैनी के सफलतापूर्वक 3 साल पूरे होने पर उनके आवास पर पहुंचकर जोरदार स्वागत किया और पगड़ी पहनकर तथा कमल के फूल का प्रतीक चिन्ह देकर उनका अभिनंदन किया और शुभकामनाएं दी, व्यापारी सुरक्षा फोरम के पदाधिकारीयो ने पालिका अध्यक्ष के कार्यकाल को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि पिछले 3 सालों में शहर का व्यापारिक माहौल सुरक्षित और सुगम हुआ है जिससे स्थानीय व्यापार को नई ऊर्जा मिली है और संगठन ने पालिका प्रशासन द्वारा धरातल पर किए गए कार्य की सराहना की वहीं इस दौरान पालिका अध्यक्ष ने घोषणा की कि शहर के प्रमुख चौराहों को नई पहचान दी जाएगी उन्होंने कहा कि सड़कों के निर्माण और प्रकार व्यवस्था सहित विकास कार्य अब रुकने वाले नहीं, ताकि आने वाली पीढ़ी अपनी समृद्ध विरासत पर गर्व कर सके पालिका अध्यक्ष ने कहा कि शहर के प्रमुख चौराहों के नाम महापुरुषों के नाम पर रखे जाएंगे, राज्यपाल सैनी ने अपने 3 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते हुए कहा कि कार्यकाल केवल भौतिक विकास नहीं बल्कि जनता के भरोसे के निर्माण का रहा है, उन्होंने शहर की बदलती सूरत का श्रेय हसनपुर की जनता के सहयोग को दिया, इस मौके पर मुख्य रूप से मुकेश गुप्ता, सचिन गुप्ता, पंकज भटनागर, तरुण अग्रवाल, सभासद नितिन सैनी, राजपाल सैनी एवं विक्रांत शर्मा, विशाल वर्मा, रानू रस्तोगी, प्रमोद रोहिल्ला, संजय टाटा, संजय सहदेव, रवि सैनी, जयप्रकाश सैनी, संजीव सैनी, राकेश सैनी, अमरेश कुमार ,ज्योति गर्ग, कविता सिंह, बबीता सैनी, कविता सैनी सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे ।

नजीबाबाद रम्पुरा के गरीब परिवार का राशन डकार रहा राशन डीलर, अधिकारीयो के दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर

लोकतंत्र की शान , खिज़र अहमद, नजीबाबाद क्षेत्र के संतोंमालन शहर से एक गरीब परिवार ने स्थानीय राशन डीलर पर उनका हक का सरकारी राशन न देने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि कई महीनों से उन्हें पूरा राशन नहीं मिल रहा है और जब भी वे डीलर से शिकायत करते हैं तो उन्हें टाल दिया जाता है। परिवार के सदस्यों का आरोप है कि उन्होंने कई बार संबंधित अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगाए, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। गरीब परिवार का कहना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंच पा रहा है, जबकि रिकॉर्ड में पूरा राशन वितरण दिखाया जा रहा है। राशन का कहना है कि यदि समय रहते मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो अन्य जरूरतमंद परिवारों के साथ भी ऐसा ही अन्याय होता रहेगा। उनका आरोप है कि शिकायतों के बावजूद राशन डीलर के खिलाफ कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया जा रहा, जिससे लोगों में प्रशासन के प्रति नाराजगी बढ़ रही है। पीड़ित परिवार ने जिलाधिकारी एवं खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषी पाए जाने पर संबंधित राशन डीलर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि गरीबों को उनका हक मिल सके। अब बड़ा सवाल यह है कि जब एक गरीब परिवार अपने हक के राशन के लिए अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहा है, तो आखिर जिम्मेदार विभाग कब जागेगा और पीड़ितों को न्याय कब मिलेगा?

बिजनौर चंद्रशेखर की धूम नीले रंग में ढग गया था बिजनौर

» 300 यूनिट मुफ्त बिजली, निःशुल्क शिक्षा और गरीबों के मुफ्त इलाज का किया वादा

लोकतंत्र की शान, खिज़र अहमद

आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नगीना लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में गुरुवार को बिजनौर में सत्ता परिवर्तन यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनपद सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। पार्टी नेताओं का आरोप है कि यात्रा को प्रभावित करने के उद्देश्य से प्रशासन द्वारा कई स्थानों पर कार्यकर्ताओं को रोका गया तथा कुछ लोगों को डिटेन किया गया। वहीं यह भी दावा किया गया कि सांसद चंद्रशेखर आजाद को धामपुर स्थित उनके आवास पर कुछ समय के लिए आगे बढ़ने से रोका गया। हालांकि, बाद में वह बिजनौर स्थित इंदिरा बाल भवन पहुंचे, जहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की जनता महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा-स्वास्थ्य जैसी मूलभूत समस्याओं से जूझ रही है। उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश में उनकी सरकार बनती है तो प्रत्येक परिवार को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा तथा गरीबों के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लक्ष्य मानकर गांव-गांव और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। उनके अनुसार, सत्ता परिवर्तन यात्रा का उद्देश्य प्रदेश की जनता को सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए आवश्यक अनुमति संबंधी प्रक्रिया पूरी न होने के कारण कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से एहतियाती कदम उठाए गए। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि उसकी प्राथमिकता क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना है। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह, कमल सिंह वालिया, महासचिव रविंद्र भाटी, मुरादाबाद मंडल प्रभारी खुर्शीद मंसूरी, जिला अध्यक्ष सतेंद्र कुमार, मौलाना अतीक अहमद, अशोक कुमार, सुखवीर प्रधान सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। सत्ता परिवर्तन यात्रा को लेकर पूरे जनपद में राजनीतिक चर्चाओं का माहौल बना रहा। पार्टी नेताओं ने इसे 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी का आगाज बताते हुए संगठन को और मजबूत करने की बात कही।

ऊर्जा मंत्री श्री ए. के. शर्मा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में रचा इतिहास,कई श्रेणियों में प्रथम स्थान

लोकतंत्र की शान

नई दिल्लीः नई दिल्ली में आयोजित "पीएम सूर्य घर पुरस्कार समारोह" में उत्तर प्रदेश ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल कर देशभर में अपना परचम लहराया। राज्य को विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष स्थान प्राप्त हुए, जिससे स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा के क्षेत्र में उसकी अग्रणी भूमिका और मजबूत हुई है।

देश के शीर्ष राज्यों में उत्तर प्रदेश को मिला सम्मान-पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत देशभर में हुए सोलर इंस्टॉलेशन के आधार पर उत्तर प्रदेश ने "टॉप थ्री स्टेट इंस्टॉलेशन" श्रेणी में तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस श्रेणी में गुजरात प्रथम स्थान पर रहा। उत्तर प्रदेश की यह उपलब्धि राज्य में सौर ऊर्जा के प्रति बढ़ती जागरूकता एवं प्रभावी क्रियान्वयन का प्रमाण है।

लखनऊ बना देश का नंबर-1 सोलर जिला-जिला स्तर पर सोलर इंस्टॉलेशन के मामले में लखनऊ ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। लखनऊ में कुल 1,02,596 सोलर इंस्टॉलेशन किए गए, जबकि दूसरे स्थान पर रहे नागपुर में 89,255 इंस्टॉलेशन दर्ज किए गए। यह उपलब्धि उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के तेजी से विस्तार को दर्शाती है।

उच्च उपभोक्ता आधार वाली श्रेणी में उत्तर प्रदेश अव्वल-राज्यवार "वेरी हाई कंज्यूमर बेस" श्रेणी में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। इसके साथ ही सर्वाधिक उपभोक्ता आवेदन, सर्वाधिक सोलर इंस्टॉलेशन तथा अधिकतम वेंडर रजिस्ट्रेशन जैसी महत्वपूर्ण श्रेणियों में भी उत्तर प्रदेश ने देश में पहला स्थान हासिल किया।

UP: आदेश की अवहेलना पर डीएम रामपुर के खिलाफ एक्शन, मानवाधिकार आयोग ने जारी किया 50 हजार का जमानती वारंट

लोकतंत्र की शान, मंडल प्रभारी अवनीत कुमार शर्मा

रामपुर।उत्तर प्रदेश / मानवाधिकार आयोग ने एक सेवानिवृत्त कर्मचारी की न्याय की गुहार को नजर अंदाज करने और बार-बार आदेश के बावजूद रिपोर्ट न सौंपने पर रामपुर के जिलाधिकारी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति राजीव लोचन मेहरोत्रा ने जिलाधिकारी के इस आचरण को अत्यंत आपत्तिजनक माना है। उन्होंने डीएम के खिलाफ 50 हजार रुपये का जमानती वारंट जारी कर एसपी रामपुर को निर्देश दिया है कि वह वारंट की तामील तय समय में करवाएं। दरअसल, रामपुर के ज्वाला नगर निवासी महेश चंद्र सक्सेना 28 फरवरी 1999 को सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो के पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हुए थे। पीड़ित के मुताबिक, शासन के आदेशानुसार, सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो और रजिस्ट्रार कानूनगो का वेतनमान बराबर (1200-2040 रुपये) कर दिया गया था, लेकिन उन्हें इसका लाभ नहीं दिया गया। नतीजतन उनकी पेंशन नहीं बढ़ी। इतना ही नहीं, वर्ष 1986 में लेखपाल पद पर रहने के दौरान उनका 5 माह का वेतन और सेवानिवृत्ति से पहले अक्तूबर 1998 से फरवरी 1999 तक का वेतन भी रोक लिया गया, जो आज तक नहीं मिला।

डीएम के खिलाफ जमानती वारंट जारी-बुजुर्ग अब बीमार और चलने-फिरने में असमर्थ हैं। कई वर्षों तक डीएम रामपुर के यहां सुनवाई नहीं होने पर उन्होंने मानवाधिकार आयोग में शिकायत की थी। इस पर आयोग ने डीएम से आख्या मांगी थी। इसके बावजूद वहां से कोई रिपोर्ट मिली न ही जिम्मेदार अधिकारी उपस्थित हुआ। तब आयोग ने डीएम के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। इसमें कहा गया कि एसपी रामपुर 9 जून तक इस वारंट की तामील कराकर आयोग को सूचित करें। मामले की अगली सुनवाई 10 जून को होगी।

विश्व पर्यावरण दिवस पर बरेली में होगा वृहद वृक्षारोपण अभियान, 7.80 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य

» "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान को जनआंदोलन बनाने की तैयारी, जनसहभागिता पर रहेगा विशेष जोर

लोकतंत्र की शान

(बरेली, उत्तर प्रदेश | संदीप चंद्रा) विश्व पर्यावरण दिवस (05 जून 2026) के अवसर पर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी पहल "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान के अंतर्गत जनपद बरेली में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस अभियान के तहत जनपद में कुल 7.80 लाख पौधों के रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिला प्रशासन ने इस अभियान को केवल सरकारी कार्यक्रम तक सीमित न रखते हुए जनभागीदारी के माध्यम से जनआंदोलन का रूप देने की तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप वृक्षारोपण कार्य समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी ढंग से संपन्न कराया जाए। साथ ही लगाए जाने वाले पौधों के संरक्षण एवं देखभाल की ठोस व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि वृक्षारोपण केवल औपचारिकता न बनकर पर्यावरण संरक्षण का स्थायी माध्यम बन सके। जिलाधिकारी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है और हर नागरिक की इसमें सक्रिय भूमिका होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अधिक से अधिक पौधरोपण अमृत सरोवरों, तालाबों, सड़क किनारों, नदियों एवं नहरों के तटों, विद्यालय परिसरों, पंचायत भवनों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर कराया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि वृक्षारोपण में स्थानीय जलवायु एवं पर्यावरणीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए फलदार एवं छायादार प्रजातियों को प्राथमिकता दी जाए ताकि पर्यावरणीय लाभ के साथ-साथ सामाजिक उपयोगिता भी सुनिश्चित हो सके। अभियान को सफल बनाने के लिए प्रशासन द्वारा विद्यार्थियों, स्वयं सहायता समूहों, सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा आम नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही विभिन्न विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वृक्षारोपण से संबंधित सूचना एवं फोटोग्राफ निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार 'मेरी लाइफ पोर्टल' पर अपलोड किए जाएं तथा सोशल मीडिया के माध्यम से अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।

होटल-हॉस्पिटल की होगी सघन जांच, 7 दिन तक चलेगा फायर सेफ्टी अभियान

» दिल्ली अग्निकांड के बाद बरेली में अलर्ट, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था पर अग्निशमन विभाग की पैनी नजर

लोकतंत्र की शान

(बरेली, उत्तर प्रदेश | संदीप चंद्रा) दिल्ली के एक होटल में हाल ही में हुए भीषण अग्निकांड के बाद बरेली अग्निशमन विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है। लोगों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जनपद में सात दिवसीय विशेष फायर सेफ्टी अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत होटल, अस्पताल, मॉल, बैंक्वेट हॉल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं की गहन जांच की जा रही है, ताकि किसी भी संभावित दुर्घटना को समय रहते रोका जा सके। अभियान के प्रथम दिन अग्निशमन विभाग की टीम ने शहर के प्रमुख होटल स्वर्ण टॉवर का विस्तृत निरीक्षण किया। जांच के दौरान होटल में स्थापित फायर अलार्म सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम, अग्निशमन यंत्र, आपातकालीन निकास मार्ग और सुरक्षा उपकरणों की कार्यक्षमता का परीक्षण किया गया। निरीक्षण में अधिकांश व्यवस्थाएं निर्धारित मानकों के अनुरूप एवं संतोषजनक पाई गईं, जिस पर विभाग ने संतोष व्यक्त किया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी (सीएफओ) मनु शर्मा ने बताया कि यह अभियान केवल औपचारिकता नहीं बल्कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि शहर में स्थित सभी बड़े संस्थानों और सार्वजनिक भवनों की अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं की बारीकी से जांच की जाएगी। जहां कहीं भी सुरक्षा मानकों में कमी या लापरवाही पाई जाएगी, वहां तत्काल सुधार के निर्देश दिए जाएंगे और आवश्यक होने पर नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान विशेष रूप से यह देखा जा रहा है कि फायर अलार्म सिस्टम सक्रिय स्थिति में हैं या नहीं, स्प्रिंकलर सिस्टम सही ढंग से कार्य कर रहा है या नहीं, अग्निशमन उपकरणों की वैधता और उपयोगिता बनी हुई है या नहीं तथा आपातकालीन निकास मार्ग पूरी तरह सुरक्षित और अवरोध मुक्त हैं या नहीं। अग्निशमन विभाग ने होटल संचालकों, अस्पताल प्रबंधन और अन्य प्रतिष्ठानों से अपील की है कि वे फायर सेफ्टी मानकों का पूरी गंभीरता से पालन करें तथा अपने कर्मचारियों को आपदा की स्थिति में बचाव और राहत कार्यों का प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराएं। विभाग का मानना है कि दुर्घटना होने के बाद राहत कार्यों से अधिक महत्वपूर्ण दुर्घटना को होने से पहले रोकना है।

AIMIM ने कस्बा सैद नंगली में आस मोहम्मद को बनाया नगर अध्यक्ष

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा

हसनपुर/ सैद नंगलीः गुरुवार को ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM द्वारा एक दिवसीय कैडर प्रोग्राम का आयोजन किया गया इस बीच संगठन विस्तार और आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई कार्यक्रम के दौरान ए आई एम आई एम AIMIM हसनपुर विधानसभा अध्यक्ष छुन्नन अल्वी ने संगठन का विस्तार करते हुए आस मोहम्मद सैफी को नगर पंचायत नंगली का नगर अध्यक्ष नियुक्त किया, नवनियुक्त अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया, इस अवसर पर पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर भारी संख्या में स्थानीय युवाओं और नागरिकों नेAIMIM एआइएमआइएम की सदस्यता ग्रहण की, यह पार्टी के जनाधार को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, सदस्यता लेने वालों में हाफिज आसिफ, शहजेब सलमानी, फारूक सलमानी, वसीम खान, शाकिर, जुबेर, फरहान, आसिफ, कासिम, समीम, रियाज, शाहिद अहमद सैफी प्रमुख रूप से शामिल रहे, विधानसभा अध्यक्ष छुन्नन अल्वी ने सभी नए सदस्यों को पार्टी की सदस्य दिलाई और उन्हें जनहित के मुद्दे पर सक्रियता से काम करने की अपील की, इस अवसर पर भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे ।

रामपुर में मंगनी की खुशियां मातम में बदलीं, घर से लगभग 5 लाख रुपये का सामान चोरी

लोकतंत्र की शान, मंडल प्रभारी अवनीत कुमार शर्मा

रामपुर। उत्तर प्रदेश/रामपुर के थाना गंज क्षेत्र के मोहल्ला घेर सलावत खां में उस समय हड़कंप मच गया जब एक परिवार के घर में मंगनी की तैयारियों के बीच चोरी की बड़ी वारदात सामने आई। जानकारी के अनुसार परिवार में मंगनी समारोह की तैयारियां चल रही थीं और घर में खुशियों का माहौल था। इसी दौरान अज्ञात चोरों ने घर को निशाना बनाते हुए लाखों रुपये के जेवरात, नकदी और अन्य कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। परिजनों ने जब घर के ताले और अलमारी खोलकर देखी तो सामान गायब मिला। बताया जा रहा है कि चोरी हुए सामान की कीमत करीब 5 लाख रुपये आंकी जा रही है। घटना का पता चलते ही परिवार में कोहराम मच गया और मंगनी की खुशियां गम में बदल गईं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है तथा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। स्थानीय लोगों ने जल्द से जल्द चोरी का खुलासा कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है।

मंगरौला में सड़क हादसाः ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र सिंह खड़कवंशी ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल, बचाई जान

लोकतंत्र की शान

हसनपुरः गुरुवार को हसनपुर42 विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मंगरौला में हुई सड़क दुर्घटना में घायल हुए राहगीरों के लिए ब्लॉक प्रमुख गंगेश्वरी राजेंद्र सिंह खड़कवंशी मसीहा बनकर सामने आए। उन्होंने तत्परता दिखाते हुए सभी घायलों को तुरंत अपने निजी वाहन से सीएचसी हसनपुर भिजवाया, जिससे समय पर इलाज मिलने से उनकी जान बच सकी। प्राप्त जानकारी के अनुसार, मंगरौला-हसनपुर मार्ग पर दो बाइकों की आमने-सामने की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार तीन युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर तड़प रहे थे। उसी दौरान ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र सिंह खड़कवंशी किसी कार्य से मंगरौला से गुजर रहे थे। सड़क पर भीड़ और घायलों को देखकर उन्होंने तुरंत अपना काफिला रुकवाया। ब्लॉक प्रमुख ने बिना समय गंवाए घायलों की स्थिति देखी और अपने साथ चल रहे लोगों की मदद से तीनों को अपनी गाड़ी में लिटाया। इसके बाद वह खुद उन्हें लेकर सीएचसी हसनपुर पहुंचे। वहां डॉक्टरों को तुरंत इलाज शुरू करने के लिए कहा। समय पर अस्पताल पहुंचने से डॉक्टर घायलों की जान बचाने में सफल रहे। चिकित्सकों के अनुसार, यदि 10 मिनट की भी देरी होती तो किसी की जान जा सकती थी। ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र सिंह खड़कवंशी ने कहा कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। सड़क पर कोई घायल पड़ा हो तो उसे अस्पताल पहुंचाना हर नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने लोगों से अपील की कि सड़क हादसा होने पर वीडियो बनाने की बजाय घायलों की मदद करें। आपकी थोड़ी सी मदद किसी की जिंदगी बचा सकती है। घटना की सूचना पर परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने ब्लॉक प्रमुख का आभार जताया। ग्रामीणों ने कहा कि राजेंद्र सिंह खड़कवंशी हमेशा सुख-दुख में जनता के साथ खड़े रहते हैं। इस नेक कार्य के लिए क्षेत्र में उनकी सराहना हो रही है। पुलिस ने भी दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

संक्षिप्त समाचार

वैशाली के पातेपुर सीएचसी में नवजात की मौत, डिलिवरी के बाद इलाज नहीं मिलने से तोड़ा दम

लोकतंत्र की शान , हाजीपुर। वैशाली के पातेपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में एक बार फिर लापरवाही का मामला सामने आया है। बुधवार देर रात अस्पताल में प्रसव के बाद समय पर इलाज न मिलने के कारण एक नवजात शिशु की मौत हो गई। इस घटना से आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया और ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। यह महज दो दिन के भीतर नवजात की मौत का दूसरा मामला है, जिसने स्थानीय स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार, पातेपुर के इमादपुर निवासी विक्रम कुमार की गर्भवती पत्नी दौलत देवी को बुधवार देर रात करीब 1 बजे प्रसव पीड़ा होने पर पातेपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था। भर्ती होने के कुछ ही देर बाद महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। जन्म के समय नवजात का वजन सामान्य से

कम था, लेकिन जच्चा और बच्चा दोनों की स्थिति नियंत्रण में बताई गई थी। कुछ समय बाद कम वजन होने के कारण नवजात की स्थिति बिगड़ने लगी। ड्यूटी पर तैनात एएनएम (ANM) और ममता कार्यकर्ता ने इसकी सूचना तुरंत ऑन-ड्यूटी डॉक्टर को दी। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने खुद मरीज को देखने आने के बजाय एएनएम से रजिस्टर मंगवाया और बिना जांच किए ही नवजात को सदर अस्पताल, हाजीपुर के लिए रेफर कर दिया। परिजनों का कहना है कि "बच्चा जब पैदा हुआ तो रो रहा था। कुछ देर बाद उसने रोना बंद कर दिया। नर्स नीचे से रेफर का पुर्जा लेकर आई और कहा कि डॉक्टर साहब ने हाजीपुर रेफर कर दिया है। जब डॉक्टर देखने ही नहीं आए, तो उन्होंने किस आधार पर रेफर किया? क्या रेफर करने से पहले ही बच्चे की मौत हो चुकी थी?" परिजन जब नवजात को लेकर आनन-फानन में सदर अस्पताल हाजीपुर पहुंचे, तो वहां के डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि बच्चे की धड़कन रुक चुकी है और उसकी मौत हो चुकी है। इसके बाद परिजनों में चीख-पुकार मच गई। आक्रोशित परिजन मृत बच्चे को लेकर वापस पातेपुर अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों की संवेदनहीनता के खिलाफ जमकर हंगामा काटा।

फायरिंग की आवाज सुन बुजुर्ग की हार्ट अटैक से मौत, वैशाली में जमीन विवाद में महिला को गोली लगी

लोकतंत्र की शान , हाजीपुर। वैशाली जिले के बिदुपुर थाना क्षेत्र के रहीमापुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर हुई हिंसक झड़प में एक महिला को गोली लग गई। इस घटना में गोलीबारी की आवाज सुनकर एक बुजुर्ग व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत हो गई। घायल महिला की पहचान 45 वर्षीय गीता देवी के रूप में हुई है, जो तेज नारायण सिंह की पत्नी हैं। उन्हें बाईं ओर सिर में गोली लगी है। घटना के बाद उन्हें तत्काल सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोलीबारी की आवाज सुनकर 65 वर्षीय राजदेव सिंह को हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। राजदेव सिंह स्वर्गीय जुलुम धारी सिंह के पुत्र थे। मृतक राजदेव सिंह किसान थे और खेती करते थे। वह अपने तीन भाइयों व एक बहन में सबसे बड़े थे। उनके दो बेटे और चार बेटियां हैं। इस मामले में अनिल सिंह के पुत्र मनीष कुमार को आरोपी बनाया गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार, घटनास्थल से लगभग 10 राउंड गोली चलने के निशान मिले हैं। पुलिस ने मौके से पांच

खाली खोखे और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। मामले की जांच पड़ताल जारी है। घटनास्थल पर FSL (फोरेंसिक साइंस लैब) टीम बुलाई गई है, जो जांच के लिए सैंपल एकत्र कर रही है। यह जमीनी विवाद जयचन सिंह (40) और तेज नारायण सिंह (डीलर) के बीच चल रहा था। तेज नारायण सिंह के परिजनों ने बताया कि यह विवाद उनकी पुश्तैनी जमीन को लेकर था, जिस पर 6 महीने पहले कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आया था। जिस जमीन पर विवाद चल रहा था, वह एक बथान (पशुओं के रहने का स्थान) है। जब वे वहां कुछ काम कर रहे थे, तभी हमला किया गया। आरोपी पक्ष से वीरेंद्र राय के पुत्र शिवकुमार भी घायल हुए हैं। उनकी कमर के पीछे गोली लगी है। शिवकुमार सुल्तानपुर औद्योगिक कला क्षेत्र के रहने वाले हैं और अपनी बुआ के घर झगड़ा करने आए थे। बिदुपुर के प्रभारी थाना अध्यक्ष आदित्य कुमार ने बताया कि जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए थे, जिसमें मारपीट हुई और गोली चली। उन्होंने पुष्टि की कि एक वृद्ध व्यक्ति की मौत हुई है और घायलों का इलाज चल रहा है। फिलहाल स्थिति पर काबू पा लिया गया है और पुलिस मौके पर मौजूद है। परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया है।

गैस सिलेंडर फटा, एक की मौत, बिदुपुर के कंचनपुर में 3 घायल, परिजन बिना पोस्टमार्टम ले गए शव

लोकतंत्र की शान , हाजीपुर। हाजीपुर के बिदुपुर थाना क्षेत्र के कंचनपुर गांव में गैस सिलेंडर फटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस हादसे में तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने घायलों को तुरंत इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को सदर अस्पताल हाजीपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान कंचनपुर गांव निवासी स्वर्गीय चंद्रकेत राय के 48 वर्षीय पुत्र तोरी राय के रूप में हुई है। डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित किए जाने के बाद परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए ही शव को लेकर चले गए। परिजनों ने घटना का कोई ठोस कारण नहीं बताया और पूछताछ करने पर चुप्पी साधे रहे। इस कारण मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। बिदुपुर थाने की पुलिस भी घटना के संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी देने में असमर्थ दिखी। हालांकि, कंचनपुर के मुखिया रामबचन राय ने घटना का एक अलग कारण बताया है। उनके अनुसार, एक व्यक्ति की मौत एलिवेस्टर गिरने से हुई है, जबकि तीन अन्य घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। मुखिया ने यह भी बताया कि परिजनों ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है। बिदुपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है।

एएनएम स्कूल की प्रभारी प्राचार्य के पति से मांगी रिश्वत, हेल्थ डिपार्टमेंट के एडिशनल डायरेक्टर गिरफ्तार

लोकतंत्र की शान , मुजफ्फरपुर। तिरहुत प्रमंडल के स्वास्थ्य विभाग के रीजिनल एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर अजय कुमार को बुधवार को निगरानी की टीम ने 40 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। डॉक्टर अजय की गिरफ्तारी पटना स्थित अशोका पैलेस के पास से की गई। शिकायतकर्ता पटना के गोपालपुर थाना के बैरिया के रहने वाले विवेक सिंह ने विजिलेंस के पटना स्थित ऑफिस में मामला दर्ज कराया था। शिकायतकर्ता ने बताया कि विजिलेंस को दी गई शिकायत में बताया था कि मेरी पत्नी नेहा कुमारी वर्तमान में वैशाली के महनार स्थित एएनएम स्कूल सह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छात्रावास की प्रभारी प्राचार्या है। उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी फिलहाल प्रेग्नेंट है और उसकी देखभाल के लिए मैं साथ रह रहा हूं। विवेक सिंह के मुताबिक, मैं अपनी पत्नी के साथ रह रहा हूं, इसके एवज में आरोपी डॉक्टर अजय कुमार की ओर से रिश्वत मांगी जा रही थी। आरोपी की ओर से कहा जा रहा था कि अगर रिश्वत नहीं देंगे तो अलग-अलग तरह के आरोप लगाकर आपको पत्नी के पास से हटा दिया जाएगा और आपकी पत्नी को भी सस्पेंड करा दिया जाएगा। शिकायतकर्ता के आरोपों का विजिलेंस ने वेरिफिकेशन किया, जिसमें आरोपी की ओर से मांगी गई रिश्वत की शिकायत सच साबित हुई। इसके बाद इस संबंध में विजिलेंस ने मामला दर्ज किया और पटना विजिलेंस की एएसपी रीता सिन्हा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम की ओर से कार्रवाई करते हुए डॉक्टर अजय कुमार को 40 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगेहाथों पटना के अशोका पैलेस के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी से पूछताछ के बाद विजिलेंस के स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा।

सहरसा के पांच एथलीट का आर्मी में चयन, जिले में खुशी की लहर

लोकतंत्र की शान

सहरसा, मो. जियाउद्दीन, जिला संवाददाताः सहरसा स्टेडियम में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे पांच एथलीट खिलाड़ियों का भारतीय सेना में सफलतापूर्वक चयन होने से जिले में हर्ष का माहौल है। चयनित खिलाड़ियों की इस उपलब्धि ने न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे जिले को गौरवान्वित किया है। जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव सह कोच रोशन सिंह धोनी ने बताया कि कोरोना काल के बाद यह दसवें खिलाड़ी हैं, जिन्होंने आर्मी के लिए क्वालीफाई किया है। इससे पूर्व वर्ष 2025 में भी पांच खिलाड़ियों का चयन आर्मी एवं CISF में हुआ था। आर्मी में चयनित खिलाड़ियों में सुमन कुमार (हकपारा, वार्ड 05), अभिमन्यु कुमार (सराही, वार्ड 08), मनीष कुमार (सलखुआ), संतोष कुमार (मोहनपुर) एवं गौरी शंकर कुमार

(नवहट्टा) शामिल हैं। ये सभी खिलाड़ी वर्ष 2021 से लगातार सहरसा जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए एथलेटिक्स में सक्रिय हैं और कई बार राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग ले चुके हैं। अभिमन्यु कुमार राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भी अपनी प्रतिभा दिखा चुके हैं। सभी खिलाड़ी 800 एवं 1500 मीटर दौड़ के विशेषज्ञ हैं। रोशन सिंह धोनी ने बताया कि सहरसा स्टेडियम में कोशी स्पोर्ट्स अकादमी एवं जिला एथलेटिक्स संघ के संयुक्त तत्वावधान में खिलाड़ियों को नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। यहां खिलाड़ियों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है और बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन स्वरूप नगद पुरस्कार एवं खेल किट भी प्रदान की जाती है। इस वर्ष भी चार खिलाड़ियों—विकास कुमार, विशाल कुमार एवं सोनू कुमार सहित अन्य को सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि यदि जिला प्रशासन का समुचित सहयोग मिलता रहा तो खेल के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रखने के प्रयास और मजबूत होंगे। पांचों खिलाड़ियों खिलाड़ियों के चयन से जिला एथलेटिक्स संघ एवं कोशी स्पोर्ट्स अकादमी के सदस्यों में खुशी का माहौल है। खिलाड़ियों के घरों में भी जश्न का माहौल है, क्योंकि अब सहरसा के बच्चे खेल के माध्यम से रोजगार भी प्राप्त कर रहे हैं। गौरतलब है कि हाल ही में सहरसा की दो सगी बहनों—प्रीतम एवं अंशु—का चयन बिहार पुलिस में हुआ है। दोनों बहनें एथलेटिक्स में लंबी दूरी की दौड़ एवं गोला फेंक प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय स्तर तक भाग ले चुकी हैं। इन सभी उपलब्धियों पर जिला एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष आर.के. सिंह, उपाध्यक्ष सैयद समी अहमद, सचिव रोशन सिंह धोनी, संयुक्त सचिव नीतीश मिश्रा, कोषाध्यक्ष विप्लव रंजन, बिहार एथलेटिक्स कोच रोहित राज, पूर्व विधायक डॉ. आलोक रंजन, जिला बॉल बैडमिंटन संघ के सचिव अंशु मिश्रा, क्रीड़ा भारती के प्रांत अध्यक्ष चंद्रशेखर अधिकारी, जिला योग संघ के सचिव अमन कुमार सिंह एवं जिला हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष दिवाकर सिंह सहित अन्य लोगों ने खुशी जताते हुए खिलाड़ियों को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

सहयोग शिविर व कृषक आईडी निर्माण की समीक्षा, लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन के निर्देश

लोकतंत्र की शान

सहरसा, मो. जियाउद्दीन, जिला संवाददाताः जिलाधिकारी श्री दीपेश कुमार द्वारा आज गूगल मीट के माध्यम से सहयोग शिविर से संबंधित परिवाद पत्रों की वर्तमान स्थिति एवं कृषक आईडी निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों का विस्तृत आकलन किया गया। समीक्षा के क्रम में योजना एवं विकास विभाग, उत्पाद, मद्य एवं निबंधन, पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य, राजस्व, ग्रामीण विकास सहित विभिन्न अंचल स्तर पर सहयोग शिविर से संबंधित कई आवेदन लंबित पाए गए। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को सभी लंबित मामलों का अविलंब निष्पादन सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश दिया। कृषक आईडी निर्माण कार्य की प्रखंडवार समीक्षा के दौरान सौर बाजार एवं सत्तर कटैया सहित कुछ प्रखंडों में प्रगति अत्यंत असंतोषजनक पाई गई। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को कार्यशैली में तत्काल सुधार लाने की कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने निर्देश दिया कि इस महत्वपूर्ण कार्य में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने के लिए मिशन मोड में कार्य किया जाए, ताकि निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

जल जमाव की समस्या के समाधान हेतु जिलाधिकारी का निरीक्षण, अवरोध हटाने व अतिक्रमण पर कार्रवाई के निर्देश

लोकतंत्र की शान

सहरसा, मो. जियाउद्दीन, जिला संवाददाताः नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में जल जमाव की समस्या के समाधान को लेकर किए जा रहे प्रयासों के तहत आज जिलाधिकारी श्री दीपेश कुमार ने सर्वा ढाला एवं सहरसा बस्ती अंतर्गत वार्ड संख्या 27 सहित अन्य क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जल जमाव की समस्या के निदान हेतु आवश्यक उपायों पर संबंधित अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। निरीक्षण के क्रम में सर्वा ढाला क्षेत्र में जिलाधिकारी ने संबंधित तकनीकी पदाधिकारियों एवं नगर निगम को निर्देश दिया कि उक्त स्थल से तिलावे तक पानी के सुगम प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए सभी अवरोधों को अविलंब हटाया जाए। उन्होंने कहा कि इससे कई वार्डों में जल जमाव की समस्या का तात्कालिक समाधान संभव हो सकेगा। इसके साथ ही उन्होंने अतिक्रमण के कारण उत्पन्न जल जमाव की समस्या को गंभीरता से लेते हुए संबंधित क्षेत्रों में शीघ्र अतिक्रमण हटाने के लिए अंचलाधिकारी कहरा को विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान उप विकास आयुक्त, नगर आयुक्त सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।

बालू-गिट्टी सप्लाई में कमीशन को लेकर खूनी झड़प, 12 साल की बच्ची समेत 3 लोग घायल

लोकतंत्र की शान , पटना

पटना जिले के खुसरूपुर थाना क्षेत्र के चैनपुर गांव में गुरुवार सुबह बालू-गिट्टी आपूर्ति में कमीशनखोरी को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। इस दौरान 10 से अधिक राउंड फायरिंग हुई, जिसमें 12 वर्षीय बच्ची समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों के अनुसार, बालू-गिट्टी सप्लाई को लेकर चल रहे विवाद ने अचानक उग्र रूप ले लिया। देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और फायरिंग शुरू हो गई। गोलियों की आवाज सुनते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों में दुबक गए।

बच्ची समेत तीन लोग गोली लगने से घायलः फायरिंग में

विकास कुमार की 12 वर्षीय बेटी नेहा कुमारी, अरुण सिंह की 50 वर्षीय पत्नी सोना देवी और रविंद्र प्रसाद के 26 वर्षीय बेटे दीपक कुमार घायल हो गए। सोना देवी के पैर में जबकि दीपक कुमार के पेट में गोली लगी है। नेहा कुमारी भी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुई है। घटना की सूचना मिलते ही खुसरूपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए खुसरूपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए खुसरूपुर थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ गांव में कैंप कर रहे हैं। इलाके में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और फायरिंग में शामिल आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।

- **खुसरूपुर के चैनपुर में 10 राउंड से अधिक फायरिंग**

दहशत में ग्रामीणः दिनदहाड़े हुई फायरिंग की घटना से चैनपुर गांव के लोग सहमे हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अचानक शुरू हुई गोलीबारी से पूरे इलाके में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई थी। कई परिवारों ने खुद को घरों में बंद कर लिया था। फिलहाल गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। फायरिंग में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

विधायक अनंत सिंह के नंदवां गांव में गीदड़ का हमला

लोकतंत्र की शान , पटना

पटना के मोकामा से जदयू विधायक अनंत सिंह के पैतृक गांव नदावाँ में बुधवार को एक गीदड़ ने अचानक आतंक मचा दिया। दिनदहाड़े गांव में घुसकर उसने कई लोगों पर हमला कर दिया, जिससे छह लोग घायल हो गए। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है और लोग डर के साये में हैं।

कुछ ही मिनटों में छह लोग हुए घायलः जानकारी के अनुसार, दोपहर के समय ग्रामीण अपने घरों में आराम कर रहे थे या गली-मोहल्लों में मौजूद थे। इसी दौरान खेतों की ओर से एक गीदड़ गांव में आ गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, गीदड़ असामान्य रूप से आक्रामक था और सामने आने वाले लोगों पर अचानक हमला करने लगा। ग्रामीणों ने बताया कि जब तक लोग स्थिति को समझ पाते, तब तक गीदड़ छह लोगों को काटकर घायल कर चुका था। हमले के बाद गीदड़ खेतों की तरफ भाग गया। घायल लोगों को तत्काल बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। गंभीर रूप से घायल कुछ लोगों को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है।

पागल होने की आशंका, ग्रामीणों में डरः ग्रामीणों का कहना है कि गीदड़ का व्यवहार सामान्य नहीं था। जिस तरह से उसने लगातार कई लोगों पर हमला किया, उससे उसके पागल या संक्रमित होने की आशंका जताई जा रही है। रात के समय भी गीदड़ की आवाज सुनाई देने से गांव के लोग भयभीत हैं।

पटना के मॉडर्न श्मशान घाट में आज से अंत्येष्टि सेवा

लोकतंत्र की शान , पटना

पटना के बांस घाट में बने हाई टेक श्मशान घाट पर आज से अंत्येष्टि सेवा शुरू हो जाएगी। इस परिसर में एक साथ लगभग 18 अंत्येष्टि की व्यवस्था की गई है, जिसमें 4 विद्युत शवदाह, 6 लकड़ी आधारित शवदाह और 8 पारंपरिक अंत्येष्टि स्थल शामिल हैं। यहां अंत्येष्टि के लिए दान और सहयोग राशि 3500 रुपए तय की गई है। यदि कोई परिवार लकड़ी या खुले में दाह संस्कार करना चाहता है, तो लकड़ी दुकान को अतिरिक्त भुगतान करना होगा।

पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा विकसित इस श्मशान घाट के संचालन की जिम्मेदारी ईशा आउटरीच संस्था को सौंपी गई है। श्रद्धांजलि और पूजा-अर्चना के लिए प्रार्थना स्थल, प्रतीक्षालय, पेयजल, स्वच्छ शौचालय, प्रकाश व्यवस्था, पार्किंग और अन्य आवश्यक नागरिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। यह श्मशान घाट 4.5 एकड़ में फैला है, जिसे 89.40 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है। यह पिछले श्मशान घाट से तीन गुना बड़ा है, जो केवल 1.24 एकड़ में फैला था। मोक्ष द्वार के पास अंत्येष्टि की सामग्री मिलेगी। इसमें कपड़ा, डीप गप्स क्लोथ, लेस गप्स क्लोथ, एकरंगा क्लोथ, राम नाम पट्टी, धोती, घी, चंदन की लकड़ी, देवदार, अगरबत्ती, कपूर, गुलाब जल, पंचमेवा, साड़ी, चूना, माचिस, जौ, हवन सामग्री सहित अन्य जरूरी सामान शामिल हैं।

बढ़ता स्क्रीन टाइम बच्चों के विकास पर खतरा

लोकतंत्र की शान , पटना

मोबाइल फोन, टीवी और अन्य डिजिटल उपकरणों का बढ़ता इस्तेमाल बच्चों के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों में बढ़ता स्क्रीन टाइम आने वाले वर्षों में एक बड़े स्वास्थ्य संकट का कारण बन सकता है। बदलती जीवनशैली, अभिभावकों की व्यस्तता और शारीरिक गतिविधियों में कमी के कारण बच्चे तेजी से डिजिटल उपकरणों पर निर्भर होते जा रहे हैं। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. अजय कुमार (डीएम पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजी) ने इस स्थिति को चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा कि आज कई बच्चे मोबाइल देखे बिना खाना तक नहीं खाते। अभिभावकों की व्यस्त दिनचर्या और परिवार में संवाद की कमी के कारण बच्चों का जुड़ाव अब खेलकूद और सामाजिक गतिविधियों के बजाय मोबाइल फोन, टीवी और अन्य डिजिटल उपकरणों से अधिक हो गया है। पहले बच्चे अपना समय खेलकूद, दोस्तों और परिवार के साथ बिताते थे, लेकिन अब उनका अधिकांश समय स्क्रीन के सामने गुजर रहा है। इसका असर उनके व्यवहार, भाषा

विकास और सीखने की क्षमता पर साफ दिखाई दे रहा है।

कम्यूनिकेशन क्षमता हो रही प्रभावितः डॉ. कुमार ने बताया कि पहले बच्चे अपना अधिकांश समय दोस्तों के साथ खेलने, नई चीजें सीखने और परिवार के साथ बिताते थे, लेकिन अब एक बड़ा वर्ग मोबाइल स्क्रीन तक सीमित होता जा रहा है। इसका सीधा असर उनके व्यवहार, भाषा, सीखने की क्षमता और मानसिक स्वास्थ्य पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है।

मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा गहरा

- **बोलने की क्षमता से लेकर मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा असर, मानसिक और शारीरिक विकास भी डिस्टर्ब**

असरः डॉ. अजय कुमार ने जोर देकर कहा कि शिशु रोग विशेषज्ञ की भूमिका अब केवल बीमारी का इलाज करने तक सीमित नहीं है। बच्चों के संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करना भी चिकित्सकों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्होंने अभिभावकों से स्क्रीन टाइम के खतरों को समझने और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया।

बढ़ रही हैं मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएंः विशेषज्ञों के अनुसार बढ़ते स्क्रीन टाइम का सीधा असर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। लंबे समय तक मोबाइल और टीवी देखने वाले बच्चों में एंजाइटी, तनाव, नींद की समस्या, अवसाद और चिड़चिड़ापन तेजी से बढ़ रहा है।

संक्षिप्त समाचार

सड़क दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित कैशलेस उपचार दिलाने हेतु iRAD / eDAR Pre-Approve प्रक्रिया लागू

PM राहत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पुलिस, अस्पताल एवं कंट्रोल रूम के बीच समन्वित व्यवस्था स्थापित

लोकतंत्र कि शान हसन रशीद जिला ब्यूरो चीफ जबलपुर कटनी मध्य प्रदेशः पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. संतोष डेहरिया के मार्गदर्शन में सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को समय पर उपचार उपलब्ध कराने तथा प्रधानमंत्री सड़क दुर्घटना राहत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर iRAD / eDAR Pre-Approve प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ बनाया गया है। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को बिना किसी विलंब के त्वरित एवं कैशलेस उपचार का लाभ उपलब्ध कराना है, ताकि दुर्घटना के बाद के "गोल्डन आवर" में पीड़ित को शीघ्र चिकित्सा सहायता मिल सके और उसके जीवन की रक्षा की जा सके। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जब भी किसी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को 112, 1033, 108 अथवा अन्य माध्यमों से जिला अस्पताल या किसी निजी अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती कराया जाता है, तब संबंधित अस्पताल, डायल सेवा अथवा पुलिस कर्मचारी द्वारा तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम कटनी को सूचना प्रदान की जाएगी। सूचना प्राप्त होने हेतु पुलिस कंट्रोल रूम कटनी का मोबाइल नम्बर 7587600044 निर्धारित किया गया है। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस कंट्रोल रूम द्वारा संबंधित थाना अथवा चौकी क्षेत्र को तत्काल अवगत कराया जाएगा। इसके पश्चात संबंधित थाना/चौकी द्वारा दुर्घटना की जानकारी iRAD / eDAR पोर्टल पर दर्ज कर आवश्यक आईडी जनरेट की जाएगी तथा प्रधानमंत्री सड़क दुर्घटना राहत योजना अंतर्गत घायल के उपचार हेतु Pre-Approve प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। इस व्यवस्था के माध्यम से पात्र दुर्घटना पीड़ितों को शीघ्र कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध होगी तथा अस्पतालों को भी आवश्यक प्रक्रिया समय पर पूर्ण करने में सहायता मिलेगी। साथ ही संबंधित थाना एवं चौकी द्वारा अस्पताल से सतत समन्वय स्थापित कर घायल के उपचार की निगरानी भी सुनिश्चित की जाएगी।

यमुनानगरःभारत-अमेरिका प्रस्तावित व्यापार समझौते के विरोध में किसानों का प्रदर्शन, ज्ञापन सौंपा

लोकतंत्र की शान : यमुनानगर। यमुनानगर में भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी) के आह्वान पर वीरवार को किसानों ने भारत-अमेरिका प्रस्तावित व्यापार समझौते के विरोध में प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के प्रति नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारी किसान जगाधरी अनाज मंडी परिसर में एकत्रित हुए, जहां से जुलूस के रूप में लघु सचिवालय पहुंचे और प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने केंद्र सरकार से प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते को वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि इसका असर देश के कृषि क्षेत्र, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, छोटे कारोबारियों तथा रोजगार के अवसरों पर पड़ सकता है।इस दौरान विरोध स्वरूप केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। भाकियू के जिला अध्यक्ष संजू ने कहा कि भारत में अधिकांश कृषक छोटे और सीमांत वर्ग से आते हैं, जबकि अमेरिका में कृषि बड़े पैमाने पर आधुनिक तकनीक और सरकारी सहायता के बल पर संचालित होती है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा, कृषि उत्पादन और ग्रामीण आजीविका जैसे संवेदनशील विषयों पर निर्णय लेते समय सभी संबंधित पक्षों से व्यापक विचार-विमर्श आवश्यक है। किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी आपत्तियों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो आंदोलन को व्यापक स्वरूप दिया जाएगा।

जींद : हेरोइन सहित एक नशा तस्कर काबू

लोकतंत्र की शान : जींद। सीआईए स्टाफ नरवाना की टीम ने नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करते हुए चमेला कॉलोनी नरवाना से एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए नशा तस्कर से 10 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। पुलिस आरोपित से नशा नेटवर्क के बारे में पूछताछ कर रही है। सीआईए स्टाफ नरवाना प्रभारी सुखदेव सिंह ने गुरूवार को जानकारी देते हुए बताया कि नशा तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए सीआईए नरवाना की एक टीम सहायक उपनिरीक्षक अवतार सिंह के नेतृत्व में मेला मंडी गेट नरवाना पर मौजूद थी। तभी टीम को सूचना मिली कि चमेला कालोनी निवासी सुलतान जो नशा तस्करी का धंधा करता है और इस समय ठंडी सड़क पर हेरोइन सप्लाई करने की फिराक में खड़ा है।सीआईए टीम तुरंत हरकत में आई और उच्च अधिकारियों को मुखबरी बारे सूचित किया व तत्परता से कारवाई करते हुए ठंडी सड़क पर छापेमारी करके आरोपित सुलतान को मौका पर ही काबू कर लिया। सीआईए टीम ने राजपत्रित अधिकारी राजेश गुप्ता की हाजिरी में सुलतान की नियमानुसार तलाशी ली तो आरोपित की पहनी पेंट की जेब से हेरोइन बरामद हुई। जिसका वजन कुल 10 ग्राम पाय गया।पुलिस ने सुलतान के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। सीआईए स्टाफ नरवाना प्रभारी सुखदेव सिंह ने कहा कि पुलिस आमजन से अपील की है कि नशा तस्करी अथवा अन्य अपराध संबंधी किसी भी सूचना को तुरंत पुलिस के साथ साझा करें ताकि समाज को सुरक्षित और नशामुक्त बनाने की दिशा में सामूहिक प्रयास सफल हो सकें।

लुधियाना में प्रेशर कुकर फटने से घर की दीवार गिरी, मां-बेटे समेत 3 गंभीर घायल

लोकतंत्र की शान : लुधियाना। लुधियाना के जमालपुर इलाके में गुरुवार सुबह एक घर में प्रेशर कुकर फटने से घर की एक दीवार गिर गई और कमरे में आग लग गई। आग की चपेट में आने से टीवी, बेड और अन्य घरेलू सामान जलकर राख हो गया। हादसे के समय घर में मौजूद विनोद, उसकी पत्नी रीमा और 14 वर्षीय बेटा मलबे के नीचे दब गए और आग में झुलस गए। पुलिस के अनुसार यह हादसा जमालपुर के विचित्र नगर में सुबह करीब 6:30 बजे हुआ। परिवार जिस कमरे में सोता था, उसी कमरे में रसोई भी बनी हुई थी। शुरुआती जांच में सामने आया है कि रात के समय परिवार ने खाना बनाते हुए प्रेशर कुकर गैस पर रखा था।

कर्मचारी देंगे धरना जोरदार होगा प्रदर्शन

लोकतंत्र की शान , राजेंद्र करनाल की रिपोर्ट

बहादुरगढ़ः आर.के. नागर, प्रदेश अध्यक्ष-हुडा जन स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन नंबर 1266 प्रेस को बयान जारी करते बताया 5 जून 26 को एचएसवीपी डिवीजन सेक्टर 9 बहादुरगढ़ में विभाग के ठेकेदारों के विरुद्ध अनदेखी ,लापरवाही, और शोषण करने के विरूध सुबह से शाम तक विरोध प्रदर्शन और धरना शुरू किया जाएगा।। धरने के दौरान बहादुरगढ़ डिवीजन के कार्यकारी अभियंता श्री <अमित राठी जी से भी वार्ता की जाएगी। राठी जी ने पहले भी कर्मचारियों के कई मसले सुलजाए हैं, कई मांगे पूरी की है।और ठेकेदारों को फटकार है। अब कई महीने से श्री ओमप्रकाश ठेकेदार और श्री राधे प्रसाद ठेकेदार बहादुरगढ़ व झज्जर के कच्चे कर्मचारियों के खातो में ई.पी.एफ./ ई.एस.आई. के पैसे जमा नहीं करवा रहे हैं। और पिछले महीना का वेतन भी अब तक नहीं दिया है। जब कर्मचारी इसकी मांग करते हैं तो ठेकेदार इनको नौकरी से हटाने की धमकियां देते हैं। एक अश्विनी नाम का सुपरवाइजर भी स्थानीय कर्मचारियों को बार-बार अनावश्यक धमकियां देकर परेशान करता रहता है। इनको पिछले कई महीना पहले श्री अमित राठी जी ने काफी फटकारा था ।और हिदायत जारी की थी कि, अनावश्यक परेशान ना करें । और समय पर वेतन दें। तथा समय पर सबका ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. जमा करवाए। परंतु ठेकेदार है कि, मानते ही नहीं। इसलिए उनके विरूध और ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने की मांग को लेकर तथा कुछ विभागीय ट्यूबवेलों पर अथवा बुस्टिंग स्टेशनों पर लैट्रिन बाथरूम नहीं बने हुए हैं अथवा कंडम हुए पड़े हैं। और कईयो पर रंग रोगन, सफेदी आदि भी नहीं कराई गई है। इस मांग को लेकर भी धरना जारी रहेगा। शेष कल धरने के दौरान जो हालात होंगे प्रेस नोट द्वारा आप सबको सूचित कर दिया जाएगा। धरना सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 तक जारी रहेगा।

गिरा करंट प्रवाहित तार, युवक की मौत

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

सीधी। नगर परिषद चुरहट के वार्ड क्रमांक 8 के एक घर में देर रात 11 हजार केव्ही विद्युत लाइन के करंट प्रवाहित तार के टूटकर गिरने से उसकी चपेट में आए एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार हरीश गुप्ता पिता हरिदास गुप्ता उम्र 37 वर्ष 3 जून की रात करीब 10:30 बजे घर के छत की रेलिंग के पास टहल रहे थे। उसी दौरान घर के समीप से गुजरे 11 हजार केव्ही विद्युत लाइन के तार में शार्ट सर्किट हुआ और करंट प्रवाहित तार टूटकर छत की रेलिंग पर आ गिरा। उसकी चपेट में हरीश गुप्ता भी आ गए। तेज शार्ट सर्किट की आवाज सुनकर जब घर के लोग मौके पर पहुंचे तो हरीश नीचे गिरे हुए थे। उन्हे आनन-फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चुरहट पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया गया। घटना की सूचना मिलने पर चुरहट थाना पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर पंचनामा एवं पोस्टमार्टम कार्रवाई के पश्चात शव परिजनों को सौंप दिया।

अवैध रेत परिवहन के लिए दतला नदी में बने रैम्प व मार्ग जेसीबी से किये गये ध्वस्त

» ग्राम दशरमन में प्रशासन की सख्ती, खनिज एवं रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के लिए बने दतला नदी के चार घाटों पर चली जेसीबी

लोकतंत्र कि शान हसन रसीद जिला ब्यूरो चीफ जबलपुर कटनी मध्य प्रदेश

कटनीः जिले में अवैध खनिज एवं रेत उत्खनन और परिवहन के विरूद्ध जिला प्रशासन का सख्त अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में गुरूवार को ढीमरखेड़ा क्षेत्र के ग्राम दशरमन स्थित दतला नदी से रेत का अवैध उत्खनन कर अवैध परिवहन करने के लिये तैयार किये गये रैम्प और मार्गों को जिला प्रशासन ने जेसीबी मशीन चलाकर ध्वस्त कर दिया। कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देश पर सिलौड़ी के नायब तहसीलदार खगेश भलावी के नेतृत्व में मौके पर पहुंची टीम ने जेसीबी मशीन की सहायता से दतला नदी के तटीय घाटों पर बनाये गये अवैध रैम्प को कटवाया तथा गहरे गड्ढे खुदवाकर मार्ग को पूरी तरह अवरूद्ध कर दिया। ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार का अवैध रेत उत्खनन एवं परिहवन न किया जा सके। रैम्प को तोड़ने और बनाये गये मार्ग को अवरूद्ध करने का यह कार्य सुनारखेड़ाघाट, डबरीघाट, बम्होरी दतलाघाट और शंकरघाट बम्होरी में जेसीबी से कार्यवाही की गई। इसके साथ ही जिला प्रशासन रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन में लिप्त लोगों पर कड़ी नजर रखे हुये है।

जीडीसी कॉलेज के सामने संयुक्त टीम ने हटाया अतिक्रमण

» नगर पालिका, नजूल एवं राजस्व विभाग का अमला रहा मौजूद

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

सीधी। शहर के शासकीय कन्या महाविद्यालय के सामने स्थित करीब दर्जन भर गोमतियों को हटाने का काम नगर पालिका ,नजूल एवं राजस्व विभाग द्वारा किया गया । इस दौरान जेसीबी के माध्यम से बल पूर्वक हटाने की कार्रवाई होनी थी लेकिन आनन-फानन में अधिकांश दुकानदार स्वतः ही अपनी सामग्री एवं गोमतियां हटा लिए । मालूम हो कि नगर पालिका क्षेत्र के कन्या महाविद्यालय के सामने पहले भी अतिक्रमण की शिकायतें थी, जिस पर कार्रवाई हुई थी। इस मामले में मारपीट की वारदातें भी सामने आई थी। फिर से शिकायत होने के बाद नगर पालिका सीएमओ प्रिया पाठक , नगर पालिका के कर्मचारी, अतिक्रमण प्रभारी, नजूल, राजस्व अमला ने व्यापारियों का अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान शुरू किए। यदि गोमती व्यवसायी समय रहते गोमती एवं सामान न हटाते तो बल पूर्वक सामान हटाने की कार्रवाई संयुक्त टीम द्वारा की जा सकती थी। इससे पहले व्यापारियों ने दुकान हटाने से मना किए तब नगर पालिका द्वारा दुकानों को धकेलने का काम भी शुरू किया। इसके बाद आनन-फानन में व्यापारी दहशत में आकर दुकान हटाने के लिए मजबूर हुए।

पहले दी जा चुकी थी नोटिस, फिर हुई कार्रवाईः सीएमओ

इस संबंध में डिप्टी कलेक्टर सह नगर पालिका सीएमओ सुश्री प्रिया पाठक ने बताया कि कन्या कॉलेज के सामने दुकानें हटाने के लिए पहले भी नोटिस दी जा चुकी थी । समय रहते दुकानदारों ने दुकान नहीं हटाई जिस वजह से संयुक्त टीम के साथ आज कार्रवाई की गई। उन्होने बताया कि कुछ व्यवसायी स्वेच्छा से अपनी दुकानें हटा लिए थे। जिन्होने नहीं हटाया उन्हें हटाने का काम किया गया है। सीएमओ सुश्री प्रिया पाठक ने आगे कहा कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। कहीं भी व्यापारी नियम विरुद्ध व्यवसाय संचालित करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।

मेडिकल स्टोरों में ग्राहकों को दवाओं का नहीं दिया जाता पक्का बिल

» सरकार को हर महीने लाखों के राजस्व की हो रही क्षति

» ड्रग इंस्पेक्टर की मनमानी से नियमों की अनदेखी

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

सीधी। जिले में कच्चे बिल पर हर महीने करोड़ों का मेडिकल व्यापार हो रहा है। कच्चे बिल एवं बिना बिल के हो रहे मेडिकल कारोबार से सरकार को प्रतिमाह लाखों के राजस्व की क्षति उठानी पड़ रही है। मेडिकल कारोबार में यह सब कुछ बेखौफ चल रहा है। जिला मुख्यालय सहित अन्य क्षेत्रों में ड्रग इंस्पेक्टर के ढुलमुल रवैया के चलते मेडिकल की दुकानें पूरी तरह से परचून की दुकान सी प्रतीत होती हैं। उचित विधिक कार्यवाही के अभाव में आवश्यक नियमों की खुले आम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। डीआई की लचर व्यवस्था के चलते बाजार का आलम कुछ इस तरह हो चला है कि ज्यादातर मेडिकल स्टोर संचालकों का पूरा व्यापार ही सिर्फ कलकूलेटर के सहारे चल रहा है। मेडिकल स्टोर से दवाईयां क्रय करने के बाद अगर कोई उपभोक्ता बिल की मांग करता है तो उसे कल और परसों की डेट दे दी जाती है। जानकारों की मानें तो नये नीति के तहत हर उपभोक्ता को क्रय की सामग्री का बिल देना अनिवार्य है। अगर कोई दुकानदार ऐसा करने में आनाकानी करता है तो शासन द्वारा इनसे निपटने के लिये सख्त कानून की व्यवस्था की गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिले में ज्यादातर मेडिकल दुकानों का रजिस्ट्रेशन किसी और के नाम से है और संचालित कोई और कर रहा है। शहर के दर्जन भर मेडिकल स्टोर का जायजा लिया गया तो मालुम पड़ा कि ज्यादातर दुकानों पर फार्माशिष्ट गायब थे। जो कि सिर्फ कागजों में देखने को मिलते हैं। शेष समय अयोग्य व्यक्ति द्वारा बिना जानकारी के यूं ही दवाई विक्रय की जाती है। ग्राहकों को क्रय किये गये दवाईयों के बिल न देने की एक वजह यह भी मानी जा रही है कि मेडिकल की दुकानों पर फार्माशिष्ट के कभी दर्शन ही नहीं मिलते हैं। जीएसटी कर जो टैक्स भारत सरकार के खाते में जाना चहिये वह दो नम्बर की काली कमाई में जा रहा है। वर्तमान परिवेश में छोटे व्यापारी के पास जीएसटी के विषय में जानकारी का अभाव है तो वहीं बडे व्यापारियों द्वारा लेखा विभाग से संबधित व्यक्तियों को हर माह लाखों का रूपये का भुगतान सिर्फ इस बात के लिये दिया जाता है कि दो नम्बर को एक नंबर में कैसे बदला जाये। बिल में क्रय किये गये माल और बिना बिल के बीच का अंतर सीधे तौर पर जेब में जा रहा है। सबसे बडी बात जो उभर कर सामने आ रही है वह यह है कि जबाब देह अधिकारी कर्मचारी कभी भी अपने उत्तर दायित्व के निर्वहन हेतु बाजार में औचक निरीक्षण नहीं करते है। सूत्रों की मानें तो ऐसा भी नहीं है कि जबाब देह अधिकारी कर्मचारी की जानकारी में सारा माजरा नहीं है किन्तु व्यापारी और अधिकारी के बीच में सूत्रधार का काम करने वाले विचौलिये अपने दायित्व का निर्वहन भली भॉति कर रहे हैं। अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा अपने दायित्व निर्वहन के प्रति घोर लापरवाही करने के कारण ही सीधी जिले से प्रतिमाह लगभग लाखों रूपये का राजस्व हानि भारत सरकार को उठानी पड रही है।

नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान में फिर बदला मौसम, कई जिलों में आंधी-बारिश

लोकतंत्र की शान

जयपुर। राजस्थान में नए पश्चिमी विक्षोभ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के सक्रिय होने से बुधवार से एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया। प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी और बारिश का दौर शुरू हो गया। उदयपुर जिले में दोपहर बाद बारिश हुई, जबकि डूंगरपुर जिले के साबला क्षेत्र में बेर के आकार के ओले गिरे। मौसम विभाग ने गुरुवार के लिए भी कई जिलों में तेज अंधड़ और बारिश की चेतावनी जारी की है।विभाग के अनुसार 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर और सिरोही को छोड़कर बाकी जिलों में यलो अलर्ट रहेगा।मौसम केन्द्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि एक अन्य मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और अजमेर संभाग के कुछ हिस्सों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंधड़ चलने के साथ मध्यम से कहीं-कहीं तेज बारिश होने की संभावना है।प्रदेश में बुधवार को दिनभर गर्मी और उमस का असर बना रहा। सबसे अधिक तापमान बीकानेर में 43.6 डिग्री सेल्सियस मापा गया।इसके अलावा जैसलमेर में 43.4 और श्रीगंगानगर में 43.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ। मौसम साफ रहने के कारण दिनभर तेज धूप और उमस से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।पिछले 24 घंटों के दौरान सिरोही और उदयपुर जिलों में घने बादल छाए रहे तथा कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। वहीं करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर और दौसा जिलों में भी शाम के समय मौसम में बदलाव देखने को मिला।मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवाओं, मेघगर्जन और बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना जताई है।

अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट में योगाभ्यास कार्यशाला आयोजित

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

सीधी। आगामी 21 जून अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में अल्ट्राटेक सीधी सीमेंट प्लांट में बुधवार 4 जून को एक विशेष योगाभ्यास कार्यशाला का अयोजन यूनिट प्रमुख के दिशा निर्देशन में किया गया। प्रबंधन के ईआर विभाग के संयोजन में आयोजित इस कार्यशाला में बड़ी संख्या में कर्मचारियों, श्रमिकों एवं ट्रेड यूनियन पदाधिकारियों ने सहभागिता कर योग के विभिन्न आयामों की जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम के मुख्य प्रशिक्षक एवं भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध अल्ट्राटेक सीमेंट कर्मचारी एवं खदान श्रमिक संघ ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष वीरभानु सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में स्वस्थ शरीर, शांत मन और संतुलित जीवन के लिए योग सबसे प्रभावी एवं प्राकृतिक साधन है। उन्होंने कहा कि नियमित योगाभ्यास न केवल शारीरिक रोगों से बचाव करता है, बल्कि मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं को भी दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। योग सत्र के दौरान प्रतिभागियों को विभिन्न योगासन, प्राणायाम, श्वास-प्रश्वास की वैज्ञानिक विधियों, ध्यान, उचित विश्राम, संतुलित आहार एवं सकारात्मक सोच के महत्व से अवगत कराया गया। इसके साथ ही सूर्य नमस्कार सहित अनेक योग क्रियाओं का व्यावहारिक अभ्यास भी कराया गया। प्रशिक्षक ने योग को केवल व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा के समन्वय का विज्ञान बताते हुए इसके नियमित अभ्यास पर बल दिया। कार्यशाला का आयोजन ईआर विभागाध्यक्ष दिनेश शर्मा के मार्गदर्शन में किया गया। विभागीय टीम द्वारा की गई उत्कृष्ट व्यवस्थाओं के बीच आयोजित इस कार्यक्रम में ट्रेड यूनियन के महामंत्री, अन्य पदाधिकारी तथा वरिष्ठ श्रमिक बंधुओं ने सक्रिय सहभागिता निभाई। उपस्थित प्रतिभागियों ने योग के महत्व को समझते हुए इसे अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करने का संकल्प भी लिया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, जो व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से सशक्त एवं आध्यात्मिक रूप से जागरूक बनाती है। नियमित योगाभ्यास से कार्यक्षमता, एकाग्रता और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिससे व्यक्ति अपने व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक जीवन में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है।

शिवसैनिको ने फूंका गृह मंत्री का पुतला

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

सीधी। जिले में गुरुवार को उस समय पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई, जब महज 20 से 25 शिवसैनिकों के विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए लगभग 200 पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पुतला दहन कार्यक्रम को लेकर विथिका भवन परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया, जिससे प्रशासन की मंशा पर सवाल उठने लगे हैं। शिवसेना कार्यकर्ता बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और जनसमस्याओं को लेकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारी पुतला लेकर कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने बीच रास्ते में ही पुतला छीन लिया और आगे बढने से रोक दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण था, इसके बावजूद पुलिस का रवैया बेहद सख्त दिखाई दिया। मौके पर चार थाना प्रभारी, दो एसडीओपी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। इतना ही नहीं, वाटर कैनन और फायर ब्रिगेड की गाडियां भी तैनात की गईं। जिले में आमतौर पर बड़े आयोजनों में भी इतनी सुरक्षा व्यवस्था देखने को नहीं मिलती, लेकिन कुछ दर्जन प्रदर्शनकारियों के लिए प्रशासन ने पूरा अमला झोंक दिया। शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पाण्डेय ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने उनकी आवाज दबाने का प्रयास किया। उनका कहना है कि उन्हें कलेक्ट्रेट तक जाने का अधिकार नहीं दिया गया और विथिका भवन के आसपास के सभी रास्तों पर पुलिस का पहरा लगा दिया गया। प्रदर्शनकारियों को लगभग 20 मीटर के दायरे में सीमित कर दिया गया, जिससे उनका विरोध प्रदर्शन प्रभावी रूप से बाधित हो गया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध प्रदर्शन को नागरिकों का संवैधानिक अधिकार माना जाता है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर शांतिपूर्ण प्रदर्शन से प्रशासन इतना भयभीत क्यों दिखाई दिया। जिले में अब यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या पुलिस का उद्देश्य कानून व्यवस्था बनाए रखना था या फिर विरोध की आवाज को कलेक्ट्रेट तक पहुंचने से रोकना।

संक्षिप्त समाचार

तेल अवीव-बेरूत शांति पथ पर, लेबनान में बनेंगे बफर जोन, हिजबुल्लाह ने तोड़ा संघर्ष विराम तो होगा हमला

वाशिंगटन/तेल अवीव/ बेरूत/तेहरान। मध्य पूर्व में तनाव और ईरान के कुवैत पर हुए हमले के बाद अमेरिका को काफी हद तक लेबनान में टकराव रोकने में सफलता मिलती दिखाई पड़ रही है। तेल अवीव और बेरूत ने बुधवार को यहां संघर्ष विराम को फिर से शुरू करने और लेबनान के अंदर कई बफर जोन (पायलट सुरक्षा क्षेत्र, सुरक्षा पट्टी, सैन्य मुक्त क्षेत्र) बनाने पर सहमति जताई है। इस समझौते में कठोरता से कहा गया है कि पायलट सुरक्षा क्षेत्र में ईरान समर्थित आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह का दखल और प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। अमेरिका की मध्यस्थता वाली बातचीत के चौथे दौर के बाद अमेरिका, लेबनान और इजराइल ने संयुक्त बयान जारी किया। इसमें कहा गया कि सैन्य विराम (युद्ध विराम/ सीज फायर) हिजबुल्लाह की गोलीबारी के पूरी तरह बंद होने और लिटानी नदी के दक्षिण के क्षेत्रों से उसके के सभी गुर्गों की निकासी पर निर्भर है।" बयान में दावा किया गया है कि लेबनानी सेना बफर जोन को पूर्ण नियंत्रण में लेगी। सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार वाशिंगटन में की इस घोषणा के बाद दक्षिणी लेबनान पर कई स्थानों पर इजराइल ने ड्रोन से हमला किया है। लेबनान की सरकारी संवाद समिति नेशनल न्यूज एजेंसी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। बुधवार को हुए इस समझौते की घोषणा के बाद इजराइल के रक्षामंत्री इजराइल काट्ज ने गुरुवार को कहा कि लेबनान के साथ हुआ ताजा संघर्ष विराम समझौता अगर हिजबुल्लाह ने तोड़ा तो इजराइल डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) और मजबूती से प्रहार करेगा। उन्होंने कहा कि ब्यूफोर्ट क्षेत्र से इजराइली सेना पीछे नहीं हटेगी। इजराइल के धुर-दक्षिणपंथी नेता इतामार बेन-गविर ने इस संघर्ष विराम को फिर से शुरू करने को एक गंभीर गलती बताया है। लेबनान और इजराइल के बीच हुए समझौते पर ईरान के विदेशमंत्री अब्बास अराघची ने कठोर प्रतिक्रिया दी है। अराघची ने कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत के रास्ते अभी भी खुले हैं। अगर ईरान समर्थित हिज़बुल्ला के खिलाफ इजराइल बेरूत पर कोई हमला करता है तो संघर्ष पूरी तरह से फिर से शुरू हो जाएगा।

अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति ट्रंप के ईरान के साथ युद्ध अधिकार पर रोक लगाई

वाशिंगटन। अमेरिकी कांग्रेस के निचले सदन 'प्रतिनिधि सभा' (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव) ने बुधवार को 215-208 वोटों से एक समवर्ती प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के साथ युद्ध करने के अधिकारों पर रोक लगा दी। महत्वपूर्ण यह है कि डेमोक्रेट्स के इस प्रस्ताव का चार रिपब्लिकन ओहियो के प्रतिनिधि वॉरेन डेविडसन, पेंसिल्वेनिया के ब्रायन फिट्ज़पैट्रिक, मिशिगन के टॉम बैरेट और केंटकी के थॉमस मैसी ने समर्थन किया। एबीसी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रस्ताव में कहा गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान या उसकी सेना या सरकार के किसी भी हिस्से के खिलाफ शत्रुतापूर्ण कार्रवाई में अमेरिकी सशस्त्र बलों का इस्तेमाल तब तक बंद कर देना चाहिए, जब तक कि युद्ध की घोषणा या बल प्रयोग का अधिकार देने वाला कानून पारित न हो जाए। प्रतिनिधि सभा से पारित यह प्रस्ताव अब सीनेट में जाएगा। सीनेट भले ही इसका समर्थन कर दे, लेकिन एक समवर्ती प्रस्ताव में कानून जितना वजन नहीं होता और इसे राष्ट्रपति के सामने पेश नहीं किया जाता, न ही इस पर राष्ट्रपति के वीटो का अधिकार लागू होता है। मतदान के बाद हाउस की विदेश मामलों की समिति के वरिष्ठ डेमोक्रेट ग्रेगरी मीक्स ने पत्रकारों से कहा, "कांग्रेस ने आज संविधान का पालन किया है। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों ने कहा कि अब बहुत हो चुका। अब इस युद्ध को खत्म करने का समय आ गया है। अब राष्ट्रपति को अमेरिकी लोगों को यह बताने का समय आ गया है कि हम इस युद्ध में क्यों शामिल हुए।" युद्ध शुरू होने के बाद से यह चौथी बार है जब हाउस में डेमोक्रेट्स के नेतृत्व वाले ईरान युद्ध अधिकार प्रस्ताव पर मतदान हुआ। वोटिंग से पहले स्पीकर माइक जॉनसन ने कहा, "मुझे लगता है कि इस समय प्रशासन और कमांडर-इन-चीफ से बातचीत करने का अधिकार छीन लेना एक बहुत ही खतरनाक कदम होगा।" व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा कि यह प्रस्ताव छह रिपब्लिकन सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण पारित हुआ है। इस अधिकारी ने कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप कमांडर-इन-चीफ के तौर पर अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करना जारी रखेंगे, और साथ ही कांग्रेस के प्रति पूरी तरह पारदर्शी भी रहेंगे।"

केरल में मानसून के दस्तक देने से बदलने लगा उत्तर प्रदेश का मौसम, कई जिलों में तेज हवा, ओलावृष्टि का अलर्ट

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अगले कुछ घंटों में तेज हवा चलने और ओलावृष्टि की संभावना है। गोरखपुर और बाराबंकी समेत कई जिलों में तेज हवा के साथ हल्की बारिश भी हुई है। मौसम विभाग ने कई जिलों को लेकर जारी अलर्ट में कहा है कि अगले तीन-चार घंटों में लखनऊ और आसपास के जिलों में आंधी-तूफान आने और बौछारें पड़ने की संभावना है। इस बीच केरल में मानसून ने दस्तक दे दी है। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में मानसून दस्तक देने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून भारत में प्रवेश कर चुका है। केरल में मानसून के आगमन की आधिकारिक घोषणा करते हुए मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि अगले तीन से चार दिनों में मानसून कर्नाटक तट से होते हुए गोवा की तरफ आगे बढ़ेगा। परिस्थितियां अनुकूल हैं। 10 जून के बाद मानसून धीमा पड़ सकता है। ऐसा होने से

24 घंटे के अंदर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना बन रही है। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी और गोरखपुर समेत कई जिलों में बौछारें पड़ी हैं। मौसम विभाग के लखनऊ केंद्र के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती हैं। राजधानी लखनऊ, उन्नाव, फतेहपुर, बांदा, प्रयागराज, कौशांबी, मिर्जापुर, जौनपुर, आजमगढ़, वाराणसी, गाजीपुर और कानपुर , चित्रकूट और सोनभद्र समेत कई जिलों में आंधी-पानी की संभावना है। इससे इन जिलों के तापमान में गिरावट आएगी और जबकि कुछ क्षेत्रों में धूलभरी आंधी और ओलावृष्टि भी हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी है । किसानों को भी फसल और पशुओं की सुरक्षा के लिए सतर्क रहने को कहा गया है। लखनऊ केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया उत्तर-पश्चिम भारत में बुधवार को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से जल्द ही यह पूरे प्रदेश को अपनी जद में ले लेगा। इससे पश्चिमी और पूर्वी यूपी में छिटपुट बारिश की संभावना है।

हेलीकॉप्टर के सामने गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने पर कैप्टन से सेना ने मांगी सफाई

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के नासिक में पासिंग आउट परेड के बाद सेना की वर्दी में हेलीकॉप्टर के सामने अपनी गर्लफ्रेंड के समक्ष शादी का प्रस्ताव रखने वाले कैप्टन भारत भारद्वाज पर सेना ने नाराजगी जताई है। सैन्य हेलीकॉप्टर के ठीक सामने घुटनों के बल बैठकर आरुषि को सगाई की अंगूठी पहनाने को सेना ने सैन्य प्रोटोकॉल एवं नियमों का उल्लंघन माना है। सख्त रुख अपनाते हुए सेना ने इस युवा अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है। नासिक के कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल से कैप्टन भारत भारद्वाज ने अपनी फ्लाइट ट्रेनिंग पूरी की और आधिकारिक तौर पर आर्मी एविएशन पायलट के रूप में ग्रेजुएट हुए। पासिंग आउट परेड के दौरान 02 जून को सेना की वर्दी पहने इस युवा अधिकारी ने वहां खड़े एक सैन्य हेलीकॉप्टर के ठीक सामने घुटनों के बल बैठकर आरुषि को सगाई की अंगूठी पहनाई। इस बेहद भावुक पल का यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आया, तो लोगों ने सैन्य उपलब्धि और व्यक्तिगत जीवन के इस खूबसूरत मिलाप की जमकर तारीफ की। वीडियो में आरुषि इस प्रपोजल को स्वीकार करती नजर आ रही हैं और आसपास मौजूद लोग तालियां बजाकर दोनों का उत्साह बढ़ा रहे हैं। रक्षा सूत्रों के अनुसार सेना ने सैन्य वर्दी और सैन्य हेलीकॉप्टर के इस इस्तेमाल पर आपत्ति जताई है, क्योंकि इस तरह सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत प्रदर्शन करना उचित नहीं है। भारतीय सेना ने इस वायरल वीडियो को बेहद गंभीरता से लेते हुए नए-नवेले कैप्टन से जवाब देने को कहा है।

4.5 करोड़ की मादक पदार्थ बरामद, छह तस्कर गिरफ्तार

एजेंसी, कछार (असम)

असम के विभिन्न जिलों में नशा-विरोधी अभियान लगातार जारी है। इस कड़ी में पुलिस ने कछार जिले की विभिन्न इलाकों में चलाए गये अलग-अलग अभियानों में तीन महिला समेत छह ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं, लगभग 4.5 करोड़ मूल्य की मादक पदार्थ भी बरामद किया है। कछार जिला पुलिस मुख्यालय ने गुरुवार को बताया कि उदारबंद पुलिस स्टेशन के अंतर्गत, विश्वसनीय जानकारी के आधार पर, इंट्रा बी-10 ट्रक (एएस-11डीसी-8629) से कुल 8010 बोतलें (100 एमएल) कोडीन कफ सिरप और 150 पैकेट ट्रामाडोल टैबलेट (प्रत्येक पैकेट में 10 स्ट्रिप और एक स्ट्रिप में 24 टैबलेट, यानी कुल 36,000 टैबलेट) बरामद की गईं। एक ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया, जिसकी पहचान ग्यासुद्दीन लस्कर के रूप में हुई है।

एक अन्य अभियान में कलाइन पुलिस स्टेशन के अंतर्गत दिगोरखाल क्षेत्र में नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले में, कलाइन की ओर आ रहे एक ट्रक (एएस-01ईसी-2533) को रोका गया। ट्रक से 14 साबुनदानी में रखी 170 ग्राम संदिग्ध हेरोइन बरामद की गई। इस मामले में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान आजाद उद्दीन के रूप में की गयी है। इसी बीच जिला मुख्यालय शहर सिलचर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत, फतोक बाजार के पास, नशीले पदार्थों की छोटी-मोटी तस्करी करने वाले एक व्यक्ति (तस्कर) अजीम उद्दीन लस्कर उर्फ 'काला' को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान, उसके कब्जे से संदिग्ध हेरोइन से भरी कुल 35 शीशियां बरामद की गईं, जिनका वजन लगभग 1.7 ग्राम था।

जबकि, सिलचर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत, सिलचर रेलवे स्टेशन के पास, नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाली एक महिला- गुल निहार बेगम लस्कर को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से 15 साबुनदानी में रखी 298 ग्राम संदिग्ध हेरोइन बरामद की गई। इस बीच सोनाई पुलिस स्टेशन के अंतर्गत रश्मीना बेगम (31) और ममताज बेगम चौधरी (37) को गुप्त सूचना के आधार पर सोनाई बाजार से गिरफ्तार किया गया। ये दोनों महिलाएं जिरिघाट पुलिस स्टेशन के अंतर्गत माखन नगर बस्ती की निवासी हैं। तलाशी के दौरान, उनके कब्जे से संदिग्ध हेरोइन से भरी 11 साबुनदानी बरामद की गईं। बरामद संदिग्ध हेरोइन का कुल वजन 122 ग्राम था।

मेड़ता रोड सीएचसी जर्जर भवन में चल रही स्वास्थ्य सेवाएं, मामूली बारिश में भी टपकती छत—हादसे का बन रही है खतरा

एजाज़ अहमद उस्मानी

मेड़ता रोड । मेड़ता रोड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) इन दिनों जर्जर भवन की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। भवन की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि मामूली बारिश में भी छत टपकने लगती है, जिससे अस्पताल में उपचार व्यवस्था प्रभावित हो रही है। सीएचसी के अंदर हालात यह हैं कि बारिश का पानी सीधे जांच मशीनों और चिकित्सा उपकरणों पर गिरता रहता है, जिससे न केवल उपकरणों के खराब होने का खतरा बढ़ गया है, बल्कि मरीजों की जांच और उपचार कार्य भी बाधित हो रहा है। अस्पताल में प्रतिदिन करीब ढाई सौ से तीन सौ मरीजों की ओपीडी रहती है, ऐसे में जर्जर भवन की समस्या गंभीर रूप लेती जा रही है। स्थानीय लोगों और चिकित्सा स्टाफ का कहना है कि यह स्थिति लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन अब तक भवन के नवीनीकरण या नए निर्माण की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। बारिश के मौसम में स्थिति और भी खराब हो जाती है, जिससे मरीजों और स्टाफ दोनों को परेशानी झेलनी पड़ती है।

सबसे चिंताजनक बात यह है कि तीन वर्ष पूर्व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) से इसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) के रूप में क्रमोन्नत किया गया था, लेकिन आज तक नया भवन नहीं बन सका है। पुराने भवन की जर्जर स्थिति अब स्वास्थ्य सेवाओं की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर रही है। स्थानीय नागरिकों ने आशंका जताई है कि यदि जल्द ही भवन की मरम्मत या नया निर्माण नहीं किया गया, तो किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। मरीजों की संख्या और बढ़ती जरूरतों को देखते हुए यह स्वास्थ्य केंद्र अब तत्काल ध्यान और कार्रवाई की मांग कर रहा है।

केंद्र ने हरित रसायन आधारित औषधि निर्माण परियोजना को समर्थन देने का किया ऐलान

कई दवाओं का आयात घटेगा

एजेंसी, नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने औषधि निर्माण क्षेत्र में आयात पर निर्भरता घटाने, सतत उत्पादन को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए चेन्नई स्थित बायोनीमटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ग्रीन केमिस्ट्री आधारित परियोजना को समर्थन देने का ऐलान किया है। इस घोषणा के साथ कंपनी को अपनी तकनीकों का व्यावसायीकरण करने और घरेलू स्तर पर सक्रिय औषधि संघटक (एपीआई) तथा नई दवा वितरण प्रणालियों का निर्माण शुरू करने में मदद की जाएगी।

केंद्रीय विज्ञान एवं तकनीक मंत्रालय ने बताया कि परियोजना के तहत मिनॉक्सिडिल, ट्रानेक्सामिक एसिड, डीक्वालिनियम क्लोराइड और उनके इंटरमीडिएट्स का स्वदेशी उत्पादन किया जाएगा। खास तौर पर ट्रानेक्सामिक एसिड का निर्माण कम लागत और पर्यावरण-अनुकूल संश्लेषण मार्ग से किया जाएगा, जो रक्तस्राव संबंधी विकारों के उपचार में उपयोगी है। साथ ही नैनो टेक्नोलॉजी आधारित ड्रग लाइपोसोम एपीआई भी विकसित किए जा रहे हैं, जिनका उपयोग स्तन और त्वचा कैंसर के उपचार में किया जाएगा।

टीडीबी के सचिव राजेश कुमार पाठक ने कहा कि औषधि निर्माण का भविष्य सतत और तकनीक-आधारित उत्पादन प्रणालियों में है, जो गुणवत्ता, दक्षता और पर्यावरणीय जिम्मेदारी को जोड़ते हैं। स्वदेशी एपीआई और नई दवा वितरण प्रणालियों का विकास भारत को वैश्विक फार्मा हब के रूप में मजबूत करेगा।

जल संरक्षण अभियान को नई दिशा देगा मीडिया का सहयोगः राउंड टेबल में सीईओ रंजीत सिंह गोदारा ने दिए महत्वपूर्ण सुझाव

एजाज़ अहमद उस्मानी।

मेड़ता रोड। राजस्थान सरकार के "वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान" के तहत गुरुवार को नागौर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) कार्यालय में मीडिया राउंड टेबल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिले के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल मीडिया के प्रतिनिधियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सीईओ रंजीत सिंह गोदारा ने जिले में चल रहे जल संरक्षण एवं जल संवर्धन कार्यों की विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत परंपरागत जल स्रोतों जैसे बावड़ियों, तालाबों एवं कुओं के संरक्षण के साथ-साथ जल संचयन संरचनाओं के पुनर्जीवन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल संकट आज एक गंभीर चुनौती बन चुका है, ऐसे में जल संरक्षण केवल सरकारी अभियान नहीं बल्कि जनआंदोलन का रूप लेना चाहिए। इसके लिए श्रमदान आधारित जनभागीदारी और व्यापक जनजागरूकता आवश्यक है, जिसमें मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सीईओ ने कहा कि मीडिया समाज का दर्पण होने के साथ-साथ परिवर्तन का सशक्त माध्यम भी है। यदि मीडिया जल संरक्षण जैसे विषयों को प्राथमिकता से उठाए तो आमजन में जागरूकता तेजी से बढ़ सकती है।

बैठक के दौरान राज्य सरकार द्वारा जल प्रबंधन एवं संरक्षण से संबंधित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। साथ ही आगामी कार्ययोजनाओं एवं प्रस्तावित गतिविधियों की जानकारी साझा करते हुए मीडिया प्रतिनिधियों से सुझाव आमंत्रित किए गए। मीडिया प्रतिनिधियों ने हाल ही में जिले के विभिन्न जल स्रोतों के किए गए फील्ड विजिट का अनुभव साझा किया तथा जमीनी स्तर पर देखी गई व्यवस्थाओं पर अपने विचार रखे। उन्होंने सुझाव दिया कि जल संरक्षण कार्यों में जनभागीदारी को और अधिक मजबूत किया जाए तथा परंपरागत जल स्रोतों के संरक्षण के लिए दीर्घकालिक रणनीति अपनाई जाए। इसके साथ ही मीडिया प्रतिनिधियों ने नवाचारों को बढ़ावा देने, स्थानीय स्तर पर जागरूकता अभियानों को तेज करने और युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। बैठक में उपस्थित सभी पक्षों ने इस बात पर सहमति जताई कि प्रशासन, मीडिया और आमजन की संयुक्त भागीदारी से जल संरक्षण अभियान को अधिक प्रभावी, परिणामकारी और स्थायी बनाया जा सकता है। इस अवसर पर जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी डॉ. मनीष जैन सहित जिले के विभिन्न समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक चैनलों, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म एवं अन्य मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

अमेरिका के किसानों के लिए भारत का बाजार खोलने से देश का किसान होगा बर्बादः राहुल गांधी

एजेंसी, देहरादून

लोकसभा में नेता प्रतिप्रक्ष राहुल गांधी ने अल्मोड़ा और पौड़ी की जनसभाओं में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा सरकार की नीतियों पर करारा प्रहार किया। वर्चुअल संबोधन में राहुल गांधी ने कहा कि देश में आर्थिक तूफान आने वाला है। यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो सत्ता में आते ही सबसे पहले अग्निवीर योजना को समाप्त कर देंगे। अमेरिका के किसानों के लिए भारत का बाजार खोलने से देश केकिसान बर्बाद हो जाएंगे।

गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अल्मोड़ा के सिमकनी स्थित एसएसजे विश्वविद्यालय के खेल मैदान पर परिवर्तन का शंखनाद और पौड़ी में कंडोलिया मैदान पर आयोजित जनसभाओं को संबोधित करना था। पंतनगर से राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर ने अल्मोड़ा की ओर उड़ान तो भरी, लेकिन मौसम खराब होने के चलते उन्हें वापस लौटना पड़ा। इसके बाद पंतनगर एयर पोर्ट से फोन के माध्यम राहुल गांधी ने सभा को संबोधित किया। इस बीच पौड़ी कंडोलिया मैदान पर आयोजित पूर्व सैनिक सम्मेलन को भी राहुल गांधी ने वर्चुअली ही संबोधित किया। उन्होंने अपने वर्चुअली संबोधन

में अल्मोड़ा व पौड़ी की जनसभा में शामिल न होने पर माफी मांगी और विश्वास दिया कि जल्द वे उत्तराखंड का दौरा करेंगे।

कांग्रेस नेता ने कहा कि नरेन्द्र मोदी ने कुछ दिन पहले अमेरिका के साथ डील साइन की। इसमें मोदी ने चार चीजें अमेरिका को सौंपी दीं। इससे एनर्जी सुरक्षा खत्म कर दी। अमेरिका के कहने पर ही हम ईंधन खरीद सकते हैं। प्रधानमंत्री ने फूड सुरक्षा को कमजोर किया। अमेरिका के किसानों के लिए भारत का बाजार खुलेगा। अब अमेरिका का किसान अपने उत्पाद भारत में बेच पाएगा। इससे हिन्दुस्तान का किसान बर्बाद हो जाएगा।

♦ खराब मौसम के चलते अल्मोड़ा और पौड़ी नही जा सके राहुल गांधीपंतनगर एयरपोर्ट से ही फोन पर राहुल ने सभा को किया संबोधित

तीसरी चीज हिन्दुस्तान का मेडिकल, व्यवसायिक का डाटा भी मोदी ने अमेरिका का दे दिया। इससे देश पर बड़ा संकट आएगा ही। इसके अलावा मोदी ने लघु उद्योगों को भी समाप्त कर दिया। यह एक सुरक्षा थी, लेकिन मोदी ने यह भी खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि देश में आर्थिक तूफानआने वाला है। उन्होंने ऐलान किया कि यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो सत्ता में आते ही सबसे पहले अग्निवीर योजना को समाप्त कर देंगे।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को कटघरे में खड़ा किया। ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र करते हुए गांधी ने कहा कि भारत अब अमेरिका के इशारे पर चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि देश की तीनों सेनाओं के साथ भी मोदी धोखा कर रहे हैं। उन्होंने अडानी व प्रधानमंत्री के संबंधों पर भी तीखा प्रहार किया।

कोलकाता में वाटर मेट्रो की तैयारी मुख्यमंत्री शुभेंदु ने की बड़ी घोषणा

एजेंसी, कोलकाता

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार को राज्य में जल परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए कोलकाता में जल मेट्रो सेवा शुरू करने की घोषणा की। सचिवालय में केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्वानंद सोनोवाल के साथ हुई उच्चस्तरीय बैठक के बाद उन्होंने यह जानकारी दी। इस बैठक में राज्य और केंद्र के बीच जलमार्ग और बंदरगाह विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी। मुख्यमंत्री ने बताया कि कोलकाता में जल मेट्रो परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे शहर के नदी मार्गों पर यातायात को अधिक सुविधाजनक और आधुनिक बनाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि यह पहल राज्य में जल परिवहन के नए युग की शुरुआत करेगी और शहरी यातायात पर दबाव को भी कम करने में मदद करेगी।

बैठक के दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य में कुल 44 जेटियों का निर्माण किया जाएगा, जबकि राष्ट्रीय जलमार्ग के लिए 25 जेटियों का निर्माण अंतिम चरण में है। इसके अलावा बागबाजार, अहिरीटोला, शोभाबाजार, मल्लिकघाट, रामकृष्णघाट और बांधाघाट जैसे प्रमुख घाटों के सौंदर्यीकरण और मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसे दुर्गा पूजा से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने गंगासागर मेले को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने की योजना पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि कपिलमुनि आश्रम के आसपास के तटीय क्षेत्र का विकास किया जाएगा।

नहीं रहे निर्माता और सेंसर बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी

एजेंसी, मुंबई

हिंदी सिनेमा के वरिष्ठ निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह पिछले कुछ समय से उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं और लिवर से जुड़ी बीमारी से जूझ रहे थे। उनके निधन की खबर सामने आते ही फिल्म उद्योग में शोक की लहर दौड़ गई। बताया जा रहा है कि उनका अंतिम संस्कार आज 4 जून को मुंबई में किया जाएगा। फिल्म जगत की कई हस्तियों ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। पहलाज निहलानी बॉलीवुड के उन निर्माताओं में शुमार थे, जिन्होंने कई सफल और चर्चित फिल्मों का निर्माण किया। उनके बैनर तले बनी 'आंखें', 'अंदाज', 'तलाश', 'रंगीला राजा' और 'जूली 2' जैसी फिल्मों ने दर्शकों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई। फिल्म ट्रेड विश्लेषक अतुल मोहन ने उनके निधन को व्यक्तिगत क्षति बताते हुए कहा कि पहलाज निहलानी का फिल्म उद्योग में विशेष सम्मान था। उन्होंने याद किया कि वितरक उनकी फिल्मों पर भरोसा करते थे और मानते थे कि जिस प्रोजेक्ट से पहलाज जुड़ते हैं, उसकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। पहलाज निहलानी ने वर्ष 2015 से 2017 तक सीबीएफसी अध्यक्ष के रूप में भी अपनी सेवाएं दी थीं। उनका कार्यकाल फिल्मों की सेंसरशिप और प्रमाणन को लेकर हुए कई विवादों और चर्चाओं के कारण सुर्खियों में रहा।

संघ की कार्यप्रणाली में होगा व्यापक परिवर्तन प्रचारकों की संख्या बढ़ाने पर विशेष जोर

एजेंसी, नागपुर

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने शताब्दी वर्ष के उपरांत अपनी कार्यप्रणाली और संगठनात्मक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने की दिशा में बढ़ रहा है। इस परिवर्तन की झलक इस वर्ष आयोजित राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ता विकास वर्ग (द्वितीय) में स्पष्ट रूप से दिखाई दी। संघ के भावी विस्तार को ध्यान में रखते हुए पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं (प्रचारकों) की संख्या में वृद्धि पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

नागपुर में आयोजित कार्यकर्ता विकास वर्ग-द्वितीय में देश के विभिन्न प्रांतों से चयनित 880 शिक्षार्थियों ने भाग लिया है। इनमें 235 प्रशिक्षणार्थी प्रचारक वर्ग से संबंधित हैं, जो कुल प्रतिभागियों का लगभग 26 प्रतिशत है। संघ की संगठनात्मक व्यवस्था में प्रचारकों को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि शाखा विस्तार, संगठन निर्माण, सामाजिक कार्यों के संचालन तथा नेतृत्व विकास में उनकी केंद्रीय भूमिका

रहती है। इसी दृष्टि से इस वर्ष प्रशिक्षण वर्ग में प्रचारकों की भागीदारी को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

गत 11 मई से प्रारंभ हुए इस प्रशिक्षण वर्ग में स्वयंसेवकों को दैनिक शाखा संचालन, सामाजिक कार्य, संगठन विस्तार तथा नेतृत्व विकास से संबंधित विविध विषयों का विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। प्रतिभागियों की पृष्ठभूमि पर दृष्टि डालें तो 583 स्वयंसेवक विभिन्न व्यवसायों से जुड़े हुए हैं, जबकि 62 प्रतिभागी छात्र हैं। इनमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) के विद्यार्थी भी सम्मिलित हैं। शैक्षणिक योग्यता के आधार पर 413 प्रतिभागी स्नातक तथा 332 प्रतिभागी स्नातकोत्तर शिक्षित हैं। इसके अतिरिक्त 31 प्रतिभागी दसवीं तक, 63 प्रतिभागी बारहवीं तक शिक्षित हैं, जबकि 41 कार्यकर्ता अन्य शैक्षणिक श्रेणियों से संबंधित हैं।

संघ के शताब्दी वर्ष के समापन के पश्चात आगामी वर्ष से संगठनात्मक ढांचे में भी परिवर्तन प्रस्तावित है। हाल ही में समालखा (हरियाणा) में सम्पन्न हुई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्यकारिणी बैठक में सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने स्वयं इस परिवर्तन के बारे में जानकारी दी थी। वर्तमान 'प्रांत' व्यवस्था के स्थान पर 'संभाग' आधारित संरचना को अधिक प्रभावी रूप से लागू करने की योजना बन चुकी है। इस नई व्यवस्था के अनुरूप संगठनात्मक आवश्यकताओं में वृद्धि होगी, जिसके परिणामस्वरूप प्रचारकों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता भी महसूस की जा रही है।

पर्यावरण संरक्षण- प्राकृतिक संसाधनों को माफियाओं से मुक्त कराने शासन प्रशासन की चुनौतीः संवैधानिक दायित्व, कानूनी व्यवस्था और मानवता का भविष्य समग्र व्यापक विश्लेषण

लोकतंत्र की शान

» पर्यावरण संरक्षण केवल एक नीति विषय नहीं बल्कि नैतिक, संवैधानिक, सामाजिक और मानवीय दायित्व बन चुका है।

» प्राकृतिक संसाधनों को ज़ब माफियाओं और अवैध दोहन से मुक्त किया जाएगा,तभी एक स्वच्छ, सुरक्षित, स्वस्थ और सम्मानपूर्ण भारत तथा टिकाऊ विश्व व्यवस्था का निर्माण संभव होगा -एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

गोंदिया - वैश्विक स्तरपर विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष हमें यह स्मरण कराता है कि स्वच्छ पर्यावरण केवल प्रकृति का विषय नहीं बल्कि मानव अस्तित्व, संवैधानिक मूल्यों और सभ्यता के भविष्य का प्रश्न है। जल, जंगल, जमीन, स्वच्छ वायु और जैव विविधता केवल संसाधन नहीं हैं, बल्कि जीवन के आधार स्तंभ हैं। दुर्भाग्यवश आज भारत सहित विश्व के अनेक देशों में प्राकृतिक संसाधनों का अवैध और अनियंत्रित दोहन गंभीर चिंता का विषय बन चुका है।अवैध रेत खनन,जंगलों की कटाई भूजल का अंधाधुंध दोहन,नदियों के तटों का विनाश तथा वन्य संसाधनों की तस्करी ने पर्यावरणीय संतुलन को गहरा आघात पहुंचाया है।अनेक स्थानों पर तथाकथित रेती माफिया,वन माफिया,जल माफिया और भूमि माफिया संगठित रूप से कार्य कर रहे हैं। इससे भी अधिक चिंताजनक स्थिति तब उत्पन्न होती है,जब शासन और प्रशासन के कुछ तत्वों पर इन अवैध गतिविधियों के प्रति उदासीनता या मिली भगत के आरोप लगते हैं। परिणामस्वरूप पर्यावरण संरक्षण के लिए बनाए गए कानून और नीतियां कागजों तक सीमित रह जाती हैं। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र सीनियर एडवोकेट ओम मेठी साहब को समर्पित इस आर्टिकल के माध्यम से कहना चाहूंगा क्रि यदि प्राकृतिक संसाधनों को इन अवैध तंत्रों से मुक्त कर प्रभावी संरक्षण सुनिश्चित किया जाए,तो पर्यावरण संरक्षण अभियान को वास्तविक गति और सुचारिता प्राप्त हो सकती है।पृथ्वी केवल वर्तमान पीढ़ी की संपत्ति नहीं है; यह आने वाली पीढ़ियों की अमानत है। इसलिए प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा केवल पर्यावरणीय आवश्यकता नहीं बल्कि सटीक रूप से नैतिक, सामाजिक और संवैधानिक जिम्मेदारी भी है।

साथियों भारतीय संविधान की मूल भावना केवल शासन संचालन तक सीमित नहीं है। संविधान का उद्देश्य ऐसा समाज स्थापित करना है जिसमें प्रत्येक नागरिक को सम्मानपूर्वक, सुरक्षित और स्वस्थ जीवन जीने का अवसर प्राप्त हो।इसी कारण पर्यावरण संरक्षण को भारतीय संवैधानिक दर्शन का अभिन्न अंग बनाया गया।वर्ष1976 में हुए 42 वें संविधान संशोधन के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को विशेष संवैधानिक महत्व प्रदान किया गया। संविधान के अनुच्छेद 48(क) में राज्य को निर्देश दिया गया कि वह पर्यावरण, वन तथा वन्यजीवों की रक्षा और संवर्धन करेगा। इसी प्रकार अनुच्छेद 51(क)(ग) प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य निर्धारित करता है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण, जिसमें वन, झीलें, नदियां और वन्यजीव शामिल हैं, की रक्षा और संवर्धन करे तथा जीवधारियों के प्रति करुणा रखे। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 21, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है,की न्यायिक व्याख्या ने स्वच्छ पर्यावरण को जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा बना दिया है। अनुच्छेद 47 सार्वजनिक स्वास्थ्य के संवर्धन को राज्य का कर्तव्य घोषित करता है।इस प्रकार संविधान स्पष्ट रूप से यह संदेश देता है कि पर्यावरण संरक्षण कोई वैकल्पिक नीति नहीं बल्कि राज्य और नागरिक दोनों की साझा जिम्मेदारी है। साथियों भारतीय न्यायपालिका ने पर्यावरणीय न्यायशास्त्र के विकास में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक महत्वपूर्ण निर्णयों में यह स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ मामलों की श्रृंखला ने पर्यावरणीय कानूनों के क्रियान्वयन को नई दिशा दी।गंगा प्रदूषण,ताजमहल संरक्षण, औद्योगिक प्रदूषण और वाहन उत्सर्जन से जुड़े मामलों में न्यायालय ने कठोर निर्देश जारी किए। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि स्वच्छ जल और प्रदूषणमुक्त वायु का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संरक्षित है। वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ मामले में न्यायालय ने सतत विकास, प्रदूषक भुगतान सिद्धांत तथा पूर्व सावधानी सिद्धांत को भारतीय कानून का हिस्सा माना। टी.एन. गोदावर्मन प्रकरण में वन संरक्षण की व्यापक व्याख्या की गई और वनों की अवैध कटाई पर अंकुश लगाने के लिए महत्वपूर्ण आदेश दिए गए। विभिन्न उच्च न्यायालयों ने भी नदियों, झीलों, भूजल और हरित क्षेत्रों के संरक्षण को नागरिकों के जीवन के अधिकार से जोड़ते हुए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। न्यायपालिका का यह दृष्टिकोण स्पष्ट करता है कि पर्यावरण संरक्षण केवल प्रशासनिक विषय नहीं बल्कि मौलिक अधिकारों का प्रश्न है। साथियों, पर्यावरण संरक्षण के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने समय-समय पर अनेक कानून बनाए हैं। प्रमुख कानूनों में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974; वन संरक्षण अधिनियम, 1980; वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981; पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986; जैव विविधता अधिनियम, 2002; राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 तथा विभिन्न खनन और वन्यजीव संरक्षण संबंधी कानून शामिल हैं। राज्यों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वन विभाग, भूजल प्राधिकरण तथा स्थानीय निकाय पर्यावरणीय नियमों के पालन हेतु जिम्मेदार हैं। परंतु समस्या कानूनों के अभाव की नहीं बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन की है।अनेक क्षेत्रों में अवैध खनन अतिक्रमण और प्राकृतिक संसाधनों की लूट यह संकेत देती है कि निगरानी व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, जवाबदेह तथा तकनीकी रूप से सक्षम बनाने की आवश्यकता है।उपग्रह निगरानी,ड्रोन सर्विलांस, डिजिटल खनन ट्रैकिंग, ई- परमिट व्यवस्था और सामाजिक लेखा परीक्षा जैसे उपायों को मजबूत बनाना होगा। साथ ही, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में संलिप्त संगठित अपराध समूहों तथा उनके संरक्षणकर्ताओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई आवश्यक है। जब तक कानून का निष्पक्ष और समान रूप से पालन नहीं होगा, तब तक पर्यावरणीय न्याय का लक्ष्य अधूरा रहेगा। साथियो, पर्यावरण संरक्षण केवल राष्ट्रीय नहीं बल्कि वैश्विक चिंता का विषय है। इसी कारण अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने समय-समय पर अनेक संधियों और समझौतों के माध्यम से पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने का प्रयास किया है। वर्ष 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन आधुनिक वैश्विक पर्यावरण आंदोलन की महत्वपूर्ण शुरुआत माना जाता है। इसके बाद 1992 का रियो अर्थ समिट, जैव विविधता सम्मेलन (सीबीडी), संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय,क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रामसर कन्वेंशन,संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण निरोधक अभिसमय तथा पेरिस जलवायु समझौता वैश्विक पर्यावरण शासन के प्रमुख स्तंभ बने। विशेष रूप से पेरिस समझौते ने वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने का सामूहिक लक्ष्य निर्धारित किया।मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को ओजोन परत संरक्षण के क्षेत्र में सबसे सफल अंतरराष्ट्रीय समझौतों में गिना जाता है। इन सभी संधियों का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके। भारत इन अधिकांश अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का सक्रिय भागीदार रहा है और उसने नवीकरणीय ऊर्जा, हरित विकास तथा जलवायु कार्रवाई के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहलें भी की हैं। साथियों अंतरराष्ट्रीय समझौतों के बावजूद इसके बावजूद वर्तमान समय में पर्यावरणीय संकट लगातार गंभीर होता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन आज मानवता के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। वैश्विक तापमान में वृद्धि, अनियमित वर्षा,अत्यधिक गर्मी,लंबे सूखे, असामान्य ठंड, समुद्र स्तर में वृद्धि तथा जैव विविधता का क्षरण विश्वभर में दिखाई दे रहा है।कई बार गर्मियों में ओलावृष्टि वर्षा ऋतु में असामान्य शुष्कता, शीतकाल में असामान्य गर्मी और मौसम चक्रों में व्यापक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। हाल के वर्षों में विश्व ने अनेक विनाशकारी चक्रवातों और तूफानों का सामना किया है, जिनमें भारत और आसपास के क्षेत्र में आए चक्रवात अम्फान, ताउते,यास, बिपरजॉय, मिचौंग, रेमल तथा अन्य उष्णकटिबंधीय तूफान उल्लेखनीय हैं। इसके अतिरिक्त यूरोप, अमेरिका, एशिया और अफ्रीका के अनेक हिस्सों में भीषण बाढ़, जंगलों में आग, हीटवेव और सूखे की घटनाएं बढ़ी हैं।हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियरों का पिघलना, भू-स्खलन, बादल फटना और अचानक बाढ़ जैसी घटनाएं नई चिंताएं उत्पन्न कर रही हैं,इसपर वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान स्वरूप में दोहन जारी रहा, तो आने वाले दशकों में जल, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर सटीकता से गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है। साथियों, आज आवश्यकता केवल पर्यावरण दिवस मनाने की नहीं, बल्कि पर्यावरणीय चेतना को व्यवहार में उतारने की है। यदि प्राकृतिक संसाधनों के अवैध दोहन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जाए, अवैध खनन और वन विनाश में संलिप्त तत्वों के विरुद्ध निष्पक्ष कार्रवाई हो, प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित की जाए तथा नागरिकों की सक्रिय भागीदारी बढ़ाई जाए, तो पर्यावरण संरक्षण के प्रयास कहीं अधिक प्रभावी हो सकते हैं।पर्यावरणीय अपराधों को केवल आर्थिक अपराध नहीं बल्कि भावी पीढ़ियों के अधिकारों के विरुद्ध अपराध के रूप में देखने की आवश्यकता है। शासन, न्यायपालिका, प्रशासन, वैज्ञानिक समुदाय, नागरिक समाज और आम नागरिकों को मिलकर ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें विकास और पर्यावरण संरक्षण परस्पर विरोधी नहीं बल्कि पूरक बन सकें। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे क्रि यह समझना होगा कि स्वच्छ पर्यावरण संविधान का मूल्य है, मानव अधिकार है और सभ्यता के अस्तित्व का आधार है। प्रकृति का संरक्षण केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि राष्ट्रीय चरित्र का प्रश्न है। जब प्रत्येक नागरिक पर्यावरण संरक्षण को अपने जीवन का हिस्सा बनाएगा,जब प्रशासन पारदर्शी और जवाबदेह होगा, जब कानूनों का कठोर और निष्पक्ष पालन होगा तथा जब प्राकृतिक संसाधनों को माफियाओं और अवैध दोहन से मुक्त किया जाएगा, तभी एक स्वच्छ, सुरक्षित, स्वस्थ और सम्मानपूर्ण भारत तथा टिकाऊ विश्व व्यवस्था का निर्माण संभव होगा। यही आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी सच्ची जिम्मेदारी और सबसे बड़ी पर्यावरणीय विरासत होगी।

-संकलनकर्ता लेखक - क्रर विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यमा सीए (एटीसी) एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र 9284141425

राहुल गांधी का मूल्यांकनः क्या भारतीय राजनीति में उनके साथ न्याय हुआ है?

लेखक- भूपेन्द्र गुप्ता

भारतीय राजनीति में शायद ही कोई नेता ऐसा रहा हो जिसकी आलोचना और चर्चा उतनी हुई हो जितनी राहुल गांधी की। पिछले डेढ़ दशक में उन्हें कभी अनुभवहीन, कभी अनिच्छुक राजनेता और कभी वंशवाद का प्रतीक बताया गया। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने भी राहुल गांधी को well-intentioned dilettante कहा था—अर्थात अच्छी नीयत रखने वाला किंतु शौकिया राजनेता। प्रश्न यह है कि क्या यह मूल्यांकन आज भी उतना ही प्रासंगिक है, या समय ने इस निष्कर्ष को चुनौती दी है? राहुल गांधी के आलोचक प्रायः उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि को उनके राजनीतिक जीवन का केंद्रीय तथ्य मानते हैं। इसमें संदेह नहीं कि वे भारत के सबसे प्रसिद्ध राजनीतिक परिवार से आते हैं। किंतु क्या किसी नेता का अंतिम मूल्यांकन उसके उपनाम से होना चाहिए या उसके सार्वजनिक जीवन के कार्यों से? यदि केवल वंशवाद ही कसौटी है, तो भारतीय राजनीति के अनेक दलों और नेताओं की वैधता पर समान प्रश्न उठने चाहिए। लगभग हर बड़े दल में ऐसे नेता मौजूद हैं जिनकी प्रारंभिक राजनीतिक पहचान पारिवारिक विरासत से बनी। किंतु उनके मूल्यांकन में अक्सर उनकी राजनीतिक क्षमता, जनाधार और चुनावी प्रदर्शन को भी महत्व दिया जाता है। राहुल गांधी के मामले में यह उदारता कम दिखाई देती है। पिछले वर्षों में राहुल गांधी ने भारतीय राजनीति में एक अलग प्रकार की राजनीतिक शैली प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा केवल राजनीतिक अभियान नहीं थे; वे जनता से प्रत्यक्ष संवाद स्थापित करने के प्रयास भी थे। हजारों किलोमीटर की यात्राएँ, लगातार जनसंपर्क और विभिन्न सामाजिक समूहों से संवाद किसी ऐसे नेता की तस्वीर प्रस्तुत करते हैं जिसे राजनीति में रुचि नहीं है, यह कहना कठिन हो जाता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि राहुल गांधी ने अत्यंत प्रतिकूल राजनीतिक वातावरण में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखी है। भारतीय राजनीति में ऐसे अनेक नेता रहे हैं जो एक बड़ी चुनावी हार के बाद सार्वजनिक जीवन के हाशिये पर चले गए। इसके विपरीत राहुल गांधी राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख विपक्षी चेहरों में बने रहे, लोकसभा में चुने जाते रहे और विपक्षी विमर्श को प्रभावित करते रहे। किसी भी लोकतंत्र में यह स्वयं एक राजनीतिक उपलब्धि मानी जाती है। यहीं रामचंद्र गुहा जैसे विश्लेषकों के मूल्यांकन पर प्रश्न उठता है। यदि किसी नेता की सफलता का मापदंड केवल सत्ता प्राप्ति है, तो लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका का महत्व कम हो जाता है। और यदि सफलता का मापदंड जनसंपर्क, वैचारिक हस्तक्षेप, संगठनात्मक प्रभाव और सार्वजनिक स्वीकार्यता भी है, तो राहुल गांधी का मूल्यांकन अधिक संतुलित होना चाहिए। गुहा की आलोचना का एक दूसरा पक्ष भी है। वे कांग्रेस में गांधी परिवार की केंद्रीय भूमिका को भारतीय लोकतंत्र की समस्या मानते हैं। यह एक वैध तर्क है। किंतु निष्पक्ष विश्लेषण की मांग यह है कि वही कसौटी अन्य दलों और अन्य राजनीतिक परिवारों पर भी समान कठोरता से लागू की जाए। यदि किसी दल में वंशानुगत नेताओं की उपस्थिति राजनीतिक क्षमता का प्रमाण मानी जाती है, तो दूसरे दल में वही तथ्य लोकतांत्रिक दोष का पर्याय कैसे बन जाता है? राहुल गांधी का मूल्यांकन करते समय यह स्वीकार करना आवश्यक है कि उनकी राजनीति से असहमति संभव है। उनकी रणनीतियों की आलोचना भी की जा सकती है। किंतु उन्हें केवल एक राजनीतिक उपनाम तक सीमित कर देना उनके सार्वजनिक जीवन के वास्तविक प्रयासों की उपेक्षा होगी। लोकतंत्र में किसी नेता का अंतिम मूल्यांकन इतिहास करता है, और इतिहास केवल वंश नहीं देखता; वह यह भी देखता है कि कठिन समय में किसने संघर्ष किया, जनता से संवाद किया और अपने विचारों के लिए कितना जोखिम उठाया। राहुल गांधी के समर्थक इसी आधार पर कहते हैं कि उनके बारे में प्रचलित धारणाओं और उनके वास्तविक राजनीतिक प्रयासों के बीच की दूरी को अब नए सिरे से परखा जाना चाहिए। इसलिए प्रश्न केवल यह नहीं है कि राहुल गांधी कौन हैं; प्रश्न यह भी है कि क्या भारतीय सार्वजनिक विमर्श उन्हें उसी कसौटी पर परखता है जिस पर वह अन्य नेताओं को परखता है।

करोल बाग से क्या रिश्ता कस्टमर्स, आर.के.धवन और मारीशस का

विवेक शक्ला

जब आप करोल बाग मेट्रो स्टेशन से उतरकर बाजार की मुख्य सड़क पर कदम रखते हैं, तो पहली नज़र में लगता है कि समय यहाँ अभी भी 1990 के दशक में अटका हुआ है। चारों तरफ़ चहल-पहल, हॉकर्स की तीखी आवाज़ें, ग्राहकों की भीड़, रंग-बिरंगे कपड़ों की दुकानें और हवा में तला-भुना खाने की महक। लेकिन जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते हैं, सूक्ष्म बदलाव आँखों को छूने लगते हैं। पुरानी दिल्ली की इस मशहूर शॉपिंग डेस्टिनेशन का चेहरा धीरे-धीरे बदल रहा है। आज करोल बाग में कई पुरानी दुकानों की जगह बड़े ब्रांड आ चुके हैं। लेकिन यह जगह सिर्फ शॉपिंग डेस्टिनेशन नहीं है। यह विभाजन के दर्द, हिम्मत, समावेशिता और नई शुरुआत की जीती-जागती मिसाल है। राजेश वाच्छर जैसे पुराने निवासियों ने बुजुर्गों से सुना है कि आर.के. धवन (जो बाद में इंदिरा गांधी के करीबी बने) यहाँ कंघियां बेचा करते थे। आर्य समाज रोड पर मॉरीशस के राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ भी अपने समधी के यहाँ आया करते थे। यहां पर उनकी बेटी की ससुराल थी। उनकी बेटी ने करोल बाग के मल्होत्रा परिवार के डॉ कृष्ण मल्होत्रा से विवाह किया था। सबसे पहला और सबसे नज़र आने वाला बदलाव भाषा का है। साल 2000 के शुरू तक करोल बाग की दुकानों के बोर्डों पर उर्दू का खूबसूरत नक्श-ओ-निगार आम था। दुकानदार उर्दू में लिखे बोर्ड लगाते थे और ग्राहकों से उर्दू-हिंदी के मिश्रण में बात करते थे। अब उर्दू लगभग पूरी तरह गायब हो चुकी है। पंजाबी भी बहुत कम सुनाई देती है। एक समय था जब करोल बाग पंजाबी संस्कृति का गढ़ माना जाता था। 1947 के बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थी परिवारों ने यहाँ बसना शुरू किया। उनकी मातृभाषा पंजाबी थी। दुकानों में पंजाबी बोलने वाले दुकानदार, गलियों में पंजाबी गानों की धुन और घरों से आने वाली पंजाबी व्यंजनों की खुशबू- इस इलाके की पहचान थी। आज हिंदी और कुछ हद तक अंग्रेजी ने उस जगह को ले लिया है। यह बदलाव चुपके-चुपके हुआ है, लेकिन इसका गहरा अर्थ है। करोल बाग धीरे-धीरे अपनी मूल पहचान से दूर होता जा रहा है।

यादगार लम्हों का बाजार- फिर भी करोल बाग की अपनी एक अनोखी चमक बरकरार है। अजमल खान रोड की चकाचौंध, गफ्फार मार्केट की धड़कन, संकरी गलियों में जूते, कपड़े, बैग, मेकअप और इलेक्ट्रॉनिक्स सामान बेचने वालों की गर्मजोशी- ये सब मिलकर इस बाजार को खास बनाते हैं। दिल्ली की शायद ही कोई पीढ़ी ऐसी होगी जिसने यहाँ शॉपिंग न की हो। किशोरावस्था में पहली जींस यहीं से खरीदी गई, शादी के लिए पहला सूट यहीं सिला गया, या फिर दोस्तों के साथ घूमते हुए सस्ते लेकिन स्टाइलिश सामान खरीदने का मजा यहीं मिला। करोल बाग सिर्फ़ बाजार नहीं, बल्कि दिल्लीवासियों की यादों का संग्रहालय है। यहां की दुकानें पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही हैं। कई दुकानदार आज भी पुराने ग्राहकों को नाम लेकर पुकारते हैं और पुरानी छूट देते हैं।

पार्किंग की समस्या- लेकिन इस रौनक के बीच एक बड़ी समस्या करोल बाग को खाए जा रही है- पार्किंग। सप्ताहांत या फेस्टिवल सीजन में यहाँ गाड़ी पार्क करना लगभग असंभव हो जाता है। लोग अब ऑनलाइन शॉपिंग या अन्य मॉल्स की ओर रुख कर रहे हैं। नतीजा यह है कि कई पुरानी दुकानों का व्यापार घट रहा है।

शास्त्री पार्क में प्रस्तावित मल्टी-लेवल पार्किंग प्रोजेक्ट दशकों से अटका पड़ा है। अगर 500 से अधिक गाड़ियों की क्षमता वाला यह पार्किंग कॉम्प्लेक्स बन जाता, तो करोल बाग की तस्वीर बदल सकती थी। ट्रैफिक जाम, सड़क पर खड़ी गाड़ियाँ और दुकानदारों की परेशानी अब रोज़ की बात हो गई है।

इतिहास की गहराई- करोल बाग का इतिहास बहुत गहरा और दर्द भरा है। बंटवारे से पहले यह इलाका झाड़ियों और जंगली घास से भरा हुआ था। यहाँ मुस्लिम आबादी अधिक थी। पाकिस्तानी क्रिकेटर सिकंदर बख्त की फैमिली भी यहीं रहती थी। 1947 के बाद सब बदल गया। पाकिस्तान से आए शरणार्थियों ने यहाँ नई ज़िंदगी शुरू की। मुसलमान परिवार चले गए और उनके मकानों में नए लोग बस गए। इन्हीं शरणार्थियों में एक नाम था- महाशय धर्मपाल गुलाटी, जो बाद में MDH मसालों के संस्थापक बने। उनकी कहानी करोल बाग की हिम्मत और उद्यमिता का प्रतीक है। छोटी-सी दुकान से शुरू करके उन्होंने साम्राज्य खड़ा कर दिया।

समावेशी संस्कृति का केंद्र- करोल बाग कभी साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र भी था। यहाँ कई साउथ इंडियन रेस्टोरेंट थे, जहां पंजाबी लेखक दक्षिण भारतीय कॉफी के साथ बैठकर घंटों बहस करते थे। अमृता प्रीतम, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता डॉ. हरभजन सिंह, करतार सिंह दुग्गल, हरनाम सिंह और महेंद्र कौर गिल जैसे दिग्गज अक्सर यहाँ मिलते थे। हरनाम सिंह के साथ गुलज़ार भी करोल बाग में रहे। कहा जाता है कि हरनाम सिंह के सान्निध्य में ही गुलज़ार को कविता लिखने का शौक बढ़ा। खालसा कॉलेज के प्रोफेसर डॉ. हरमीत सिंह आज भी उन दिनों को याद करते हुए बताते हैं कि कैसे प्रो. जनार्दन द्विवेदी के साथ वे भी इन साहित्यिक बैठकों का हिस्सा होते थे। अब वक्त आ गया है कि करोल बाग को नई जान फूँकी जाए। बेहतर और पर्याप्त पार्किंग, पुरानी दुकानों और बोर्डों की विरासत का संरक्षण, साफ-सुथरी गलियाँ, हेरिटेज वॉक का आयोजन और आधुनिक सुविधाएँ — ये सब मिलकर इस बाजार को उसकी खोई रौनक वापस दिला सकते हैं। करोल बाग सिर्फ एक बाजार नहीं, दिल्ली की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। इसे बचाना और संवारना हमारी जिम्मेदारी है। बेशक, यह जगह अपनी पूरी रौनक वापस पाने के काबिल है।

पर्यावरणीय संकट से समाधान की ओर बढ़ने का समय

लेखक -ललित गर्ग

5 जून को मनाया जाने वाला विश्व पर्यावरण दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि पृथ्वी और मानवता के भविष्य को बचाने का वैश्विक संकल्प है। वर्ष 2026 का विश्व पर्यावरण दिवस ऐसे समय में आया है जब जलवायु परिवर्तन, प्लास्टिक प्रदूषण, जैव विविधता का क्षरण, जल संकट, वायु प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन ने पृथ्वी के अस्तित्व को गंभीर चुनौती के सामने खड़ा कर दिया है। इस वर्ष की थीम "प्लास्टिक प्रदूषण का अंत" (ठमंज च्सेंजपब च्वससनजपवद) केवल प्लास्टिक के उपयोग को कम करने का आह्वान नहीं है, बल्कि उपभोगवादी जीवनशैली और प्रकृति-विरोधी विकास मॉडल पर पुनर्विचार का भी संदेश है। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को झेल रही है। कहीं भीषण गर्मी जीवन को असहनीय बना रही है, कहीं अनियंत्रित वर्षा और बाढ़ तबाही ला रही है, तो कहीं सूखा और जल संकट मानव अस्तित्व पर प्रश्नचिह्न खड़े कर रहे हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। उत्तराखंड के जंगलों में आग, हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना, महानगरों में प्रदूषण, बेंगलुरु जैसे तकनीकी नगरों में जल संकट और लगातार बढ़ती गर्मी इस बात के संकेत हैं कि पर्यावरणीय संकट अब भविष्य की नहीं, वर्तमान की वास्तविकता बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टें चेतावनी दे रही हैं कि पिछले एक दशक में जलवायु संबंधी आपदाओं से लाखों लोगों की मृत्यु हुई है और खरबों डॉलर की आर्थिक क्षति हुई है। जैव विविधता का ह्रास, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण-ये तीनों संकट परस्पर जुड़े हुए हैं। यदि वैश्विक तापमान वृद्धि को नियंत्रित नहीं किया गया तो मानव सभ्यता के सामने अभूतपूर्व संकट खड़ा हो सकता है। 2015 के पेरिस जलवायु समझौते में वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन आज भी दुनिया उस दिशा में अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ रही है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि विश्व के सामने उपस्थित इस सबसे बड़े संकट को भारत की राजनीति में वह महत्व नहीं मिला, जिसका वह अधिकारी है। चुनावी घोषणापत्रों में पर्यावरण का उल्लेख तो होता है, लेकिन वह केवल औपचारिकता भर रह जाता है। राजनीतिक दल यह मानकर चलते हैं कि पर्यावरण, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन वोट दिलाने वाले मुद्दे नहीं हैं। परिणामस्वरूप पर्यावरणीय प्रश्न न तो चुनावी बहस का हिस्सा बनते हैं और न ही राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का। जबकि सच्चाई यह है कि आने वाली पीढ़ियों का जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा इसी प्रश्न पर निर्भर करती है। पर्यावरणीय संकट का मूल कारण विकास की वह अवधारणा है जिसमें प्रकृति को केवल संसाधन और उपभोग की वस्तु मान लिया गया है। हमने जंगलों को उद्योगों के लिए, नदियों को अपशिष्ट के लिए और भूमि को कंक्रीट के जंगलों में बदलने के लिए प्रयोग किया। प्रकृति हमें जीवन का आधार निःशुल्क देती है, लेकिन हमने उसके प्रति कृतज्ञता के बजाय दोहन का व्यवहार अपनाया। परिणामस्वरूप वनस्पतियों का विनाश, वन्य जीवों का संकट, भूमिगत जल का क्षय और प्रदूषण का विस्तार निरंतर बढ़ रहा है। भारतीय संस्कृति ने सदैव प्रकृति को पूजनीय माना है। वृक्षों, नदियों, पर्वतों और वनस्पतियों को केवल भौतिक संसाधन नहीं, बल्कि जीवनदाता के रूप में देखा गया। आयुर्वेद और वनौषधि विज्ञान इसका श्रेष्ठ उदाहरण हैं। जड़ी-बूटियों और वनस्पतियों ने हजारों वर्षों तक मानव स्वास्थ्य की रक्षा की, लेकिन आधुनिकता की अंधी दौड़ में यह ज्ञान और प्राकृतिक संपदा दोनों उपेक्षित होते गए। आज जब नई-नई बीमारियां मानव जीवन को चुनौती दे रही हैं, तब पुनः प्रकृति और वनस्पति जगत की ओर लौटने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। वर्तमान संकट केवल पर्यावरणीय नहीं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और नैतिक संकट भी है। वायु प्रदूषण लाखों लोगों की असामयिक मृत्यु का कारण बन रहा है। जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं। कृषि व्यवस्था प्रभावित हो रही है। मौसम चक्र असंतुलित हो गया है। गरीब और कमजोर वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। कभी इंदिरा गांधी ने कहा था कि 'गरीबी सबसे बड़ा प्रदूषक है।' आज यह कथन और अधिक प्रासंगिक हो गया है क्योंकि गरीबी और पर्यावरणीय विनाश एक-दूसरे को बढ़ाने वाले कारक बन गए हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए कानूनों की कमी नहीं है। 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम से लेकर अनेक पर्यावरणीय कानून बनाए गए। लेकिन कानूनों और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के बीच गहरी खाई बनी हुई है। अवैध खनन, वनों की कटाई, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की अनदेखी और पर्यावरणीय मंजूरियों में शिथिलता इस बात का प्रमाण हैं कि संस्थागत इच्छाशक्ति अभी भी पर्याप्त नहीं है। फिर भी आशा की किरण दिखाई देती है। युवाओं में पर्यावरण के प्रति जागरूकता तेजी से बढ़ रही है। विभिन्न सर्वेक्षणों में बड़ी संख्या में युवाओं ने जलवायु संकट को गंभीर विषय माना है और सरकार से इस संबंध में शिक्षा एवं जनजागरण की अपेक्षा की है। यह संकेत है कि नई पीढ़ी पर्यावरण को केवल प्रकृति का नहीं, बल्कि अपने भविष्य का प्रश्न मान रही है। आवश्यकता इस चेतना को सामाजिक और राजनीतिक शक्ति में बदलने की है। समाधान क्या है? सबसे पहले विकास और पर्यावरण को विरोधी नहीं, पूरक मानने की दृष्टि विकसित करनी होगी। ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों को बढ़ावा देना, जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करना, सार्वजनिक परिवहन को मजबूत बनाना, जल संरक्षण को राष्ट्रीय अभियान बनाना, वृक्षारोपण को जनांदोलन का रूप देना और प्लास्टिक के उपयोग पर प्रभावी नियंत्रण आवश्यक है। केवल सरकारी योजनाओं से यह कार्य संभव नहीं होगा, इसके लिए समाज, उद्योग, शिक्षा संस्थानों और नागरिकों की साझी भागीदारी चाहिए। दूसरा, पर्यावरण को राजनीतिक एजेंडा बनाना होगा। जिस प्रकार रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य चुनावी मुद्दे बनते हैं, उसी प्रकार स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल, हरित विकास और जलवायु सुरक्षा भी राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनें। मतदाता अपने प्रतिनिधियों से पर्यावरण संबंधी दृष्टि और प्रतिबद्धता के बारे में प्रश्न पूछें। जब जनता पर्यावरण को प्राथमिकता देगी, तब राजनीति भी उसकी ओर मुड़ेगी। तीसरा, शिक्षा व्यवस्था में पर्यावरणीय चेतना को व्यवहारिक रूप से शामिल करना होगा। बच्चों और युवाओं को केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ जुड़ाव, जल संरक्षण, कचरा प्रबंधन और जैव विविधता संरक्षण के व्यावहारिक संस्कार दिए जाने चाहिए।

फ्रेंच ओपनः अन्ना कालिंस्काया को हराकर

पहली बार माजा च्वालिन्स्का ने सेमीफाइनल में जगह बनाई

पेरिस। पोलैंड की टेनिस स्टार माजा च्वालिन्स्का ने फ्रेंच ओपन में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। कोर्ट फिलिप-चैटियर में नंबर 22 सीड एअन्ना कालिंस्काया को 7-6(3), 6-3 से हराकर अपने पहले ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल में जगह बनाई। 24 साल की माजा पहली बार फाइनल में जगह बनाने के लिए वर्ल्ड नंबर 1 एरिना सबालेंका और नंबर 25 सीड डायना श्नाइडर के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल की विनर से होगा। कड़ी रैलियों और अहम मोमेंटम स्विंग वाले मुकाबले में, च्वालिंस्का ने अहम मौकों पर शानदार संयम दिखाया और अन्ना कालिंस्काया को हराकर आखिरी चार में अपनी जगह पक्की की।

पोलिश खिलाड़ी ने रिटर्न पर अपने मौकों का पूरा फायदा उठाया, आठ में से सात ब्रेक-पॉइंट चांस को शानदार तरीके से बदला, जबकि अन्ना कालिंस्काया ने 11 मौकों में से सिर्फ पांच को बदला। अन्ना कालिंस्काया ने मैच के सिर्फ दो एस मारे, लेकिन छह डबल फॉल्ट की वजह से उन्हें मुश्किल हुई, जिससे च्वालिंस्का पूरे मैच के दौरान स्ट्राइकिंग डिस्टेंस के अंदर रहीं।

पहला गेम हारकर मैच की शुरुआत करने वाली च्वालिंस्का ने लगातार ब्रेक हासिल करके 5-1 की बढ़त बना ली। हालांकि, कालिंस्काया ने लगातार चार गेम जीतकर वापसी की। सेट आखिरकार टाई-ब्रेक तक गया, जो काफी आसान था।

पहले सेट में काफी कड़ा मुकाबला होने के बाद, च्वालिंस्का अगले सेट में पूरी तरह हावी रहीं और वापसी का थोड़ा मौका गंवा दिया, क्योंकि उन्होंने लगातार दूसरा सेट 6-3 से जीतकर अगले राउंड में जगह बना ली।

श्नाइडर ने सबालेंका को चौंकाया, पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचीं

रूस की 22 वर्षीय डायना श्नाइडर ने फ्रेंच ओपन के विमेंस सिंगल्स क्वार्टरफाइनल में 'वर्ल्ड नंबर 1' अर्यना सबालेंका को चौंका दिया। श्नाइडर ने एक सेट और दो ब्रेक से पिछड़ने के बावजूद आखिरी 10 गेम जीते और 2 घंटे 12 मिनट तक चले इस मैच में 3-6, 7-5, 6-0 से जीत दर्ज करते हुए पेरिस के स्टेड रोलैंड गैरोस में अपने पहले ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल में जगह बना ली। 25वीं सीड श्नाइडर ने जबरदस्त वापसी करते हुए सबालेंका को इस जीत के साथ ही उन्होंने नंबर 1 सीड सबालेंका के लगातार 6 बड़े सेमीफाइनल में पहुंचने के सिलसिले को भी तोड़ दिया। 22 वर्षीय श्नाइडर एक समय पूरी तरह से हारी हुई लग रही थीं, क्योंकि सबालेंका ने एक बड़ी बढ़त बनाकर अपनी जीत लगभग पक्की कर ली थी। लेकिन इस रूसी युवा खिलाड़ी ने यह साबित कर दिया कि जब तक मैच खत्म नहीं हो जाता, तब तक हार नहीं माननी चाहिए। उन्होंने एक शानदार वापसी की। दूसरे सेट में जब स्कोर 5-4 था और सबालेंका मैच जीतने के लिए सर्व कर रही थीं, तब वह जीत से सिर्फ दो प्वाइंट्स दूर थीं। ठीक उसी समय, बाएं हाथ से खेलने वाली श्नाइडर ने मैच का रुख पलटना शुरू कर दिया।

अपने पहले ग्रैंड स्लैम क्वार्टरफाइनल में खेल रहीं श्नाइडर पहली बार वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी का सामना कर रही थीं। जब कोर्ट फिलिप-चैट्रियर में तेज हवाएं चल रही थीं, तब भी उन्होंने हालात पर पूरी तरह से काबू पाया और इस बड़े मौके का शानदार फायदा उठाते हुए अपने पहले ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल में जगह बनाई।

6-3, 4-1 से पिछड़ने के बावजूद श्नाइडर ने अपने बाएं हाथ के फोरहैंड से लगातार विनर्स लगाते हुए अगले 13 में से 12 गेम जीत लिए। इसमें 5-3 के स्कोर के बाद लगातार जीते गए आखिरी 10 गेम भी शामिल हैं। इसके उलट, सबालेंका का अपने खेल पर से कंट्रोल हट गया और उन्होंने 57 अनफोर्स्ड एरर कर दिए, जिनमें से 17 तो सिर्फ निर्णायक सेट में हुए। ऐसा पहली बार था, जब उन्होंने 2024 दुबई के दूसरे राउंड में डोना वेकिच के खिलाफ तीसरे सेट के बाद से कोई सेट 6-0 से हारा था।

फुटबॉल वर्ल्ड कप हो जाएगा और रोमांचक

- फीफा ने लिया बड़ा फैसला, हर हाफ के बीच में पानी पीने के लिए दिया जाएगा ब्रेक

नई दिल्ली। फुटबॉल का खेल 90 मिनट का होता है और इसमें 45-45 मिनट को दो पीरियड होते हैं जिनके बीच 15 मिनट का ब्रेक होता है, लेकिन 2026 के फीफा वर्ल्ड कप में ये नियम बदल जाएगा। यही नहीं पहली बार मैच में हर हाफ के बीच में पानी पीने के लिए ब्रेक दिया जाएगा। ये ब्रेक पहले हाफ के 22वें मिनट में और दूसरे हाफ के 67वें मिनट में होंगे और मौसम कैसा भी हो ये ब्रेक जरूरी होंगे।

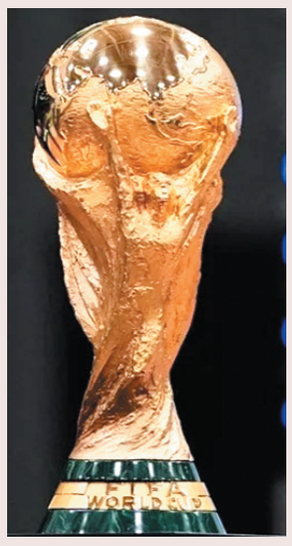

इस बार फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में किया जाएगा और यहां पर गर्मी होगी। गर्मी में होने वाले इस टूर्नामेंट को देखते हुए फीफा के लिए गर्मी से बचाव और खिलाड़ियों की सेहत का ध्यान रखना सबसे बड़ी चिंता बन गई है। ऐसे में फीफा ने एक जैसा नियम अपनाने का फैसला किया है जिसे हर मैच में लागू किया जाएगा। इन ब्रेक की वजह से इस गर्मी में फुटबॉल काफी हद तक हॉकी, बास्केटबॉलर और अमेरिकन फुटबॉल जैसा लगेगा।

खेल को व्यवस्थित करने के लिए उठाया कदम

फीफा द्वारा किए गए इस बदलाव के बाद से फुटबॉल असल में चार-क्वार्टर वाला खेल बन गया है। 45 मिनट तक बिना रुके खेलने के बजाय अब टीमों को हर हाफ के बीच में थोड़ा ब्रेक मिलेगा। हॉकी खिलाड़ी इस कॉन्सेप्ट से पहले से ही परिचित हैं। कोच क्वार्टर ब्रेक का इस्तेमाल प्रेसिंग पैटर्न बदलने, डिफेंसिव स्ट्रक्चर को फिर से व्यवस्थित करने और खेल की गति में आने वाले उतार-चढ़ाव को रोकने के लिए करते हैं।

राहुल-हेड ओपनर

गिल समेत 4 भारतीय शामिल

संजय बांगड़ ने चुनी टेस्ट के लिए वर्ल्ड प्लेइंग 11

नई दिल्ली। आईपीएल का रोमांच अब खत्म हो चुका है। 6 जून से भारतीय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच खेलने उतरेगी। अब दुनिया में टेस्ट क्रिकेट का रोमांच शुरू होने वाला है। उससे पहले भारत के पूर्व खिलाड़ी संजय बांगड़ ने टेस्ट के लिए वर्ल्ड 11 का चुनाव किया है। उन्होंने अपनी टीम में भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल समेत चार भारत के खिलाड़ियों को चुना है।

भारत-ऑस्ट्रेलिया के सबसे ज्यादा खिलाड़ी- भारत और ऑस्ट्रेलिया के सबसे ज्यादा 4-4 खिलाड़ियों को संजय बांगड़ ने अपनी वर्ल्ड टेस्ट 11 में जगह दी है। केएल राहुल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह के रूप में चार भारतीय इस टीम का हिस्सा बने हैं। जबकि कंगारू टीम के चार खिलाड़ी, ट्रेविस हेड, स्टीव स्मिथ, पैट कमिंस (कप्तान) और मिचेल स्टार्क इस टीम में शामिल हैं। इंग्लैंड के दो खिलाड़ी बेन स्टोक्स और जो रूट भी इस टीम का हिस्सा हैं।

टेस्ट के लिए बांगड़ की वर्ल्ड प्लेइंग 11

केएल राहुल, ट्रेविस हेड, जो रूट, शुभमन गिल, स्टीव स्मिथ, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), बेन स्टोक्स, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस (कप्तान), जसप्रीत बुमराह, केशव महाराज।

वैभव होंगे एक्शन में, तिलक की कप्तानी में जीतने उतरेगी इंडिया 'ए'

नई दिल्ली (एजेंसी)। आईपीएल 2026 में अपनी बल्लेबाजी से तूफान मचाने वाले वैभव सूर्यवंशी अब 9 जून से फिर से एक्शन में नजर आने वाले हैं। वैभव का जादू भारतीय क्रिकेट फैंस के सिर पर इस कदर चढ़कर बोल रहा है वो उनके किसी भी मैच को मिस नहीं करना चाहते। वैभव देश में खेलें या फिर विदेश में हर कोई उनकी बल्लेबाजी को किसी भी कीमत पर देखना चाहता है। वैभव के इस क्रेज को देखते हुए अब इंडिया ए के श्रीलंका दौरे पर होने वाले मैच का लाइव प्रसारण किया जाएगा।

सोनी स्पोर्ट्स पर किया जाएगा ट्राई सीरीज के मैचों का प्रसारण- वैभव सूर्यवंशी का क्रेज अब इंटरनेशनल लेवल पर भी फैल रहा है और ऐसा लग रहा है कि इसकी वजह से ब्रॉडकास्टर अपनी स्ट्रैटेजी पर दोबारा सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। इंडिया ए टीम में उनके शामिल होने से लोगों में काफी दिलचस्पी जागी है और इसी को देखते हुए अधिकारियों ने फैसला किया है कि श्रीलंका में होने वाली अगली ट्राई-सीरीज का टीवी पर सीधा प्रसारण किया जाएगा।

व्यापार

हीरो मोटोकॉर्प के शेयर 3 प्रतिशत उछले, कंपनी ने लॉन्च की भारत की पहली 100 सीसी फ्लेक्स-फ्यूल बाइक

नई दिल्ली, एजेंसी। देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प के शेयर गुरुवार को करीब 3त्न तक चढ़ गए। कंपनी के शेयर बीएसई पर 4,980 रुपये के स्तर तक पहुंच गए। भारत की पहली 100 सीसी फ्लेक्स-फ्यूल बाइक की लॉन्चिंग के बाद निवेशक इस ऑटो स्टॉक पर टूट पड़े।

हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी लोकप्रिय कम्यूटर बाइक स्प्लेंडर प्लस प्लेक्स फ्यूल और एचएफ डीलक्स फ्लेक्स ईंधन को लॉन्च किया है। ये दोनों मोटरसाइकिलें पेट्रोल के साथ 85त्न तक एथेनॉल मिश्रण पर चल सकती हैं। यह भारत में फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक वाली पहली 100 सीसी श्रेणी की मोटरसाइकिलें हैं। फ्लेक्स-फ्यूल वाहन ऐसे इंजन से लैस होते हैं जो पेट्रोल और एथेनॉल के विभिन्न मिश्रणों पर चल सकते हैं। एथेनॉल एक बायो फ्यूल है, जो गन्ने और अन्य कृषि उत्पादों से तैयार किया जाता है। इसका इस्तेमाल पेट्रोल पर निर्भरता कम करने और प्रदूषण घटाने के लिए किया जाता है। इन मोटरसाइकिलों की लॉन्चिंग केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की मौजूदगी में किया गया। सरकार लंबे समय से एथेनॉल बेस्ड फ्यूल को बढ़ावा देने की नीति पर काम कर रही है। हीरो मोटोकॉर्प का यह कदम उसी दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक भारत में भविष्य की मोबिलिटी का अहम हिस्सा बन सकती है।

नए बिजनेस में एंट्री लेगी सुजलॉन एनर्जी, शेयर पर टूट पड़े निवेशक

नई दिल्ली, एजेंसी। अगर पोर्टफोलियो में सुजलॉन एनर्जी के शेयर हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, सुजलॉन एनर्जी ने कारोबार विस्तार का ऐलान किया है। सुजलॉन 2.0 के तहत कंपनी अब केवल विंड टरबाइन निर्माता नहीं रहेगी बल्कि सोलर, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और अन्य रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्युशंस में भी विस्तार करेगी। कंपनी की इस घोषणा के बाद गुरुवार को सुजलॉन के शेयरों में 3 फीसदी की तेजी देखी गई। हालांकि, ब्रोकरेज का अनुमान है कि यह शेयर अभी और मुनाफा देगा। आइए डिटेल जान लेते हैं। बीएसई पर 54.38 रुपये की पिछली क्लोजिंग के बाद गुरुवार को शेयर 55.75 रुपये तक गया। यह करीब 3 पर्सेंट का उछाल है। ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल के अनुसार सुजलॉन के शेयर ?65 तक जा सकते हैं। यह करीब 20 फीसदी के उछाल का अनुमान है। जून 2025 में यह शेयर 69.48 रुपये तक गया था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। मार्च 2026 में शेयर 38.17 रुपये के निचले स्तर पर आ गया। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है। पिछले एक वर्ष में शेयर में 17 फीसदी की गिरावट रही है, लेकिन तीन वर्षों में इसने 405 फीसदी और पांच वर्षों में 725 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है। सुजलॉन ने एक बयान में कहा कि कंपनी अब बैटरी स्टोरेज सहित कई नए व्यवसायों में प्रवेश करेगी। इसके साथ ही यह एक प्लेटफॉर्म भी शुरू करेगी, जिसके जरिये रिन्यूएबल एनर्जी की संभावनाओं को बड़े पैमाने पर परियोजनाओं में बदला जाएगा। इस प्लेटफॉर्म को कंपनी ने आरइ देवको नाम दिया है। कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि केवल इस देवको इकाई में वित्त वर्ष 2026-27 में 500 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इसके अलावा अन्य व्यवसाय क्षेत्रों में भी 600 से 700 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। सुजलॉन ने अपने अगले पांच वर्षों के लक्ष्य भी साझा किए। इसके तहत कंपनी का लक्ष्य है कि उसकी वार्षिक रिन्यूएबल एनर्जी बिक्री चार गुना बढ़कर 10 गीगावाट तक पहुंच जाए और वर्ष 2031 तक कंपनी की ऑर्डर बुक 15 गीगावाट तक बढ़े।कंपनी का लक्ष्य सुजलॉन का लक्ष्य एफवाय31 तक 15 जीडब्लू का ऑर्डर बुक तैयार करना, भारतीय विंड एनर्जी बाजार में लगभग 40 फीसदी हिस्सेदारी हासिल करना है।

चढ़ता ही जा रहा है क्रूड, दिल्ली में पेट्रोल 102 तो डीजल 95 के पार

नई दिल्ली, एजेंसी। क्रूड ऑयल के अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक बार फिर से कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। हालांकि, इंडियन बॉस्केट क्रूड के दाम में दो दिनों से कोई परिवर्तन नहीं दिखा है। शायद इसका ही असर है कि भारत में पेट्रोल-डीजल बेचने वाली सरकारी तेल कंपनियां ने आज यानी गुरुवार, 4 जून 2026 को दाम में कोई बदलाव नहीं किया। बीते 12 दिनों से इसके दाम स्थिर हैं।

11 दिनों में 4 बार बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम: पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव बीतने के बाद ही पेट्रोलियम कंपनियों ने 11 दिनों में चार बार दाम बढ़ा चुकी है। सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों ने सबसे पहले 15 मई 2026 को पेट्रोल 3 रुपये और डीजल 3.29 पैसे महंगा किया था। इसके बाद 19 मई को पेट्रोल 87 पैसे तो डीजल 91 पैसे, 23 मई 2026 को पेट्रोल 87 पैसे तो डीजल 91 पैसे और 25 मई 2026 को

पेट्रोल 2.61 रुपये और डीजल 2.71 रुपये महंगा किया था। तेल कंपनियों की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली में आज पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। कोलकाता में इसकी कीमत 113.51 रुपये, मुंबई में 111.21 रुपये और चेन्नई में 107.77 रुपये है। एक अनुमान के मुताबिक क्रूड ऑयल महंगा होने से सरकारी तेल कंपनियों को रोजाना पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और जेट फ्यूल पर करीब 750 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है। कच्चा तेल का ग्लोबल बाजार बुधवार को गरम ही रहा था। इसके बाद गुरुवार की सुबह इस बाजार में जो शुरुआती रूझान दिखे, उसमें मानक ब्रेंट क्रूड के दाम में 1.89 फीसदी की बढ़ोतरी दिख रही है। सुबह के कारोबार में यह 97.81 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिख रहा है। डब्ल्यूटीआई क्रूड के दाम में

डीजल की कीमत क्या है

सरकारी ऑयल कंपनियों के मुताबिक बुधवार को दिल्ली में डीजल का प्रति लीटर दाम 95.20 रुपये है। कोलकाता में यह 99.02 रुपये, मुंबई में 97.83 रुपये और चेन्नई में 99.55 रुपये प्रति लीटर है। कच्चे तेल की कीमत में हाल में काफी बढ़ोतरी हुई है। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद यह करीब 50 फीसदी महंगा हो गया है।

भी 0.69 फीसदी की तेजी दिख रही है। इस समय यह 95.36 प्रति बैरल पर ट्रेड होता दिख रहा है। हां, इंडियन बॉस्केट क्रूड के भाव में पिछले दो दिनों से कोई बदलाव नहीं दिखा है और यह अभी भी 96.12 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड होता दिख रहा है। पेट्रोल-डीजल के भाव जब भी बदलते हैं, तब सुबह 6 बजे अपडेट हो जाते हैं। पेट्रोल-डीजल का रोज का रेट आप स्स्रू के जरिए भी जान सकते हैं।

99 प्रतिशत बढ़ाकर दिखाया रेवेन्यू! राजेश एक्सपोर्ट्स के शेयर हुए धड़ाम, सेबी ने लगाया मालिक पर बैन

नई दिल्ली, एजेंसी। सोने की रिफाइनिंग और जूलरी मेकिंग कंपनी राजेश एक्सपोर्ट्स का शेयर आज बाजार खुलते ही लोअर सर्किट पर पहुंच गया। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कंपनी और उसके प्रमोटर राजेश मेहता के खिलाफ एक अंतरिम आदेश जारी किया है। कंपनी पर बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं, जांच के दौरान सहयोग न करने और कंपनी के रेवेन्यू को 97 से 99 प्रतिशत तक बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने का आरोप है। सेबी ने अगले आदेश तक राजेश मेहता को कंपनी के शेयर खरीदने, बेचने या किसी भी तरह का लेन-देन करने से रोक दिया है।

राजेश एक्सपोर्ट्स का शेयर बीएसई पर पिछले सत्र में 110.15 रुपये पर बंद हुआ था और आज यह 5 फीसदी गिरावट के साथ 104.65 रुपये पर खुला। इसका 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर 239 रुपये और न्यूनतम स्तर 80.11 रुपये है। सेबी ने 3 जून को जारी अंतरिम आदेश में कहा कि उसकी जांच और फोरेंसिक जांच में वित्तीय अनियमितताओं के कई प्रमाण मिले हैं। कंपनी ने अपना रेवेन्यू 97-99 प्रतिशत बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया। रेगुलेटर ने इसे बेहद गंभीर और अभूतपूर्व मामला बताया है।

क्या है मामला

सेबी ने कंपनी को जांचकर्ताओं के साथ सहयोग करने और अपने वित्तीय विवरणों तथा संबंधित पक्षों के साथ किए गए लेन-देन की सही जानकारी देने को कहा है। मार्च 2024 में सेबी को एक शिकायत मिली थी। इसमें कंपनी के खातों में दिखाए गए बड़े पैमाने

पर ट्रेड रिसीवेबल्स पर चिंता जताई गई थी। सेबी ने अप्रैल 2020 से मार्च 2024 के बीच की अवधि को कवर करते हुए एक विस्तृत जांच शुरू की। साथ ही फोरेंसिक ऑडिटर नियुक्त किया।राजेश एक्सपोर्ट्स एनएसई तथा बीएसई दोनों पर लिस्टेड है। कंपनी घरेलू और विदेशी बाजारों में सोने के उत्पादों की मार्केटिंग करती है। साथ ही शुभ जूलर्स ब्रांड के तहत आभूषणों के आउटलेट चलाती है। स्विट्जरलैंड में राजेश एक्सपोर्ट्स की सहायक कंपनियों की वित्तीय रिपोर्टिंग की भी जांच की। राजेश मेहता को कंपनी की सिक्योरिटीज में लेन-देन करने से रोकने के अलावा ने राजेश एक्सपोर्ट्स 30 दिन के भीतर सारी जानकारी देने को का है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सैयद ज़की हैदर के लिए इरानीयन आर्ट प्रिंटर्स 1534 कासिमजान स्ट्रीट दरियागंज नई दिल्ली 11006 से मुद्रित कराकर, 2684 गली काले खां कूचा चलान दरियागंज नई दिल्ली 02 से प्रकाशित किया।
संपादक : सैयद ज़की हैदर- हैड ऑफिस :- एफ19/4 सेकेंड फ्लोर नफीश रोड जामिया नगर दिल्ली- 110025., सम्पर्क सूत्र :- 9911371802, 9810383593 RNI No.: DELHIN/2008/23928
जितेन्द्र कुमार बिस्वाल ब्यूरो चीफ उड़ीसा/ गोविंद कनोडिया/ पटना/ सैय्यद यूसुफ अली नक़वी-पॉलिटिकल एडिटर। ई-मेलः- (LOKTANTRAKISHAAN@GMAIL.COM

किसी भी प्रकार के विवाद हेतु निपटारे के लिए केवल दिल्ली न्यायालय ही मान्य होगी।
नोट- किसी भी समाचार/आलेख पर दावा प्रति दावा/आपत्ति समाचार प्रकाशन के 15 दिनों के अन्तराल तक ही मान्य होगा। समाचार पत्र में प्रकाशित आलेख से संपादक/प्रकाशक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

क्षेत्रीय कार्यालय अनवार मंजिल नया टोला गंज नंबर 01 बेतिया/ बिहार/ पिन नंबर 84 5438/>> संवाददाता, सना खान/(डॉ. अमानुल हक) स्थानीय संपादक/बिहार)